

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]

नई विल्ली, शनिवार, सितम्बर 7, 1985/माद 16, 1907

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1985/BHADRA 16, 1907

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या **दी जाती है जिससे कि यह अलग** संकलन के रूप में रखा जा सके

Agrate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड ३—दप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के सन्त्राक्षयों द्वारा जारी किये गये सार्विधिक आवेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

> विधि और न्याय मंत्रालय (विधि छार्य विभाग) नई दिल्ली 13 श्रगस्त, 1985

> > म् चन/एं

का ब्या ० 4089 — नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 ह के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी ० पी ० घीं श्र, पालि निटर एण्ड एडवोकेट, । 1 डाक्टर्ल, लेन, गोल माकिट, नई दिल्ली-110001 ने उक्त प्राधिकारों को उक्त नियम के नियम 4 के अधीं एक श्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उंदिल्लो में व्यश्नाय करने के लिए रोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त ध्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर िसी भी प्रकारका श्राक्षेप इस सूचना के प्रकाणन के चौरह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पाप भेजा जाए।

[मं०एफ० 5(19)/85 - न्या.]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE (Department of Legal Affairs) New Delhi, the 13th August, 1985 NOTICES

S.O. 4089.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the sold Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri B. P. Ghosh, S li itor and Advocate, 1, Doctor's Lane, Gole Market, New Delhi-110001, for appointment as a Notary to practise in Union Territory of Delhi.

2. Any obejection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(9)/85-Judl.]

नई दिल्ली, 16 श्रास्त, 1985

का श्या ० 4090. — नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 क के अनुप्रण में सक्षम प्राधि गरी द्वारा यह सूच गदी नाती है कि श्री अधि गथ गंगुली, अधि बक्ता 1 दो, गली पुराना डाकखाना-पहली मंगिल, कमरा नं० 7 (पाईन एन्ड पाईन) के लकरता-700001 ने उक्त प्राधि गरी को उक्त नियम के

(4659)

िराम 4 के प्रधीन एए प्रावेदन इस बात के लिए दिया है ए उसे एलएता में व्यव ाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त िया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर छिसी भी प्रतार की झाक्षेप इस सूचना के प्रणाणन के चौबह दिन के मीतर लिखित रूप में मेरे पात भेजा जाए।

> [सं० फ० 5/37/85-न्या ०] एस० गुप्तु, सक्षम प्राधिशारी

New Delhi, the 16th August, 1985

S.O. 4090.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, unnder rule 4 of the said Rules, by Shri Adinath, Ganguly Advocate, 1B, Old Post Office Street, 1st Floor, Room No. 7 (Pyne & Pyne), Calcutta-700001, for appointment as a Notary to practise in Calcutta.

2. Any objection to the appointment of the said nerson as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

S. GOOPTU, Competent Authority

गह मैत्रालय

(गृह विभाग) (पुनर्वाप प्रभाग)

नर्ड दिल्ली, 2 म्रागस्त, 1985

का ० आ ० 4091 - विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वाप)
प्रिधिनियम, 1954 (1954 का 44) की घारा 3 की उप
धारा (1) द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार एस० डी औ० (प्रिविल) (देहात), शिमला को
उनके अपने कार्यभार के प्रतिरिक्त, मुप्रावना पूल के भाग
की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त प्रधिनियम द्वारा
अपवा उसके प्रधीन बन्दोबस्त प्रधिकारी को सौंपे गए
कार्यों का निष्पादन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के उता,
शिमला, सोलन, किन्नार, सिरमार और बिलासपुर जिलों से
संबंधित बन्दोबस्त प्रधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

इससे दिनांः 3 जुलाई, 1971 की भ्रधिश्चना संख्या 3(2)/श्रम व पुनर्वात/67 ा अधिकमग िया जाता है।

[सं॰ 1(19) वि॰सं॰/84-एस॰ एस॰ Π (ए)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Home Affairs)
(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 2nd August, 1985

S.O. 4091.—In exercise of the powers conferred by Subsection (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints S.D.O. (Civi!) (Rural), Shimla as Settlement Officer in respect of Una, Shimla, Solan, Kinnaux. Sirmaur & Bilaspur Distts of Himachal Pradesh for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to the Settlement Officer by or

under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the compensation pool.

This supersedes Notification No. 3(2)/L&R/67 dated 3rd July, 1971.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(A)]

का श्या ०.- 4092 विस्थापित काकित (प्रतिकर तथा पुनर्याप प्रधित्यम, 1954 (1954 का 44) की घारा 3 की उपधारा (1) हारा प्रदत्त शिक्तराों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एम ० ही० औं ० (जिविल) कांगड़ा और नायब तहसीलदार (बिकी) कांगड़ा, हिमाचल प्रवेश को, उनके प्रपने कार्यभार के प्रतिरिक्त मुप्रायजा पूल के भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त प्रधितियम द्वारा प्रथवर उद्योग प्रधीन बन्दोबस्त प्रधिकारी और प्रवन्ध प्रधिकारी को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए कांगड़ा जिला (ऊना तहसील को छोड़कर) कुल्लू, लाहौल और स्पीती, चम्बा और मंडी जिले के संबंध में बन्दोबस्त प्रधिकारी और प्रवन्ध प्रधिकारी के कर्म में तियुक्त करती है।

इससे दिनां त 3 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या 3(2)/श्रम और पुनर्वान/67 ा अधिकामण िया जाता है। [मं० 1(19)/वि०सै०/84-एस एस० II(बी)]

S.O. 4092.—In exercise of the powers conefrred by Subsection (i) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints S.D.O. (Civil) Kangra & Naib Tehsildar (Sales) Kangra in Himachal Pradesh as Settlement Officer and Managing Officer in respect of Kangra District (Excluding Una Tehsil), Kulu, Lahaul and Spiti, Chamba and Mandi Districts for the purpose of performing, in addition to his own duties, the function assigned in the Settlement Officer & Managing Officer by or under the sald Act, in respect of the land and properties forming part of the compensation pool.

This supersedes Notification No. 3(2)/L&R/67 dated 3rd July, 1971.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.H(B)]

को व्या ० 4093ः विस्थापित ध्यक्ति (प्रति उर तथा पुनर्वास) प्रिवित्यम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों वा प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उप सचिव (राजस्व I), हिमाचल प्रदेश सरकार, सहायना तथा पुनर्वाम विभाग को, उप सचिव के रूप में उनके ग्रापने रार्यभार के प्रतिक्ति, हिमाचल प्रदेश राज्य में "मुग्नावजा पूल" के भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उका प्रधिनियम हारा श्रायवा उपके प्रधीत बन्दोबस्त प्राक्युत को सौंपे गए धार्यों का संबंध के किया प्रवास करने के नियं बन्दोबस्त प्राव्युत आयुक्त के रूप में नियुक्त उरती है।

इसमें दिनाँ 28 जुनाई, 1975 की अधितूबना संख्या - 5(2)/75-वि०सै० /एप एस० Π ा अधिकमग किया जाता है।

[सं. 1(19)/वि०सै०/84-एस०एस० II(सी)]

S.O. 4093.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Com, ensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Deputy Secretary (Revenue-1) to the Government of Himachal Pradesh, Relief and Rehabilitation Department as Settlement Commissioner for the putpose of performing, in addition to his own duties, as Deputy Secretary the function assigned to such Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the lands and properties forming part of the "Compensation pool" within the State of Himachal Pradesh.

The supersedes Notification No. 5(2)/75-Spl. Cell/SS.II dated 28th July, 1975.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(C)]

का श्या ० 4094 .— विस्थापित व्यक्ति (प्रितिक्र तथा पुनर्वास) प्रधिनियम, 1954 (1954 को 44) की धारा 3 हारा प्रदत्त मिक्तयों ो प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उपमित्र (चयन ग्रेड) (राजस्व II), हिमाचल प्रदेश सरकार, सहायता तथा पुनर्वाम विभाग को, उपमित्र के स्पर्म उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य में ''मुआवजा पूल'' भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम हारा अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त आयुक्त के स्पर्म गए कार्यों का निष्पान्दन करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

इससे विनां र 28 जुलाई, 1975 की ग्रिधित्चना संख्या— 5(2)/75-विन्ते ० /एस० एस० II का ग्राधकमण किया जाता ह ।

[सं.
$$1(19)$$
/वि०सं० $/84$ -एस०एस $\mathbf{H}(\mathbf{\xi})$]

S.O. 4094.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Deputy Secretary (Selection Grade) (Revenue-II) to the Govt. of Himachal Pradesh, R&R Department as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Deputy Secretary the function assigned to such Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the "Comp.nsation Poof" within the State of Himachal Pradesh.

This supersedes Notification No. 5(2)/75-Spl. Cell/SS.II dated 28th July, 1975.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(E)]

हा ० आ ० 4095 - निष्कान्त सम्पत्ति प्रशासन
प्रधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा
प्रदत्त प्रक्तियों या प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सचिव,
सहायता तथा पुनर्वात विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को
सचिव के रूप में प्रपने पार्यभार के प्रतिरिक्त उक्त
प्रधिनियम द्वारा प्रथवा उसके प्रधीन उप महाभिरक्ष । को
सौंपे गए कार्यों था निषटान करने के प्रयोजनार्थ तराल
प्रभाव से उप महाभिरक्षक, निष्कान्त सम्पत्ति के पद पर
नियुक्त करती है।

 $[\ddot{\mathfrak{u}} \circ 1(19)/\ddot{\mathfrak{u}} \circ \ddot{\mathfrak{u}} \circ /84$ -एस ०एस ० Π (एफ)] डी ० डी ० डी ० इंग्टी, श्रवर सचिव

S.O. 4095.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) the Central Government hereby appoints, with immediate effect, Secretary, R&R Department, Government of Himachal Pradesh to be the Deputy Custodian General of Evacuee Property in addition to his own duties, as Secretary for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian General by or under the said Act,

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(F)]
D. D. INGTY, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 श्रगस्त. 1985

का. म्रा० 4096 . - विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुन-वांत्र) म्राधितियम, 1954 (1954 का 44) की घारा 34 की उप धारा (2) द्वारा प्रवंत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दें इस विभाग की दिनां है 2-8-85 की म्राधिसूचना संख्या 1(19)/वि०सैं./85-एस० स० $\mathbf{H}(\mathbf{H})$ द्वारा भन्दोबस्त म्रायुक्त की गिक्तयों का प्रयोग कर रहे उप सचिव, राजस्य मृत्या प्रयोग कर प्रवंश सरकार, सहायता और पुनर्वात विभाग को मुख्य बन्दोबस्त म्रायुक्त की निम्नलिखित शक्तियों सौंपतां हूं :---

- उक्त भ्रधितियम की धारा 23 के भ्रधीन भ्रपील सुनने की शक्तियां।
- 2. उक्त प्रधितियम की धारा 24 के प्रधीन पुतरीक्षण सुनने की शक्तियां।
- उक्त श्रिधिनियम की घारा 28 के श्रिधीन मामलों के हस्तान्तरण की णिक्तियां।
- 2. इससे 28 जुलाई, 1975 की श्रिधसूचना संख्या 5/2/75-वि. से ०/एस ०एस II का श्रिधकम किया जाता है।

[सं o 1(19)/त्रि oसे o/84-एस oएस o II(डी o)]

New Delhi, the 14th August, 1985

S.O 4069.—In exercise of the powers conferred by Subsection (2) of Section (34) of the Displaced Hersons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) I hereby delegate to Deputy Secretary, (Rev.-I), to the Government of Himachal Pradesh, R&R Department, appointed as Sculement Comissioner vide this Department's Notification No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(C) dated 2nd August, 1985 the following powers of the C.S.C.:—

- (i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said Act.
- (ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.
- (ili) Powers to transfer cases under Section 28 of the said Act.
- 2. This supersedes Notification No. 5/2/75-Spl. Cell/SS.II dated 28th July, 1975.

[No 1(19)/Spl. Cell/84-SS. II(D)]

का ० था ० 4097 .-- निष्कान्त सम्पत्ति प्रणासन प्रधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा महाभिरक्ष इ के रूप में मुझे प्रदत्त पाक्तियों जा प्रयोग करते हुए, में इन विभाग की श्रिधसूचना संख्या 1 (19)/ वि० से ०/84-एस एस ० \mathbf{H} (एफ) दिनों छ 2 भगस्त, 1985 के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए उप महाभिरक्ष छ,

निष्कांत उम्पत्ति के रूप में तियुक्त सहायता तथा पुनर्वास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरशार के सचिव की महाभिरक्षक की निमालिखित शक्तितयां सौंपता हूं :---

- 1. भ्रधितियम की धारा 24 और 27 के भ्रधीन शक्तिया।
- 2. ग्रिधियम की धारा 10(2)(O) के अधीन िसी भी विकास सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुमादन की मक्तिया।
- 3. निष्कान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 30-क के प्रधोन मामला के हस्तान्तरण की णिक्तयां।

[सं 1(19)/वि०सैं०/84-एस०एस० II (जी)] जी० पा० एम० साहा, महाभारक्षक

S.O. 4097.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by Sub-section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I hereby delegate to Secretary, Relief & Rehabilitation Department, Government of Himachal Pradesh, appointed as Deputy Costodian General of Evacuee Property for the State of Himachal Pradesh vide this Department's Notification No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(F) dated the 2nd August, 1985, the following powers of the Custodian General:

- (i) Powers under Sections 24 and 27 of the Act.
- (ii) Powers of approval of transfer of any Evacuee Property under Section 10(2)(0) of the Act.
- (iii) Powers of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(G)] G. P. S. SAHI, Custodian General

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासिक सुधार और लोक शिकामत

तथा पैशन मेनालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

का. आ. 1098 - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त मिलतयों का प्रयोग करते हुए, निम्निलिखित अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में विनिदिष्ट करती हैं जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:--

- (क) आतंकवादी और विष्यंसकारी क्रियाकलाप (निवा-रण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 4 और धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन दंडनीय अपराध; और
- (ख) ऊपर उल्लिखित अपराध, और वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनकी बाबत, प्रयत्न, हुष्प्ररण और षड्यंन।

[संख्या 228/21/85-ए०वी० डी० 1]]

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMN. REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4098.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifics the following offences as offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment namely:—

- (a) Offences punishable under sub-sections (2) and (3) of section 3, section 4 and sub-section (4) of section 13 of the Terrorist and Disputive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985); and
- (b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, the offence mentioned above and any other offence committed in the source of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228]21]85-AVD.II]

का. आ. 4099 .--कन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियस, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:--

- (क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध-
- (ख) ऊपर उल्लिखित अपराध और वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनकी बाबस प्रयस्त, दुष्प्रेरण और पहुर्यक्ष।

[सं. 228/22/85-ए०वी०डी० II(i)]

S.O. 4099.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment A.t. 1946 (2.5 of 1946, the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

- (a) Offences punishable under section 34 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);
- (b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, the offences mentioned above and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228[22]85-AVD-H(i)]

आदेश

का. आ. 4100 .— केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वाराप्रदक्ष गिक्तयों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार की सहमित से, पंजाब के संगरूर जिले के शेरपुर थाने में 20 अगस्त, 1985 को की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 98 के अधीन रिजस्टर किए गए मामले की बाबत, भारतीय दंड संहिला, 1860 (1860 का 45) की धाराएं 302, 307 और 34, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 और धारा 27 और आतंकवादी और विध्वसंकारी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) की

धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराधों के, तथा वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधां के संबंध में या उनसे संबंधित, प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और पड्यंत्रों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का समस्त पंजाब राज्य पर विस्तार करती है।

[संख्या 228/22/85-ए. वी. डी. (II) (ii)] एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4100—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Punjab, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment of the whole of the State of Punjab for the investigation of offences punishable under sections 302, 307 and 34 of the Indian Panel Code, 1860 (45 of 1860), sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) and section 3 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts, in regard to the case registered under FIR No. 98 dated 20th August, 1985 at Police Station Sherpur, District Sangrur, Punjab.

[No. 228]22]85-AVD.II(ii)] M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1985

(आय-कर)

का.आ. 4101:—-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सोसाइटी ऑफ दि फ्रांसिसियन (हास्पिटलर) सिस्टर्स, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1985-86 के अंतर्गत आने वाली अविध के लिए अधिसुचित करती है।

[सं. 6323 (फा.सं. 197/40/83-आ.क.नि.-1)] पी. सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
New Delhi, the 16th July, 1985
(INCOME-TAX)

S.O. 4101.—In exercise of the powers conferred by subclause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Society of the Franciscan (Hospitaller) Sisters, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1985-86.

[No. 6323 (F. N. 197|40|83-ITI(AI)] P. SAXENA, Dy. Secy. (आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1985

का. आ. 4102 .—प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदृश्वारा श्री डी. के. गुप्ता को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगा-बाद (मध्य प्रदेश) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29-6-85 से प्रारम्भ होकर 30-6-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी. के. गुप्ता अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ-2-8/82-आर आर बी.] च. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 12th August, 1985

S.O. 4102.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri D. K. Gupta as the Chairman of the Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad (MP) and specified the period commencing on the 29-6-85 and ending with the 30-6-88 as the period for which the said Shri D. K. Gupta shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-8]82-RRB] C. W. MIRCANDANI, Director

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1985

का आ. 4103 — बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्ष बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध 31 दिसम्बर, 1985 तक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक इनका संबंध मेसर्स वंगाल हेल्थ एंड केमिकल वक्स लि. में गिरवीदार के रूप में 10 रुपये प्रति णेथर के हिसाब से 10,050 शेयरीं की शेयर धारिता से है।

[स्॰ .-15/29/79-बी. ओ III] एम. के. कुट्टि, अवर सचिव

New Delhi, the 16th August, 1985

S.O. 4103.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsection (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a period upto the 31st December, 1985 in respect of its holding 10,050 shares of Rs. 10|- each in M|s Bengal Health and Chemical Works Ltd., as pledgee.

[No. 15]29[79-B.O. III]

का. आ. 4104. — बैककारी टिनियमन अिंधनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शिक्टयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की

उपधारा (2) के उपबंध यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता पर अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की उंग्रेश तक उस मीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक इनका संबंध मैंसर्स स्टार्लिंग फार्मास्यूटिकल्स प्राडक्ट्स को शि ति की शेयर शेयर धारिया से हैं।

[सं. एफ-15/1/84-बी.ओ..3] एम. के. एम. क्टिंट, अवर सचिव

S.O. 4104.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsection (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a period of two years from the date of the notification insofar as they relates to its holding of shares of Mis. Sterling Pharmaceutical Products Co Pvt. Ltd.

[No. 15]1]84 B.O. 111] M. K. M. KUTTY, Under Secy.

वाणिज्य महालय

् (मुख्य नियल्लक आयात-निर्यात का कार्यालय) नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

आदेश

का. आ. 4105 — मैसर्स तिमलनाडु न्यूजिप्टि एवं पेपर लि., 16 व्हाईट रोड, मद्रास-600014 को 100 मिलियन डालर्स की विश्व बैंक ऋण के अधीन प्ंजीगत माल आयीत करने के लिए 1,18,80,200/- रुपए (एक करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार और दो सी रुपए मान्न) के लिए आयात लाइसेंस सं. आई/सी/जी/2040450, दिनांक 8-7-1983 दिया गया था।

पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति की अनुिलिप प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आयेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति के आंणिक रूप से 1,16,09, 71,5-/ क्पए के मूल्य के लिए उपयोग में लाई गई थी।

- 2. अपने नकं के समयंन में, लाइसेंसधारी ने नोटरी पिछतक मद्रास के सम्मुख विधिवत गपथ लेते हुए स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्न वाखिल किया है। तदनुसार, मैं ससुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. आई०/सो०जी०/2040450, दिनांक 8-7-1983 की मूल सीमा शुल्क प्रयोंजन प्रति पार्टी द्वारा खो गई हैं अथवा अस्थानस्थ हो गई है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) के अधीम प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैंसर्स तिमलनाडुन्यूजप्रिट एण्ड पेपसं लि., मद्रास को जारी की गई उक्त मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सं. आई/सी जी/2040450 दिनांक 8-7-1983 एतद्वारा रह की जाती है।
- उक्त लाइसेंस की सीमा मुल्क प्रयोजन प्रति की अनु लिपि प्रति पार्टी को अलग से जार की जा रही है।

[सं. सी जी II/आई डी/13/83-84/565]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 20th August, 1985

ORDER

S.O. 4105.—M|s. Tamil Nadu Newsprint & Paper Ltd., 16-White Road, Madras-600014 were granted an import licence No. I|CG|2040450 dated 8-7-83 for Rs. 1,18,80,200 (Rupecs One Crore eighteen lahks eighty thousand and two hundred only) for import of capital goods under World Bank Loan of 100 million Dollars.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original customs purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the licence was registered with Madras Customs Authority and as the value of Customs purpose copy has utilised partly for Rs. 1,16,09,715]-.

- 2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Madras. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of Import Licence No. I|CG|2040450 dated 8-7-83 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the power conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes copy No. I|CG|2040450 dated 8-7-83 issued to M/s. Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd., Madras is hereby cancelled.
- 3. A duplicate Customs purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/ID/13[83-84]565]

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

आदेश

का. आ. 4106.—श्री रतन के० हेमनानी, 713-रहेजा सेन्टर, नारीमन पाइंट, बम्बई-21 को आवेदक की स्वयं की विदेशी मुद्रा बचत के अधीन फांस/आस्ट्रिया से संलग्न सूची के अनुसार बेफर बिस्कुटों के विनिर्माण के लिए पूंजींगत माल मशीनरी के आयात के लिए 13,38,300/- रुपए (तेरह लाख अड़तीस हजार तीन सौ रुपए माल) (अमरीकी डालर 110878) के लिए एक आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2096846, दिनांक 22-11-1984 जारी किया गया था।

- 2. पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिप प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत किए और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।
- अपने तकं के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका, 1985-88 के अध्याय दो के पैरा

86 में यया अपेक्षित एक शपय-पत्न दाखिल किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि पार्टी द्वारा आयात लाइ से सं. पी/सीजी/2096846, दिनांक 22-11-1984 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। यथा संशोधित अयत नियंत्रण आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री रतन के हेम।नी, बम्बई को जारी किए गए आयात लाइ सेंस सं. पी/सीजी/2096846, दिनांक 22-11-1984 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रह की जाती है।

 उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल नं. 1137/28/आई एन एस ए/84-85/सीजी-4] पॉल बैंक, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 22nd August, 1985 ORDER

- S.O. 4106.—Shri Rattan K. Hemmani, 713, Raheja Centre Nariman Point, Bombay-21 was granted an import licence No. P[CG]2096846 dt. 22-11-84 for Rs. 13,38,300]- (Rupees Thirteen lakhs thirty eight thousand and three hundred only) (US \$ 110878) for import of capital goods machinery for the manufacture of wafer Biscuits as per list attached from France Austria under applicant's own foreign exchange saving abroad.
- 2. The party has applied for issue of Duplicate Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes copy of the licence has been lost misplaced without having been registered with any Customs authority and not utilised at all.
- 3. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit as required in Para 86 of Chapter II of Hand Book of Import-Export Procedures 1985-88. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of Import Licence No. P|CG|2094846 dt. 22-11-84 has been lostlimically by the party. In exercise of the power conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purpose copy of Import Licence No. P|CG|2096846 dt. 22-11-84 issued to Shri Rattan K. Hemnani, Bombay is hereby cancelled.
- 4. A duplicate Customs Purposes Copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 1137]28]INSA[84-85]CG IV]
PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Fxports.

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1985

का आ. 4107.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रोय सरकार एतब्द्वारा मैसर्स ईस्टर्न कछार टी कम्पनी लिनिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9, बाबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पन्न संख्या 2298/85) के निरस्तीकरण को अधिसुचिन करती है।

[सं. 16/115/85-एम-3]

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs) New Delhi, the 19th August, 1985

S.O. 4107.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Eastern Cachar Tea Company Limited having its registered office at 9, Brabourne Road, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 2298|85).

[No. 16|115|85-M.III]

का. अ. 4168. — एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधि-नियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतब्दारा मैसर्स औरिफटल पावर केबल्स लिमिटेड फंजीकृत कर्ण्यालय, पी. ओ. व्यन्त नगर, स्टन. अलिनया, जिला कोटा (राजस्थान) व्यक्तिथन अधिनियम व्यअंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1239/76) के निरस्तीकरण को अधिमस्ति करती है।

[मं . 16/18/83-एम . -3]

S.O. 4108.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Oriental Power Cables Limited having its registered office at PO. Cablenagar, Stn. Alnia, District Kota (Ralasthan) under the said Act (Certificate of Registration No. 1239) 76).

[No. 16|18|83.M-]II]

का.आ. 4109.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स आई.वी.पी. लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय मणीकान्त एन. रोडिज मार्ग घोरूपदेव बम्बई-400033 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पद्म संख्या 964/74) के निरस्तीकरण को अधिमूचित करती है।

[सं. 16/14/85-एम०-3]

S.O. 4109.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. IVP Limited having its registered office at Shashikant N. Rodji Marg, Ghorupdeo, Bombay-400033 under the said Act (Certificate of Registration No. 964/74).

[No. 16]14]85-M.III]

गा० आ० 4110.----एकाधिकार तथा अकरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969(1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्हारा मैसर्स एलकोन (महास) लिमिटेड, पंजीहर कार्यालय 61/2

बी, इन्नौर हाई रोड, तिख्वोटीयुर, मद्राप-600019 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत गंजीकरण (पंजीकरण गमाण-पत्र संख्या 1485/80) के निरस्तीणरण को अधिसूचित करनी है ।

मिं० 16/23/85-एम०-3]

S.O. 4110.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Elecon (Madras) Limited having its registered office at 61/2B Ennore High Road, Tiruvotiyur Madras-600019 under the said Act (Certificate of Registration No. 1485/80).

[No. 16]23|85.M-III]

का॰ अ११११ — एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्हारा पैसर्स एलकोन इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पंजी त कार्यालय आनन्द सोजिन्ना रोड, वरलभ विद्या नगर-388120 (गुजरात) के व्यथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पन्न मंख्या 1406/78) के निरस्त्रीकरण को अधिमुचिन वर्गनी है ।

[सं० 16/24/85-एम-3]

S.O. 4111.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of Ms. Elecon Engineering Company I imited having its registered office at Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-388120 (Gujarat) under the said Act (Certificate of Registration No. 1406 [78].

[No. 16]24]85.M-III]

का ० अ१० 4112----एकाधिकार तथा अवरोधह कापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एहद्हारा में सर्स उमको एलकोन (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत गार्यालय आनन्द सोजिला रोड, बल्लम विद्या-भगर-388120(गुजरात) के कथित अधिनियम के अन्तर्गत रंजीलरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1429/78) के निरस्त्री धरण को अधिसूचिन करती है ।

[मं॰ 16/25/85-एम-3]

S.O. 4112.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Emco Elecon (India) Limited having its registered office at Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-388120 (Gujarat) under the said Act (Certificate of Registration No. 1429/78).

[No. 16]25[85.M-111]

कार्ल्यात 4113 - एलाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यापहार अधिनियम, 1969 (1969 पा 54) की धारा 28 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा मैसर्स मर्करी पेन्ट्य एण्ड बार्तिश ितिटेड, पंजी त आयित्य वीर सावरकार मार्ग, प्रभावेती, बस्वई-400025 के छथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रभाग-पत संख्या 1353/77) के निरस्ती उरण को अधिसूचित करती है।

[सं 0 16/27/84-एम-3]

S.O. 4113.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Mercury Paints and Varnishes Limited having its registered Office at Veer Savarkar Marg. Prabhadevi, Bombay-400025 under the said Act (Certificate of Registration No. 1353|77).

[No. 16/27/84-M-III]

का०आ० 4114—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुत्रण में केन्द्रीय सरकार एतब्द्वारा मैंनर्स ब्लॉ प्लास्ट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी०आई०पी० हाउस, 88-सी० ओल्ड प्रभादेवी रोड, बम्बई-400025 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजी उरण, (पंजी उरण प्रमाग-पज मंख्या 2103/84) के निरस्त्रीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं ० 16/28/85-एम०-3]

S.O. 4114.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Blow Plast Limited having its registered office at VIP House, 88-C. Old Prabhadevi Road, Bombay-400025 under the said Act (Certificate of Registration No. 2103|84).

[No. 16]28]85-M-ΠΠ

का०आ० 4115---एकाधिशार तथा अवरोधश व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुप्तरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स बी०आई०पी० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजी त कार्यालय वी०आई०पी० हाउस, 88-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, बम्बई-400025 के श्थित अधिनियम के अरार्गत पंजी-रण (पंजी-कारण प्रमाण-पत्र संख्या 2104/84) के निरस्त्रोजरण की अधिमूचित शरदी है ।

मि**०** 16/29/85-एम-3

S.C. 4115.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s, V.I.P. Industries Limited having its registered office at V.I.P. House, 88-C, Old Prabhadevi Road, Bombay-400025 under the said Act (Certificate of Registration No. 2104|84).

[No. 16|29|85.M-III]

्रा॰आ॰ 4116 - एटाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैं सर्व आर०बी॰ रोडा एण्ड अम्पनी लिमिटेड, पंजी त कार्यालय 2, रेडकास प्लेस, पी॰बा॰ नं॰ 2179, कलक्सा-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजी-

रापण प्रमाण-पत्र संख्या 1134/75) के निरस्त्रीकरण की अधिमुचित रापती है ।

सिं॰ 16/42/85-एम॰-3]

S.O. 4116.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. R. B. Rodda & Company Limited having its registered office at 2, Red Cross Place P.B. No. 2179, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1134|75).

[No. 16|42|85.M-III]

कार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुभरण में केन्द्रीय सरकार एनद्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान नेशनल ग्लाम एंड इंडस्ट्रीज लिए पंजीकृत कार्यालय 2, रेड कीस प्लेस, रालाचन-700001 के तथिन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पंज संख्या 1045/75) के तिरस्क्रीकरण को अधिसूचित धरती है।

[सं० 16/43/85-एम०-3]

S.O. 4117.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of Mis, Hindustan National Glass & Industries Limited having its registered office at 2, Red Cross Place, Calcutta-700301 under the said Act (Certificate of Registration No. 1045/75).

[No. 16]43|85.M-IIII

व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 वा अवरोध स व्यापारि उ व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 वा 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्राय सरकार एतब्द्वारा मैसर्स बनारिया जूट बाटन सिल्त निमिटेड, पंजाकृत कार्यालय 4/1, रेड कोड प्राप्त प्रवान-700001 के प्रथित अधिनियम के अनुमान पंजी रूण (पंजीधरण प्रवाग पत्र संक्या 1685/84) के निरस्कीकरण को अधिसृचिन करती है।

[सं॰ 16/55/85 -एम॰ 3]

S.O. 4118.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Kanoria Jute Cotton Mills Limited having its registered office 4|1, Red Cross Place, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1685|84).

[No. 16]55]85.M-III]

का ० अ ० ४ 119. — एक धि तर तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधि ियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धाना (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरणार एक वृह्यारा मैंसर्स एक एक एम-मान्यकाल इन्ह्रस्ट्रीज निमिट्टेड, पंजी देत पार्यालय वा प्रवाना मैंन सन्स, दिनका बाचा रोड, बम्बई-400020 के अधिन अधिनियम के अन्तर्गत पंजी अरण (पंजी करण प्रमाण-पत्र संख्या 1715/84) के निरस्त्रोक्षरण को अधिसूचित अरह, ही।

[सं॰ 16/56/85-एम॰-3]

S.O. 4119.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s, SLM-Maneklal Industries Limited having its registered office at Vaswani Mansion, Dinshaw Vachha Road, Bombay-400020 under the said Act (Certificate of Registration No. 1715/84).

[No. 16|56|85.M-111]

ला॰ अ 120 - स्टाधितात तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधित्यम, 1969 (1969 टा 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स इक्पूपवेंद होता लिमिटेड पंजीकृत विकास वास्तानी मैनसन्त दिन्सा बाचा गंड, प्रकृति 1000 टा में एथित अधित्यम के अनुभीत पंजीकृत (पंजी टिप प्रमाण-पत्र संख्या 1710/84) के तिरस्त्री एरण को अधिमूचित एरती है।

[सं॰ 16/57/85-एम॰-3]

SO. 4120.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Equipment Hoses Limited having its Registered Office at Vaswani Mansions, Dinshaw Vachha Road, Bombay-400 020 under the said Act (Certificate of Registration No. 1710/84).

[No. 16/57/85.M-]II]

का०आ० 4121: - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनयम, 1969 (1969 पा 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुषरण में केन्द्रीय सरकार एतद्हारा मैतर्स वेतिगर-मानरकाल इंगीनियरिंग निमिटेक, पंजीकि कार्यालय वातवानी मैतर्सन्त, विनशा बाचा रोड, बम्बई-400020 के व्यथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्न संख्या 1709/84) के निरस्त्रोक्तरण को अधिस्चित धरती है।

[मं॰ 16/58/85-एम॰-3]

S.O. 4121.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolics and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Benninger-Manck-l'al Engineering Linsited having its registered office at Vaswani Mansions, Dinshaw Vachha Road, Bombay-400 020 under the said Act (Certificate of Registration No. 1709/84).

[No. 16/58/85.M-III]

का ० आ ० 4 122: --- एका धिचार तथा अवरोध क व्यापारिक्त व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुप्रण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा मैं पूर्व मोरीस इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेंड पंजीकृत कार्यालय भोमारी इन्डस्ट्रियल इस्टेंट, पूना-411026 के कथित अधिनियम के अन्तर्ग । पंजीकरण (पंजी करण प्रमाण-यत संख्या 2329/85) के निरस्त्रोधरण को अधिसूचित करती हैं।

[सं॰ 16/62/85-एम॰-3]

S.O. 4122.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Morris Eletronics Limited having its registered office at Bhosari Industrial

Estate, Poona-411026 under the said Act (Certificate of Registration No. 2329/85).

[No. 16/62/85.M-III]

का • आ • 4123 --- एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स कनोडिया एक्सपोर्टन लिमिटेड पंजीकृत जार्यालय 8, बार्बान रोड, जलकत्ता-700001 के व्यथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्न संख्या 2299/85) के निरस्त्रीकरण को अधिसूचित क्राती है।

[सं॰ 16/73/85-एम॰-3]

S.O. 4123.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of Mis. Kanodia Exports Limited having its registered office at 8, Brabourne Road, Calcutta-700 001, under the said Act (Certificate of Registration No. 2299/85).

[No. 16/73/85-M.III]

का॰आ॰ 4134 - एकाधि तर तथा अवरोध त व्यापाएक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 ता 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा में सर्म बंगाल टी एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पंजीरत लार्यालय 9, अबोर्न रोड, धलकाना-700001 के प्राथत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत संख्या 2297/85) के निरस्ती करण को अधिसूचित करती है।

[सं॰ 16/76/85-एम॰-3]

S.O. 4124.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s, Bengar Tea & Industries Limited having its registered office at 9, Brabourne Road, Calcutta-700 001 under the said Act (Certificate of Registration No. 2297/85).

[No. 16/76/85-M.III]

का. आ. 4125.— एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा मैसर्स सोमानी प्रोप्रटीज प्राइवेट लि. पंजीकृत कार्यालय 2, रेड कास प्लेस, कलकत्ता— 700001 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्न संख्या 1136/75) से निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/ 110/ 85-एम.-3]

S.O. 4125.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Somany Properties Private Limited having its registered office at 2, Red Cross Place, Calcutta-700 001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1136/76).

[No. 16/110/85,M-III]

का. आ. 4126 — एकाधिकार तथा अवरोधक ध्यापारिक ध्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उन-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स बारेन टी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय देवहाल टी एस्टेट, पी. ओ. हुगरीजा जिला, डिबरुगढ़, असम-- 786601 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजी-- करण प्रमाण-- पन्न संख्या 1470/79) के निरस्तीकरण को अधिस्थित करती है।

[सं. 16/118/85-एम-3]

S.O. 4126.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Warren Tea Ltd. having its registered office at Deohall Tea Estate, P.O. Hoogrijan Distt. Dibrugath, Assam-786 601 under the said Act (Certificate of Registration No. 1470/79).

[No. 16/118/85-M-III]

का. आ. 4127:—-एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्— द्वारा मैसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय प्रोस्पेक्ट, चेम्बर्स 317/21, डा. दादाभाई नौरोजी रोड, फोर्ट वम्बई— 400001 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण—पत्न संख्या 1526/81). के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं॰ 16/121/85-एम-3]

S.O. 4127.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Dharamsi Morarji Chemical Company Limited having its registered office at Prospect Chambers, 317/21, Dr. Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Bombay-400001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1526/81).

[No. 16/121/85-.M-III]

का. आ. 4128 — एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा मैंसर्स गेणागाई पेपर बोर्डस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय पाल्लीपलायम सलेम जिला— इरोड—638007 (तिमलनाडु) के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण—पत्र संख्या 500/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/129/85-एम.-3]

S.O. 4128.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopo'ies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Seshasayee Paper and Boards Limited having its registered office at Pallipalayam, Salem District, Erode-638 007 (Tamilnadu) under the said Act (Certificate of Registration No. 500/70).

[No. 16/129/85,M-III]

का. आ. 4179. — एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा मैसर्स ग्लास इक्युपमैन्ट (इंडिया) लिभिटेड, पंजीकृत कार्यालय 603-दीप शिखा, 8-राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली-140008 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण) (पंजीकरण प्रमाण-पत्न संख्या 1097/75) के निरस्तीकरण को अधिसुचित करती है।

[ぜ. 16/140/85-収年.-:]

S.O. 4129.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Glass Equipment (India) Limited having its registered office at 603-Deep Sikha, 8-Rajendra Place, New Delhi-110008 under the said Act (Certificate of Registration No. 1097/75).

[No. 16/140/85.M-III]

का, अ:.4130---एका विकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतव्-द्वारा मैसर्स सोफ्टवेयर सर्विसेस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एस पी आई सी सेन्टर, 97— माउन्ट रोड मद्रास— 600032 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण— पत्न संख्या 1714/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

> [सं. 16/6/85-एम-3] वेद प्रकाश गुप्त, निदेशक

S.O. 4130.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Professional Software Services Limited having its registered office at SPIC Centre, 97-Mount Road, Madras-600 032 under the said Act (Certificate of Registration No. 1714/84.

[No.16/6/85,M-III] V. P. GUPTA, Director

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

का.आ. 4131.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजप स्न, तारीख 28 अगस्त, 1982 में प्रकाणित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2985 तारीख 6 अगस्त, 1982 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) की घारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 21159.70 एकड़ (लगभग) या 8562.90 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आगय की सूचना दी थी;

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है;

अतः. अब, केन्द्रीय सरकार ख़क्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अगस्त, 1984 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐमी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है।

अनुसूची गोपाल प्रसाद ब्लाक (तालचेर कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग संख्या राजस्व 1106/81 तारीख 28-12-81

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

कम	र्भं. ग्राम	तहसोल	थाना	ग्राम सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	. 8
1.	मार्वाहरिहरपुर	तालचेर	कोयला खान	5 5	धेनकानल	307.20	भाग
2	चितलपुर) 1	11	20	"	416.00	भाग
3.	बानाबासपुर	31	,,	41	"	346.60	भाग
4.	पुराबे डा	11	,,	40	"	339.12	पुर्ण
5.	गोपाल प्रसाद खामर	11	11	19	,,	96.40	पूर्ण
6.	तेलीपुर	**	7.7	27	17	368.83	पूर्ण
7.	आरक्षित वन	n	,,,		1)	430.00	पूर्ण
8.	गोपाल प्रसाद	,,,	,,	18	11	961.26	पूर्ण
9.	कुमुण्डा	3)	,,	11	11	640.00	भाग

1	2	3	4	5 	6	7	8
10. भालूगाडिया		त लचेर	कोयला खान	52	धेनकानल	670.77	पूर्ण
🕩 बाधुबोले		11	n .	44	77	397.14	पूर्ण
12 कुसुमपाल		23	"	12	73	103.53	पूर्ण
 आसानाबाहली 		11	<i>n</i>	1	"	105.38	पूर्ण
. 4. मालीबान्ध		11	"	54	11	294.49	पूर्ण
l 5. नौमुहित l 6. अन्तीगाडिया		n	"	36	11 ,	157.98	पूर्ण
.ठ. जालगाड्या १७. कालमाचुईन		11	"	3	11	155.93	पूर्ण फर्म
। ८. खुरिंगा		"	11	6 16	1)	1506.78	पूर्ण पर्ण
9. सीलीडा		"	,,	63	"	162.04 1152,00	पूर्ण भाग
o. बीराबारपुर		7)	,,	48	"	77.29	
1. माझीका		"	,,	53	11	. 158.66	पूर्ण पूर्ण
2. सत्यबाडीपुर		,,	11	62	17 -	73.98	र पूर्ण
3. नाथागाम		"	"	34	†1 11	80.73	पूर्ण पूर्ण
4. तेल ईपासी	,	,,	,,	26	,,	239.74	पूर्ण
 श्रासणबाह्ली 		"	,,	47	"	393.76	पूर्ण
छोटा बेरिनी		छेंदीपाडा	बरापाडा	64	 11	35.40	भाग
7. कानकाराई		"	11	65	"	588.80	भाग
8. पिर खा मान		हैंदीपाडा	अरापाडा	66	"	246.16	पूर्ण
9. क्षालीभन्द्रपुर	-	11	"	6 7	11	438.74	पूर्ण
0. आरक्षिस वन (प	गि . एफ .)	11	13		11	1514.00	पूर्ण
1. नीसा		"	17	69	1,	152.00	भाग
2. कालियाकाटा		"	n	70	n	473,60	भाग
3 रामाडीही		अंगुल	अंगुल		11	230.40	भाग
4. निरंजनपुर		"	"	8	ij	192.00	भाग
निरंजनपुर (पी	.आई.टी.) (II)	11	11		11	527.20	भाग
6. आरक्षित वन		11	"		"	256.00	भाग
7. भुवानपुर)1	n	10	11	128.00	भाग
8. जमुनाली		")1	15	**	50.20	भाग
9. व डाझा रन		11	11	5	"	509.01	पूर्ण
0. आरक्षित वन कु	आ जगल	"	1)		11	35.00	भाग
1. बैठियानाली		71	n	4	**	336.83	पूर्ण
2. बारामहीटोला		**	11	7	11	1132.17	भाग
3. नाटांडा		"	j)	3	27	1429.21	पूर्ण
4. अम्बापाल		11	11	1	**	624.64	पूर्ण
5. अम्बापाल जंगल	1	7)	73	2	1)	388.40	पूर्ण
 सानमाहीटोलग् 		,,	11	6	11	51,83	पूर्ण
 खाजूरिया] 		तालचेर	" कोयलाखान	15	"	202.51	ू . पूर्ण
8. नीलाद्रीपुर				35		34.63	ूर्ण पूर्ण
9. वामोल		11	11	25	H		
		",	1)		71	91,14	पूर्ण
0. सारंग ————————————————————————————————————		**	77	60	71	75,00	भाग
1. नाकईपासी []]		11	11	32	11	480.80	भाग
2. प्रसान प्रसाद		11	,,	39	y+	510.42	पूर्ण

कुल क्षेत्र: 21159.70 एकड़ (लगभग) या: 8562.90 हैक्टर (लगभग)

11.5	जात जे	
सीमा	वणन	

क-ख रेखा ग्राम कालियाकाटा से होकर जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख—ग रेखा ग्राम कालियाकाटा, रामाडीही, भुवानपुर, निरंजनपुर, आरक्षित वन, निरंजनपुर र्बा.आई.टी. II, वारामही टोला और जमुनाली से होकर ग्राम बाढ़ाझारन और आरक्षित वन कुंओं जंगल की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती हुई आरक्षित वन कुओं जंगल से होकर जाती है बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग—घ रेखा तहसील अंगुल और तहसील तालचेर की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो नाटिडी व्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

ध —क रेखा ग्राम कालमाचुईन और दानरा, श्राखणवाहली और डानरा, प्रसान प्रसाद और दानरा, नाकईपासी और दानरा, प्रसान प्रसाद और दानरा, पुन नावक्ष्पासी और दानरा की भागतः सम्मिलिस सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।

ड़--च रेखा ग्राम नाकईपासी से होकर जाती है (जो अनंताबरिनी ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'च' पर मिलती है ।

च-छ-ज रेखा ग्राम नाकईपासी और सारंग से होकर जाती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

ज ---झ रेखा ग्राम खाजरिया और कान्थाबुआई की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलती हुई ग्राम तो<mark>लोडो से</mark> होकर, ग्राम तेलीपुर और सोलोडो की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम बाना वासपुर से होकर जाती है और बिन्दु 'ल' पर मिलती है ।

झ-–জা रेखा ग्राम बानाबासपुर, चितलपुर, मार्दाहरिहरपुर और कुनन्डा से होकर जाती है और बिन्दु 'জ' पर मिलती है ।

ज—ट रेखा नवी से होकर, ग्राम द्वोटाबुरिनी और कानकाराई से होती हुई बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

ट—ठ रेखा सड़क की भागतः पूर्वी दिशा के साथ साथ जाती है और ग्राम नीसा में बिन्दु 'ठ' पर मिलती है ।

ठ—क रेखा, ग्राम सीसा से होकर, ग्राम नीसा और नाली क्राह्मणी कालियाकाटा और आरक्षत घन की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ जांती है और आरक्षित बिन्दु 'क' पर मिलती है।

> [फा.सं. 19/28/82-सो.एस./सी.ए.] टी.सी.ए. श्रीनियासन, निदेशक

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 21st August, 1985

S.O.4131.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2985 dated the 6th August, 1982 published in the Gazette of India, dated the 28th August, 1982, under Sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1959 (20 of 1957) the Central Government gave a notice of its intension to 1 respect for coal in lands meaturing 21159.70 acres (approximately) or 8562.90 hectares (approximately) in the loality specified in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 28th August, 1984, as the period within which the Central Government may give notice of its intension to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Gopal Prasad Block

(Talcher Coalfield)

Drg. No. Rev./106/81 dated 28-12-81

(Showing lands notified for prespecting)

SI. No	Village			Tahsil	Police Station	Village number	District	Area	Remarks
1	2		<u>,</u>	3	4	5	6	7	8
1.	Mardahariharpu	 iт		Talcher	Colliery	55	Dhenkanal	307.20	Part
	Chitalpur	,		-do-	-do-	20	-do-	416.00	-do-
	Banabaspur			-do-	-do-	41	-do-	346, 6 0	-do-
4.	Purabeda .			-do-	- d o-	40	-do-	139,12	\mathbf{Full}
5.	Gopal Prasad K	hamar	•	-do-	-do-	19	-do-	96,40	-do-
	Telipur .			-do-	-do-	27	-do-	3 6 8.83	-do-
	Reserved forest			-do-	-do-	·	-do-	430.00	-do-
	Gopal Prasad			-do	-do-	18	-do-	961.26	-do-
	Kumunda .	•		-do-	-do-	11	-do-	640.00	Part
	Bhalugadia	•		-do-	-do-	52	-do-	670.77	Full
	Baghubole .	•		-do-	-do-	44	-do-	397,14	-do-
	Kusumpal		•	-do-	-do-	12	-do- -do-	103.53	-do-
	Asanabahali	•		-do- -do-	-do- -do-	1 54	-do-	105.38 294.49	-do-
	Malibandha	•	•	-do-	-do-	36	:do-	157.98	-uo-
	Nuamuhin	•		-do-	-do-	3	-do-	157.98	-do-
	Antagadia Kalamachuin	•		-do-	-do-	6	-do-	1506.78	-do-
	Khuringa	•		-do-	-do-	16	-do-	162.04	-do-
		•		-do-	-do-	63	-do-	1152.00	Part
	Soloda .	ī	• •	-do-	-do-	48	-do-	77.29	
_	Birabarpur	•							Full
	Majhika .	•		-do-	-do-	53	-do-	158 66	-do-
2.	Satyabadipur			-do-	-do-	62	-do-	73 98	-do-
3.	Nathagan			-do-	-do-	34	-do-	80.73	-do-
4.	Teleipasi			-do-	-do-	26	-do-	239.74	-do-
5.	Brahmanbahali			-do-	-do-	47	-do-	393.7 6	-do-
6.	Chhotaberini			Chhendipada	Jarapada	64	-do-	35,40	Part
	Kankarai			-do-	-do-	6 5	-do-	588.80	-do-
	Pirakhaman		,	- do-	-do-	66	-do-	246.16	Full
	Balichandrapur			-do-	-do-	67	-do-	438,74	-do-
		/m 17 \			-do-		-do-	1514.00	-do-
-	Reserved Forest	(P.F.)		-do-		— 69	-do-	152.00	
	Nisa .	•		-do-	-do-				Part
	Kaliakata .			-đo-	-do-	70	-do-	473.60	Part
3.	Ramadihi .			Angul	Angul	_	-do-	230.40	-do-
4.	Niranjanpur			-do-	-do-	. 8	-do-	192.00	-do-
5.	Niranjanpu: BIT. II	•	•	-d o-	-do-		-do-	527.20	-do-
6.	Roserved forest			-do-	-do-	_	-do-	256.00	-do-
	Bhubanpur	_		-do-	-do-	10	-do-	128.00	-do-
	Jamunali	•		-do-	-do-	15	-do-	50.20	-do-
		•	•	-do-	-do-	5	-do-	509.01	Full
9.	Badajharan	77			-do-	_	-do-	35.00	Part
-	Reserved Forest	K.1100	Jungle	-do-		4	-do-	336,83	
1.	Bethianali .			-do-	-do-	4	-00-	220.02	Full

1	2		2	3	4	5	6 .	7	8
42.	Baramahitole		,	Angul	Angul	7	Dhonkanal	1132.17	Part
43.	Natada .	,		-do-	-do-	3	-do-	1429,21	Full
44.	Ambapal .		,	-do-	-do-	1	-do-	624.64	-do-
45.	Ambapal Jungle			-d <i>o</i> -	-do-	2	-do-	388,40	-d ∩-
46.	Sanamahitola	•		-do-	-do-	6	-do-	51.83	-do-
47.	Khajuria ,			Taleher	Colliery	15	-do-	202.51	-do-
48.	Niladripur			-do-	-do-	35	-do-	34.63	-do-
49.	Damol			-do-	-do-	25	-do-	91.14	-do-
50.	Sarang .			-do-	-cb-	60	-do-	75.00	Part.
51.	Nakeipasi,			-do-	-do-	32	-do-	460.80	-do-
52.	Prasan Prasad			-do-	-d o-	39	-c 5-	510.42	Full

Total area: -21159.70 acres (approximately)

or

8562.90 hectares (approximately).

Boundary description :---

- A-B Line passes through villago Kaliakata and moots at point "B".
- B—C Line passes through villages Kaliakata, Ramadihi, Bhubanapur, Niranjanpur, Reserve Forest, Niranjanpur BIT-II, Baramahitola, and Jamunali, passes along part common boundary of villages Badajharan and Reserve forest Kueo Jungle through reserved forest Keuo Jungle and meets at point 'C'.
- C-D Line passes along the part common boundary of Tahsil Angul and Talhsil Tacher (which forms common boundary of Natidi Block and meets at point 'D'.
- D—E Line passes along the part common boundary of villages Kalamachuin and Danra, Brahmanbahali and Danra, Prasan Prasad and Danra, Nakeipasi and Danra, Damol and Danra, again Nakeipasi and Danra and meets at point 'E'.
- E-F Line passes through village Nakcipasi (which forms common boundary of Anantaberini Block) and meet at point 'F'.
- F-G-H lines pass through villages Nakeipasi and Sarang and meet at point 'H'.
- H—I Line passes along part common boundary of villages Khajuria and Kandhobuani, through village Soloda passes along common boundary of villages Telipur and Soloda, through village Banabaspur and meets at point T.
- I-J Line passes through villages Banabaspur, Chitalpur Mardahariharpur and Kununda and meets at point "J'.
- J-K Line passes through river through village Chhotaberini and Kankarai and meets at point 'K'
- K-L Line passes along part eastern side of road and meets at point 'L', in village Nisa
- L—A Line passes through village Nisa, passes along part common boundary of villages Nisa and Malibrahmani, Kaliahata and Reserve Forest and meets at starting point 'A'.

[No. 19/28/82-CL/CA] T.C.A. SRINIVASAN, Director

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

का. आ. 4132:—यतः पेट्रोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधिस्चना का. आ. सं. 4503 तारीखं 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का

अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देशी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पक्ष्वात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिनत का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुनूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतों है कि उका भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित्त होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित्त होगा।

अनुसूची हाजिरा बरेली जैगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेन्ट

	जिरा बरेर				ोजेक्ट
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गरार
					गया रकवा
			<u> </u>		
1	2 	3	4	5	6
इटावा	विधुना	विधुना	चौदा	56	0-12
				1.3	0-0
				20	0-0 5
				24	0-27
	•	I		48/2	0-02
				50	0-37
				18	0-29
				62/1	0-17
				15	0-26
				14	0-0
				8	0-11
				5	0-08
				51	0-13
				23	0-13
				16	0-0
				7	0-16
				6	0-44
				55	0-15
				52	0-12
				53	0-13
				54	0-39
				19	0-03
				49	0-02
				62/2	0-03

[मं. O-14016/393/84--जी पी]

MINISTRY OF PETROLEUM New Defhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4132.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4503 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals P pelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this neithfeat on:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government bereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Itd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tohsil	Pargana	Village	Plot No	. Area Acquired
1	2	3	4	5	··· —_6
Etawa	Bidhura	Bichura	Chordi	56	0-12
				13	0-06
				20	0-05
				24	0-27
				48/2	0-02
				5 0	0-37
				18	0-29
				62/1	0-17
				15	0-26
				14	0-01
			•	8	0-11
		1		5	0~08
				51	0-13
				23	0-12
				16	0-06
				7	0-16
				6	0-44
			•	55	0-15
				52	0-12
				53	0-13
				54	0-39
				19	0-03
				49	0-02
				62/2	0-03

[No. O 14016/393/84-GP]

का. आ. 4:33.--यता पेट्रोलियम और यांनिश पाइम-अव्हर्न (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम गद्रालय की अधिसूजना था. आ. सं. 4504 तारीख 3:12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूजना में संलग्न अनुसूजी में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनो की बिछाने के लिए अजिन कानी का अपना आजा घोषित कर विज्ञासा

अंति यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे की है। ्और आगेयतः केन्द्रीय सरकार ने अक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पत्रचात् इन अधिनुचना से संलग्न अनुसूचों में विनिधिट भूमियों मे उप-सोग का अधिनार अजित करते का विनिध्या किया है।

जन्म, जन, उन्नन जिनियम की धारा 6 के उपनारा (1) हार। प्रदश्त प्रिन्ति का प्रमीप नारम हुए कन्द्रीय भरावर एनद्द्राना प्रीपित करती है कि इस अधिमुक्का में संजन्म अपुम्मी में विनिद्धित उक्त भूमियों में उपयोग का विभागर पाद्द्रण लाइन बिळाने के प्रयोजन के थिए एनद्द्रारा अजिन किया जाता है !

और आने उस धारा की उपबादा (4) द्वारा प्रदेश णिक्यों का प्रयोग करने हुन, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिन होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. ये सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की, इस तारीख का निहित होगा।

अनुमुची

हा	जिरा⊸बरेली	–जगदीशप्	रु पा इ प	लाइन प्रोप	जेवट
जिला	 तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकवा
1	2	3	4	5	6
इटावा	विध्ना	 विधुना	हरवंश	· -	
			पुर	451	1-36
				452	0-48

451	1-36
452	0-48
448	0-02
435	0-27
434	0-57
437	0-63
431	1-20
139/5	0-03
440/1	0-01
400	0-10
401	0-15
40?	0-06
403	0-22
404	0-22
405	0-15
399	0-07
406	0-08
318	0-67
. 81	0-18
93	0-15
94	0-10
71	0-20
72	0-16
73	0-03
70	0-60
69	0-15
68	0-12
63	0-12

	2	3	-1	5 ,	6
				${64/1}$	0-02
				52	0-12
	,			53	0-03
				51	0-01
				50	0-67
				48	0 → 1 0
				43	0-08
				44	0-42
				42	0-02
				35	0→75
				22	0-37
				25	0-57
•				24	0 - 20
				23	0-01
				36	0-03
				393	0- 03
				394	0~ 0 1
				319	0-06
				92	0-16
				317	$0 \rightarrow 0$

[मं. O-14016/34/804-जीपी]

S.O. 4133.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petrolcum S.O. 4504 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laving pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in 'the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Harbans Pur	451 452	1-36 0-48
				448	0-02

PART JISec. 3(ii)	ſ	PART	JISEC.	3(ii)
-------------------	---	------	--------	-------

1	.2	3	4	۲	(t .					कार की पा	
		-		4 35	027	को बिछा	ने के लिये	জিনি ন	करने का	अपना आध	॥य घोषित
				434	0.57	कर दिया	था।				
				437	0 - 63	अती ज	क्त' स्या	र प्रतिशक्त	र्की के जब	त अधिनि यम	। क्री धारा
				431	1-20					ा आजापर रको रिपोर्ट	
				439/5	0-03		1 1				
				440/1	0 -01	और	अ।भे,	यतः केंद्री	य सर्का	र ने अक्त	रिपोर्ट पर
				400	0.40	विचार क	रने के पा	म्चात् इस	। अधिसूचः	ना में मंलग	न अनुसूची
			,	401	0-15	में विभिन्नि	रप्ट भूमिर	प्रों में उप	योग का	अधिकार अ	जिंत करने
				402	0-06	का विनि	श्चय किय	१ है।			
				403	0-22			•		*** Tr /: #	-h -m
				404	0-22					धारा 6 व	
				405 399	0-15 0-07	` '				रते हुए केन्द्र	
				406	0 -08					. अधिमूचना	
				318	0-67					में उपयोग व	
		•		81	0-18	प∂इप ला	डेन बिफ्राने	के प्रयो	जन के वि	लिए एसद्द्व	ाग अजित
				93	0-15	किया जा	दा है।				
		=		94	0-10	ਆ ਹੈ ਹ	आसे भा	ਰ ਸ਼ੀਤ ਸ	की उत्तर	ाग (4) ह	द्वारा प्रसटन
		,		71	0-20					ारा (क्) । सरकार निवे	
				72	0-16						
				73	0-03	-	•			केन्द्रीय सरका चन्द्रीय सरका	
				70	0-60	_				लिमिटेड में स	
				69	0-15	3		धाषणा	के प्रकाश	न की इस	ताराख्य का
				68	0-12	निहित हो	गा।				
				63	0-12			अनुस्	चो		
				64/I 52	0-02 0-12			_			
				53	0-03	द्राप	जरा—बर्ल	ोजगदीः 	भर्ते ताक	प लोइन प्र	जिम्द
				51	0-01	কিকা	तहसीन	प्रगना	स्रा	गाटा मं.	लिया
				50	0-67						गया
				48	0-10						(कवा
				43	0-08						
				44	0-42	1	2	3	4	5	6
				42	0 -02						()
				35	0- 75	च का कार्री	- ਜਿਸ ਕਾ		п иба-	0.1.1	
				22 25	0-37	इट≀वाहुँ	विधूना	(अवूग)	पूर्वावले	211	0-33
				25 24	0-57 0- 2 0					210	0 17
				/. T	リームリ					209	0-02
				23	0-01					208	0 - 38
				23 36	0- 0 1 0-03					$208 \\ 206$	0-38 0-02
				23	0- 0 1 0-03 0-03						
				23 36 393	0- 0 1 0-03					206 205	0-02 0-47
				23 36 393 394	0-01 0-03 0-03 0-01					206 205 204	0-02 0-47 0-09
				23 36 393 394 319	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06					206 205 204 203	0-02 0-47 0-09 0-48
			—•——	23 36 393 394 319 92 317	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06 0-10 0-02					206 205 204 203 218	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34
	<u> </u>	······································	[No.	23 36 393 394 319 92 317	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06 0-10					206 205 204 203 218 219	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34 0-33
		······································		23 36 393 394 319 92 317	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06 0-10 0-02 					206 205 204 203 218 219	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34 0-33
क् रि. ३	¥T. 413	 3·4 यत	''पेट्रोलि	23 36 393 394 319 92 317 . O-14016	0-01 0-03 0-03 0-01 0-01 0-06 0-10 0-02 					206 205 204 203 218 219 198	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34 0-33 0-08
इस (भू	्मि में उप	ायोग के ३	ं पेट्रोलि अधिका र	23 36 393 394 319 92 317 O-14016 यम और	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06 0-10 0-02 					206 205 204 203 218 219 198 197	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34 0-33 0-08 0-11
इन (भू 962 (:	[मि में उप 1962 की	ायोग के व ा 50) व	ं पेट्रोलि अधिकार हीं धार	23 36 393 394 319 92 317 O-14016 यम और का अर्जन	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06 0-10 0-02 					206 205 204 203 218 219 198 197 196 220	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34 0-33 0-08 0-11 0-11
इन (भू)62 (: अधीन	्मि में उप 1962 का न भारत	ायोग के व ा 50) व सारकार	ं पेट्रोलि प्रधिकार हीं धार के ऊर्जा	23 36 393 394 319 92 317 O-14016 यम और का अर्जन मंत्रालय	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06 0-10 0-02 					206 205 204 203 218 219 198 197 196 220 182	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34 0-33 0-08 0-11
इन (भू 62 (: अधीन गगकी	मि में उप 1962 का 7 भारत अधिसूचना	।योग के व 1 50) व सरकार 1 का. आ	" पेट्रोलि अधिकार ही" धार के `ऊर्जा . सं. 4	23 36 393 394 319 92 317 O-14016 यम और का अर्जन 1 3 की '	0-01 0-03 0-03 0-01 0-06 0-10 0-02 					206 205 204 203 218 219 198 197 196 220	0-02 0-47 0-09 0-48 0-34 0-33 0-08 0-11 0-11

3 -						- 					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
,,				166/412	0-42				-	198	008
				374	1-13					197	0-11
				•						196	0-11
		•		375	0-79					220	0-04
				383/1	0-10					182	0-25
				383/2	0-16					221	0-77
				385	0-20					222	0-51
				384	0-83					166/412	
				391	0-77					374	I-13
				393	0-42					3 7 5	079
				217	0-15					383/1	0-10
					·					383/2	0-16
		[सं.	O- 140	016/395/84-	–जा पा]					385	0-20
S.O.	4134\	Whereas by	notificati	on of the Go	overnment					384	0-83
of Indi	of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4505 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum									391	0-77
and Mi	nerals Pi	pelines · (A	Acquisition	of Right of	Us e r in				-	373	0-42
				he Central Go ight of user in					•	217	0-15
specified	l in the		ipp e nded	to that notific			m=+- 1- 1			AL /	U-1)

[No. O-14016/395/84-GP]

purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Anthority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notificamen hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this data of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDÜLE

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot	N.	Area Acquired
1	2	3	4		5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Purwa	211		0-33
			Valay	210		0-17
			-	209		0-02
				208		0 - 38
				206		0 - 02
				205		0-47
				204		009
				203		0-48
				218		0 34
				219		0 - 33

का०आ० 4135 व्यतः पेट्रोलियम और खिनज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० मं० 4509 तारीख 22-12 84 हारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमिशों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों की बिछाने के लिए अजित करने का अपना आणय घोषित कर विदा था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है।

और आगे गतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिकोर्ट पर विचार करने के पण्चात इस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिल्व दिख्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिण्चय किया है।

अब. अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) बारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतट्डारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विकान के प्रयोगन के लिये एतद्डारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में गभी पाधाओं ने मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अन् सूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर	पाइव	साइन	प्रोजेक्ट
Guara azan anana Zz	119(7		41440

जिला	तहमील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिय गया रकवा
1	2	3	4	5	6
 इटांबा	विधूना	 विधूना	बहादूरपु		·
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	सहार	52	0-08
-				54	0-02
				58	0-3-
				5 7	0-3
				7 1	1-16
				75	0-13
				74	0-2
				88	0 - 18
				89	0-07
				90	.12
				91	0-7
				92	0 04
				97	0-02
				98	0-02
				350	0-40
				351	0-23
				352	0-03
				353	0-14

सि. O-14016/399 84-जीपो]

S.O. 4135.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4509 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira - Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tohsil	Pargana	Village	Plot	No.	Area Acquired
1	2	3	4	= -	5	6
Etawa	Bidhur	a Bidhura	a Bahadi	tr 52	~	0-08
			pur	54		0~02
			Shahar	58		0-34
				57		035
				71		116
				75		0-12
				74		0-24
				88		0-15
				89		0-07
				90		1~25
				91		0-71
				92		0~04
				97		0-02
				98		0-02
				350).	0-40
				351		0-23
				352	;	0~03
				353	3	0-14

<u>L</u>

को. भी. 4136--- यतः पट्टोलियम भीर खनिश पाष्टप लाइन (भूमि में उपयोग के भ्राधकार का भर्जन) भ्राधिनियम, 1962 (1962 का को 50) का धारा 3 क. उपधारा (1) के भ्रधन भारत स कार के पेट्रोलियम मंत्रालय के भ्राधिनुषना का. भ्रा. सं. 1501 तारं ख 27-12-84 द्वारी केन्द्रीय सरकार ने उस श्रीधमूबना से सलग्त श्रनुसूच, में 1:निविष्ट भूमियों के उपयोग के श्रीधकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए श्रीजत करने का अपना श्राह्मय धार्षित कर दिया था।

भौर यतः सक्षम प्राधिकारं। ने उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

श्रीर श्रागे, यतः केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न श्रनुसूचं में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार श्राजित करने का विनिध्यय किया है।

श्रव, अतः उक्त सधितियम क धारा 6 कः उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्द्वारा घोषिन करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूचः में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विद्याने के प्रयोजन के लिए एनद्द्वारा अजित किया जाना है।

श्रीर श्रामे उस धारा को उपधारा (1) हारा प्रदत्त शिक्तयो का प्रयोग करने हुए केन्द्र य सरकार निर्वेण देते. है कि उक्त भूमियों में उपयोग का श्रीधकार केन्द्राय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभं, बोधाओं से मुक्त यप मं बोषणा के प्रकाशन को इस ताराख को निहित होगा।

0 - 08

886

~~~	TAXABLE IN
- MIN	
91.1	<b>M</b> -111

अनुसूची 					S.O. 4136.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4501 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3	
 हां तिरा 	 बरेला -जग 		 पाइप ल 	 ।इन प्रोजेक्ट 	· -	of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Righ of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govern ment declared its intention to acquire the right of user in
जिला	तहमील	प्रशन्त	ग्राम	गाटा म	लिया	the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;
					गया रक्षवा	And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report
	2	3	4	 5	 6	to the Government;  And further whereas the Central Government has, after
 इटावा	 विधृता	 ਰਿध ਜਾ		 615	0-31	considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this
56141	1-1-4-11	(13%,11	94 6	616	0-52	notification;
				621	0~06	Now, therefore, in exercise of the power conferred by
				624	0-03	sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the
				626	0-95	said lands specified in the schedule appended to this notifica-
				622	0-10	tion hereby acquired for laying the pipeline;
				623	0-30	And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the
				625	0-54	right of user in the said lands—shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of
				715	0-03	this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from
				718	0-27	encumbrantes.
				719	0-17	SCHEDULE
					0-36	
				720	0-68	Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.
				722		Distt. Tehsil Pargana Village Plot No. Area
				723	0-21	Acquired
				724	0-22	1 2 3 4 5 6
				773	0-06	
				782	0-01	Etawa Bidhuna Bidhuna Usraha 615 0-31
				787	0-05	616 0-52 621 0-06
				786	0-05	624 0-03
				788	1-39	626 0-95
				801	0-87	622 <b>0–10</b>
				875	1-20	623 0-30
				876	1-07	625 0-54
				877	017	715 0-03
				878	0-02	718 0–27 719 0–17
				883	003	720 0-36
				885	0-03	722 <b>0</b> –68
				886	0-08	723 0-21
				892	0 - 2.7	724 0-22
				893	0-14	773 0-06
				894	0 - 0 6	782 0-01
				907	0-08	787 0-05 786 0-05
				911	0-03	786 0-03 788 1-39
				912	0-20	801 0-87
				913	0 - 2.4	875 1-20
				914	0-12	876 I <b>07</b>
				915	0 01	877 0-47
				916	0-41	878 0-02
				923	0-03	883 0-03
				لبشدر		885 0-03
			- <del></del>			883 U-U3

[सं. O-14016/390/84-जीपी]

4000	4000 THE GAZETTE OF INDIA . SEFJEMI					z			[] ART II -510. 5(1)]		
1	2	3	. 4	5	6	1	2	3	4	5	6
				892	0-27						
				893	0-14					727	0-03
				894	0-06					711	0-44
				907	0-08					729	0-48
				911 912	0~03		,			777	0-22
				912	0-20 0-24					778	0-18
				914	0-12					779	0-01
				915	0-01						
				916	0-41					<b>7</b> 76	0-61
				923	0-02	•				780	0-01
										781	0-18
			ĪNo.	Ö_14016	5/390/84/GPJ					774/9	0-18
			-							774/7	0-18
					ाइपलाडन (भूगि -					774/8	0-01
					८ (1962 का ारत सरक(र के					756/1	0-92
,					रित सरकार क रिना 22-12-84					773	0-08
•					ग्ला अनुसूची में					767/5	0-08
					। प्रमुखना न ।इनों को बिछाने						
	क्र. जैन क∀रने क									767/6	0-06
-										768	0-10
	≀क्षः मक्षम ऽ ⊥) के अधी				ो घारा 6 की					769	0-19
										764	0-12
					र विचार करने र्योजन अस्तिकों के					765	0-01
	इस आधसूर अधिकार अ				र्षिष्ट भूमियों में है।					766	0-10

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदश्य एक्ति का प्रयोग अरते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंतरत अनुसूची में विनिदिव्ट उक्त मूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन विद्यान के प्रयोजन के लिए एत्त्रद्वारा अभिन किया जाता है।

और आसे उस धारा की उपधारा (६) हारा प्रदल मितियों का प्रयोग करते हुए के द्वीय मध्कार निर्वेण वेती है कि उपन भीमयों में जायोग का अधिकार के द्वीय मध्कार में निहिन होने के वंशय भारतीय सैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस नारीख को निहिन होगा।

अनुसूची

A COLUMN TO THE							
हारि	जरा बरेली	जगदीर	ापुर पा	इप लाइन प्र	ोजबट		
जिला	तहसील	परगना	 ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकवा		
1	2	3	. 4	5	6		
इटावा	बिधुना	बिधुना	म् डिक	709	0-15		
			मीत	720/1	0-18		
				708	001		
			-	710	0-09		
				719	0-12		
				718	0-32		
				721	0-20		
				722	0-64		
				728	0-38		

S.O. 4137.—Wheeras by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4506 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying nipeline;

[सं. O-14016/396/84-जी. पी.]

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this nonficiation;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the aid lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## **SCHEDULE**

Ha	jira Bar	cilly Jag	dishpur P	ipe Linc	Project
Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1		3	4 .	5	6
Etawa	Bidhun	a Bidhut	na Modak meat	- 709 720/1	0-15 0-18

1	?	3	4	5	6
		_		708	0-01
				710	0-09
				719	0-12
				718	0-32
				721	0 - 20
				722	0 64
				728	0-33
				727	0-03
				711	044
				7 29	0-48
				777	0 -22
				778	0-18
				779	0-01
				776	0 61
				780	001
				781	<b>0</b> - 18
				774/9	0 - 18
				774/7	<b>0</b> 18
				7:74/8	0 1
				756/1	0 -92
				773	0-03
				767/5	0- <b>0</b> 8
				767/6	0-06
				768	010
				769	0-19
				764	0-12
				765	0-01
				766	010

[No. O-14016/396/84--GP]

का. आ. 4138.— यत पेट्रोलियम और खानिज पाइपलाइन (मृपि मे उपयोग के अधिकार का अर्थन) अधिनयम, 1962 (1982 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलिएए मंत्रालय की अधिनूचना का. आ. मं. 4507 तारीख 12-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिनूचना से संलग्न अनुसूची में निर्निदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप नाइनों की खिछाने के निर्अतित करने था अपना आग्रय योपित कर दिया था।

भीर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 6 की उपभारा (1) के मधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

भीर भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस प्रधिमूचना से संलग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का प्रधिकार मोजिय करने का विनिष्चय किया है।

ध्रव, ध्रत: उनस प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त समित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषिस करती है की इस प्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उनत भूमियों में उपयोग का ध्रधिकार पाइपलाइन श्रिष्ठाने के प्रयोजन के लिए एनद्द्वारा भाजित किया जाता है।

श्रीर भागे जग धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त णिक्तवों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरफार निर्देश देती हैं कि उत्तर वृक्षियों में उपवाग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण जि. में सभी बाबाभों से मुक्त रूप में, गोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

		બહેર્	۳1		
हारि	 ारा बरली	जगदीशपु	र पाइप	लाइन प्रोजेक्ट	. 1
जिला	तहसीत	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकवा
1	2	3	4	5	6
इट <b>ावा</b>	विध् <b>न</b> ।	 विधूना	मुड़िया	524	0-49
		ζ,		525	0-60
				531 .	0-06
				563 .	0-11
				568	0 - 38
				857	0-06
				858	0-7.8
				861	0-2-9
				862	0-79
				863	0 - 27
				564	0-78
		[Ħ. C	)—1,401	6/397/94-5	ग़ि. पी.]

अत धनी

S.C 4128 --Wherevs by notification of the Government of India in the Ministr yof Petroleum S.O. 4507 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared in the schedule appended to that notification for the purpose

of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### **SCHEDULE**

				, -		
Ha	jira Bar	eilly Jagdi	ishpur P	ipe Line	Project	
Distt.	Tehsil	Pargana '	Village	Plot No.	Area Acquired	
<u> </u>		3	4	5	6	
Etawa	Budhur	na Budhun	a Murya	524 525 531 563 568 857	0-49 0-60 0-06 0-11 0-38 0-06	

							- · <del></del> -	<u></u>	
3	A	5	6	. 1	2	3	.3	5	ß
,		858	0 78					111	0-03
		861	0 - 29					181	0-43
									0-55
		564	<b>0–7</b> 8						0-04
	-							95	0-07
	[No. O	-14016/3	397/84 GP]					96	0-02
<del>~</del> –यतः ^{हे}	नेट् <u>रोलियम</u>	<b>और</b> खनि	जिपाइय लाइन					98	0-09
अधिकार	का अर्ज	नि) अधि	नियम, 1962					167	0-01
ो धारा	3 की	उपधारा ।	(1) के अधीन					107	0-27
ोलियम मं	त्रालय क	ो अधिसूष	त्र बनाकाः अतः					105	0-39
2-12-84	द्वारा केन	द्रीय सरका	र ने उस अधि-					104	0 - 27
ची में वित्	<b>वि</b> ष्ट भू	मियों के उ	पयोग के आधि-					145	0-03
						[सं. (	D-14016	392/84	–जी∘·पी.]
	अधिकार ही धारा लियम मं 2-12-84 चीमें विर्ति	[No. O ——यतः पेट्रोलियम् अधिकार का अर्ज गिधारा 3 की गिथाम् मंत्रालय के १-12-84 द्वारा केत् ची में विनिद्विष्ट भू	858 861 862 863 564 [No. O-14016/3 —	858 0 78 861 0-29 862 0-79 863 0-27	858 0 78 861 0 · 29 862 0 – 79 863 0 - 27 564 0 – 78  [No. O – 14016/397/84 — GP] — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ती धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन तियम मंत्रालय की अधिसूचना का अर स्थान	858 0 78 861 0-29 862 0-79 863 0-27 564 0-78  [No. O-14016/397/84GP]	858 0 78 861 0 · 29 862 0 – 79 863 0 - 27 564 0 – 78  [No. O-14016/397/84 — GP] — यतः पेट्टोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ही धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का अः 2-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि- ची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि-	858 0 78 861 0 · 29 862 0 – 79 863 0 - 27 564 0 – 78  [No. O-14016/397/84 — GP] — यतः पेट्टोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ही धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का अः 2-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि- ची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि-	858 0 78 861 0 - 29 862 0 - 79 863 0 - 27 564 0 - 78 95 [No. O - 14016/397/84 GP] 96

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीम सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिक्त का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिद्धिः उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप नाइन विछाने के प्रयोगन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और अामे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देण देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी वाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची हाजिंदा बरेली जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम'	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3 ,	4	5	6
<u>इटा वा</u>	विधृना	———— बिधूना	भगधन्त	171	0-57
.,	•	•	पुर	170	0-49
				179	0-73
				106	0-17

S.O. 4139.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4509 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the light of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the sald Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of nower conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Haj	ira Bareil	lly Jagdish	pur Pipe	Line	Project	
Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot		Area quired
1	2	3	4		5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Bhag- vantpur	171 170 179 106 111 181 92 94	0-: 0-: 0-: 0-: 0-: 0-: 0-: 0-:	49 7 3 17 03 43 55
				96	0-(	)2
				98	0-(	J9

भारते का	राज्ञपक्षाः वि		16,1908	
		 	<del></del>	

_				/ * * h
1 to T.F.	,,,	700 方	-73	( * 1 ) [
1411	11-		.)	
Γ	_ ~			(ii) J

698 GI/85—4

40	-	_
40	ň	- 1

1 2 3 4 5 6		1	2	3	4	5	6
167 0-01	,			,		433	0-48
107 0-27 105 0-39						449	001
105 0-39 104 0-27						435	0-01
145 0-03						436	0-43
[No. Q-14016/392/84-						437	0-16
[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b>~.</b> ]					438	0-47
का , आ . 4140 — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप	लाइन					440	0-36
(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, :						455	0-21
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन						459	0-12
रिकार के पेट्टोलियम मंत्रालय, की अधिसूचना	क्षां.					460	0-30
ा.सं. 554 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार	-					461	0-12
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपर						464	0-22
प्रधिकारको पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित कार						521	0-02
अपना आशय घोषित कर दिया था।						522	0-02
		•				519	0-16
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्स अधिनियमकी						<b>52</b> 6	0-20
$6$ की उपधारा $(1)$ के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे $^\circ$	शे हैं।					527	0~0
और अत्मे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपो	÷					523	0-1
·						529	0-16
वेचार करने के पश्चात् इस अधिमूचना से संलग्न अ र जिल्लामान प्रतिनों में जालीय का अधिमान अधिक क	•					536	0-1
ां विनिद्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकारअजिन क' जिल्लामा	रना भाः					535	0-1
विनिष्चय किया है।						537	0-1
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उ	पधारा					905	0-0
(1) द्वारा प्रदत्त मक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रोय स	<b>र</b> कार					842	0-0
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में	संलग्न					841	0-0
प्रनुसूचो में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग <b>का</b> अ	धिकार		-			843	0-0
।।इपंलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्द्वारा अजित	(किया					844	0-2
नता है।						846	0-1
ं और आमे उस धारा की उपधारा (4) हारा	TT-FRE					849	0-1
जार जाग उस बारा नग उनवारा (क्) आर तिक्तयों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय <b>सरका</b> र निर्देण						850	01
क उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में						848	0-0
क उपना मूलिया ने उपवाद का आवातार कन्द्राव करकार न होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधा						856	0→2
पुरुत क्या में, घोषणा के प्रशासन की इस तारीख़ को						857	0-3
नुष्य १५ मा प्राप्ता के स्वक्ति का द्वाराहिक का होगा ।	1.016.1					858	0-0
						859	0-0:
अनुसूची						860	0-0
हाजिरा बरेली जगदीणपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट						862	0-10
जेला तहसील पराना ग्राम गाटासं.	 लिया					861	0-3
	गया					872	<b>a-</b> 0
	रक्षवा					919	0-0
						997	0-0
1 2 3 4 5	6					968	0-6
टावा त्रिधूना बिधूना धरमगद 428	0-15					969	0-1
पुर 432	0-01					970	0-2
429	0-06					976	0-0
430	0-03					977	0-4
431	0-02					1055	0-0

1 2 3 4	5	6				SCH	EDULE		
	049	0-49	Haj	ira	Bircilly	Jage'is	hpur Gas	Pire I.	ire Project
	050	0-11	District	Т	elisil P	- Pargina	Village	Plot	Area
	0 5 1	0-51					, ,	No.	acqured
	146	0-35	1		2	3	4	5	6
	145	0-03	Etawah	a Ri	ilhun.	Tidha	na Dham	420	0.75
	144	0-11	Btawan	a Di	una		na Puar godpur	- 428 432	0:75 0:01
	150	0-35				maj	30.1pu1	429	0-06
	151	0-71						430	0-03
								431	0-02
	154	0-24						433	0-48
	149	0-27						449	0-01
	196	0-01						435	0-01
	1197	0-5.4						436	0-43
1	198	0 - 31						437	0 -16
1	1200	0 - 0.2						438	0-47 0-36
1	1204	0-15						440 455	0-30
1	205	0 - 55						459	0-12
1	206	0 - 45						460	0-30
1	207	0-07						461	0-17
	1181	0-03						464	0-22
	1182	0-42	*					521	0-02
	1260/1	0-12						522	0-02
	1260/6	0-03						519	0-16
	520	0-30						526	0~20
	524	0-04					٠	527 523	0-01 0~16
		0-02			*			529	0-16
	531							536	0-16
	369	0-01						535	0-13
• •	1260/7	0-37						537	0 -17
[₹ . O-140]	16/01/85-	जी.पी.]						905	006
								842	0-02
S.O. 4140.—Whereas by notification			÷					841	0-04
of India in the Ministry of P dated 9-2-1985 under sub-section (		S.O. 554 tion 3 of					•	843	0-08
the Petroleum and Minerals Pipelines (A. User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)	Acquisition o	f Right of						844 846	0 -22
ment declared its intention to acquire	the right	of user in						849	0-17 0-15
the lands specified in the schedule appetion for purpose of laying pipeline:	ended to the	at notifica-						850	0-10
							,	848	0~04
And whereas the Competent Authority section (1) of Section 6 of the said Action 6.								856	0-27
the Government;		•						857	0-35
And further whereas the Central C	Government	has after						858	0~03
considering the said report, decided to	o acquire th	e right of						859	0-02
user in the lands specified in the sche notification;	edule Anpend	led to this						860 862	0-01
								861	0-46 0-32
Now, therefore, in exercise of the subsection (1) of the Section 6 of the								872	0-32
Government hereby declares that the	right of u	ser in the						919	0-02
said lands specified in the schedule app tien hereby acquired for laying the pip		is notifica-						997	0-36
And further in exercise of power co	•	sub-section						968	0-62
(4) of that section, the Central Gov	ernment d	irects that						969	0-10
the right of user in the said lands sl in Central Government vests on this	date of the	publication						970	0-20
of this declaration in the Gas Author	rity of India	Ltd. free						976	0-05
TENAL CHEGINALANCES	•								

										21 2777	<del></del>
1	2 3	4	5	6		लाधन रि	ब्रष्ठाने के	प्रयोगन	के लिए	एतद्द्वारा अ	िंत किया
			977	0-46	-	जाता है	1				
			1055	0-07		और	: श्रामे	उस धार	ো কী	उपधारा (	(4) ৱানা
			1049	0 49		प्रदत्त ।	गक्तियों ः	का प्रयोग	। करते	हुए केन्द्रीय	( सरकार
			1050	0 -11		निर्देश देत	ताहै कि	उक्त भू∄म	भी में उप	योग का अधिक	कर करदेथ
			1051	0-51			में निर्दे	-	ने वेत		सोय गैस
			1146	0 -35				•		गुक्त रूप	
			1145 1144	0 -03 0 -11			निकाइस			_	
			1150	0-35		, ,, ,, ,,	,		(सूची	· · · · · ·	
			1151	0 71			रक चरेकी			- 	<del>**-</del>
			1 154	0 -24		គ្			-	लाइ <b>न प्री</b> जेब	
			1149	0 - 27		जिला	परगना	तहमील	ग्राम	गाटा सं.	लिया
	,		1106	0 01							गया
			1197	0-54							रक्या
			1198	0-31		1	2	3	 4	5	6
			1200 1204	0-02 0-15						-	- -
			1204	0 - 15		इटावा	बिधूना	बिध्ना	लखना	871	0-68
			1206	0-35						870	0 - 22
			1207	0 -07						869	0-58
			1181	0-03						868	0-30
			1182	0-42						867	0-26
			1260/1	0-12						862	0-40
			1260/6	0.03						861	0-34
			520	0 -30						858	0-34
			524	0 04						857	0-08
			531 869	0 - 0 2 0 - 01						1060	0-20
			1260/7							1061	
		FN1.s. A		01 /85—GP]	1					1062	0-71
		[NO, V	J=14010/	01 (05-01)	l						0-01
ক্তি স্থাত	4141य	त. पेटो	निय <b>म ।</b>	भौर खनिब						1063	0-02
पाइपलाइन (		•		का अर्जन)						1047	0-52
	962 (1962			धारा 3 की						1046	0-06
उपधारा (1)	•		•							1138	0 - 22
•	ना का०ग्रा०स नाका०ग्रा०स		· ·							1139	0-24
										1141	0-01
द्वारा केन्द्रीय र										1142	0-10
में वितिर्दिष्ट										1143	0-36
लाइनोंको बिट		, ग्रागन व	हरन का क	(पना भ्राशय						1145	0-10
घोषित कर	प्दया था।									1146	0-05
और यनः	ः सक्षम प्राधि	कारी ने	उन्त र्थाः	धनियम की						1147	0~10
धारा 6 की										1153	0-22
देदी हैं।		,	4 541 5	, ., ., .,						1154	0-32
_		y q <del>o</del> 7	<u>-</u>	<b>(</b>				•		1175	0-75
	ो यतः केन्द्रीय विकास									1194	0-33
विचार करने ः ८-८-४				9.6						1194	
में विश्विद्धिः - ५-५-		पाग <b>क</b> ि १	प्राधकार	श्राात करने							0-45
का विनिष्चय	ाकया है।										0-08
_				5						1199	0-32
	: তৰৰ অঘিটি -					-	•			1200	0-35
(1) द्वारा प्रव										1203	0-05
एतद्द्वारा घोति										1204	0-8.3
में विनिर्दिष्ट	उयतः भूमियो	मं उपयोग	कः ग्रह	कि⊾र पाइप-					-	1205	0-01

1	2	3	4	5	6	Now, therefor sub-section (1) Government here	of Section	n 6 of the	suid Act,	the Central
				1206	0-80	sa'd lands specif	ied in the	e Schedule	appended	to this <b>no</b> ti-
				1288	0-24	fication hereby a	icquired 1	or laying t	the pipeline	i
				1290	0-30	And further i section (4) of the				
				1291	1-04	that the right o	f user in	the said	lands shall	, instead of
				1298	0-01	vesting in Centra cation of this	i Governn Jeclaration	nent, vest o in the (	on this date Gas Author	or the publi- ity of India
				1300	1-40	Limited free from				
				1302	0-42		S	CHEDUI	Œ	
				1304	0-10	Hajira-Baro				Project
				1305	0-60					<del></del> <del>_</del> -
				1307	0-03	Distt Pargana	t Tensii	viitage	Plot No.	Area acqiured
				1308	0-42				<del>-</del>	- — [
				1319	0-02	1 2	3.	4		<u>6</u> 
<b>Y</b>				1326	0-76					*
				1603	0-74	Etawah Bidhu	ma Bidh	una Lucki		0~68
					0-40				870 869	0–22 0–58
				1542					868	0-30
				1543	0~08				867	0-26
				1544	0-42				862	0-40
				1545	0-10				168	0-34
				1562	0-20				858	0-34
				1563	0-40				857	0-08
				1573	0-10				1060	0~20
				1576	0-10				1061 1062	0-7 1 0-01
				1583	0-22				1062	0-01
				1584	0-02				1047	0-52
•				1585	0-56				1046	0-06
				1586 0-	-33 16 <b>3</b> 8				1138	0-22
				1638	0-20				1 139	0-24
				1054	0-05				1141	0-01
				1050	0-30				1142	0-10
				1051	0-70				1143	0~36
				1052	0-05				1145 1146	0-10 0-05
				1052	0-10				1147	01-0
				1156	0-10				1153	0 -22
				1549	0-25				1154	0-32
				1549	0-25					
				1307	0-10				1 155	0-75
			0.14	oreleales	<del></del>				1194	0-33
		Ľα.	<b>U</b> -14	016/02/85	—जी.पी.]				1195 1196	0-45
S.O. 41	141.—W	hereas by	notifica	tion of the	Government				1196	0-08 0-32
of India	in the	Ministry	of Petro	oleum S.O.	555 dated				1200	0-35
leum and	Minera	als Pipeline	es (Acqu	usition of R	of the Petro- light of User				1203	0-05
in Land)	Act, I	962 (50 of	1962),	the Central e right of	Government				1204	0-82
lands spec	cified in	the Scheo	iule appe	ended to the	t notification				1205	10-0
tor the p	om bose	of laying	pipeline	i					1206	0-80
And w	hereas	the Comp	etent A	uthority has	under Sub-				1288	0 -24
to the Go	overnme	ection 6 o ent;	i ine sai	ia Act, sub	mitted report				1290	0-30
And fo	rther u	vherene the	Central	[ Governme	nt has, after				1291 1298	1-04 101
of user in	g the	said repor ands specij	t, decide	d to acqui	ire the right appended to		·—-		1300	1-40

1	2	3	4	5	6			अनु	सूची		
	_			1302	0 42	हा	जिस बरेल	ी जगदीश	ापुर पाइप	लाइन प्रोजे	<b>भ</b> ट
				1304	0-01						
				1305 1307	0-60 0-03	जिला	तहसील	पर्गना	ग्राम	गाटा सं	लिया
				1307	0-03						गया
				1319	0 02						रकवा
				1326	0 –76						
				1603	0-74	1	2	3	4	5	6
				1542	0–40					·	
				1543	0-08	इटावा	विधूना	विधूना	कैथाबा	11	0-30
				1544	0-42	42141	1,12,11	113/11	17.11.41	12	0-08
				1545 1562	0-10 0-20					13	
				1563	0-40						0-29
				1573	0-10					14	0~05
				1576	0 -10					15	0-64
				1583	0 22					179	0-30
				1584	0-02					178	0-30
				1585	0 56					177	0-24
				1586	0-33 1638					175	0-37
				1638 1054	0-20 0-05					174 .	0-30
				1050	0-30					173	0-56
				1050	0-70					187	0-03
				1052	0-05					188	0-10
				1053	0-10					172	0-57
				1156	0–26					159	0-05
				1549	0-25					158	0-60
				1587	0 10					157	0-37
			[No. (	<b>)</b> -14016	/02 /85-G.P.]					170	0-30
		• • •	_	,	,					166	
					न्नाइन (भूमि में 					165	0-25
		,		•	962 का 50)						0-27
		• •			र के पेट्रोलियम 9-2-85 द्वारा					164	0-13
					त्र-४.७.५ प्राप्त विनिद्दिष्ट भूमियों					167	0-01
					के लिए अजिन					168	0-20
		घोषित कर			•					162	0-21
		C - 2 - 2		-0	2					172	0-31
					ाघारा 6्रकी					173	0-02
उपधारा (	া) ক স্বয়ান	'सरकार को	(१५१८ द	वाह्।						298	0-31
धीर व	<mark>धागे,</mark> यतः केन	द्रीय सरकार ने	ने उक्त वि	रंपोर्ट पर	विचार करने के					281	0-18
पक्षात् इस	<mark>भ्रधिसूचना</mark> से	ो संलग्न अनु	;सूची में	विनिद्दिष्टः	भूमियों में उपयोग				,	282	0-06
का मधिका	र अजिंत कर	ने का विनिध	चिय किया	ा <b>है</b> ।	1		·			283	0-02
भ्रम,	भ्रतः उक्त म	धिनियम की	भारा 6	की उपधा	रा (1) द्वारा					287	0-43
					घोषित करती					272	0-22
है कि इस	ग्रधिसूचना मे	र्गे संक्षरन <b>भ</b> नुस्	(ची में वि	वेनि <b>दि</b> ष्ट ः	उक्त भूमियों में					273/1	0-44
			छाने के	प्रयोजन के	लिए एसदृहारा					293	0-19
भजिल किय	या जाना है ।	ł	•							1114	0-14
और र	प्राने उस धार	राकी उपधा	रा (4)	क्षारा प्रद	त्त मक्तियों का					1112	0-14
	_				मयों में इपयार						
			-		य भारतीय गेंस					1113	0-34
		-	भाकतामं	, घोषणा के	ठप्रका <i>गन</i> की					1126	() 0 4
इस तारीख	'का मिहितः	हाभा ।								1128	0-2.2

1	<b>2</b> 	3:	4 5	6	And whereas the Competent Authority has under S Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted rest to the Government;
			1129	0 - 25	A = 1 Suether where Abs Control Consequent box of
			1130	0-16	And further, whereas, the Central Government has, all considering the said report, decided to acquire the right
			1136	0 - 27	user in the lands specified in the schedule appended to t notification;
			1135	0-09	
			1061	0 - 0.2	Now therefore, in exercise of the power conferred sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Cent
			1051	0 - 23	Government hereby declares that the right of user in t
			1062	0 - 0.7	said lands specified in the schedule appended to this notifi- tion hereby acquired for laying the pipeline;
			1063	0-18	
			1056	0-36	And further, in exercise of power conferred by sub-stien (4) of that section, the Central Government directs t
			1057	0-12	the right of user in the said lands shall instead of vesting
			1050	0-02	Central Government vests on this date of the publication this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free fr
			1049	0-15	encumbrances.
			1001	0-68	SCHEDULE
			1002	0-05	SCHEDOLE
			1017	0-16	Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.
			1018	0-03	
			1015	0-08	Distt Tehsil Pargana Village Plot no. Area
			1016	0-06	Aquire
			1013	0-02	1 2 3 4 5 6
			1014	0-86	
			985	0-01	Etawah Bidhuna Bidhuna Kai- 11 0 30
			984	0-02	thawa 12 0-08 13 0-29
			987	0-21	14 0 0 5
		•	986	0-23	15 0-,64
			970	0-15	179 0–30
				0-15	178 0-30
			10		177 0-24
•			1277	0-15	175 0-37
			1305	0-25	174 0-30 173 0-56
			1307	0-06	187 0-03
			1308	0-03	188 0-10
			1306/1444	0-06	172 0–57
			1306	0-35	159 0-05
			1321	0-41	158 0-60
			1322	0-12	157 0-37 170 0-30
			1323	0-08	170 0-30 166 0-25
			1314	009	165 0.27
			1320	0-78	164 0-13
•			1330	0 - 35	. 167 0-01
			1331	0-15	168 0-20
			1334	0-88	162 0-21
					172 0-31 173 0-02
		[सं .	O-14016/03/85-5	ती.पी.]	298 0-31
		_		_	281 0 18
i.O. 41	42Whe	reas by 1	notification of the Go	vernment O. 556	282 0-06
ed 9th	February	7, 198 <b>5</b> ur	y of Petroleum S. der sub-section (I) of t	Section 3	283 0 02
the Pe	troleum :	and Mine	rals Pipelines (Acquisi 1962 (50 of 1962), the	tion of	287 0-43
vernmer	nt declare	ed its into	ention to acquire the	right of	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
r in the	e lands sj	pecified in	the schedule appended	d to that	273/I 0-44

1	2	3	4	5	6					तियम की ध	गय 6 की
				293	0-19	उपश्चारा (	1) ক মণ	ान संस्कार	को निर्पोर्ट	दंदी है।	
				1114	0 - 14	भौर :	प्रागे बतः क	र्ज्वाय सरका	र ने उभव	रिपोर्ट पर वि	भ्यार करने के
				1112	0 51						यां में उपयोग
				1113	0-34		का ग्रधिकार भर्जित करने का विनिश्चय किया है।				
				1126	0-04					,	
				1128	0 -22						ा (1) <b>द्वा</b> रा
				1129	0 25						षित करती है
				1130	0-16		•••				ल भूमियों में
				1136	0-27				बिछाने के	प्रयोजन लि	ए एतद्शास
				1135	0- 09	श्रजित कि	शा जाता है	ł			
				1061	0 02			<del>-</del> -	174 <del></del>		
				1051	0-23						गमित्यों का
				1062	0-07						थों में उप <b>रो</b> ग 
				1063	0 18						प भान्सीयगैस घोषणा के
				1056	0 -36					का रूप म	घाषणा क
				1057	0-12	সকালণ প	ગ મૂબ લાદા	स्त्र को निहि	าหูเนเ		
				1050	0 -02			3	<b>ान्</b> मृची		
				1049	015				_		<b>.</b>
				1001	0-68	7	र्गाजरा-त्ररं	ली-जगदींग	पुर पाइप	लाईन प्रो	जेक्ट
				1002	0 05						
				1017	0-16	जि <i>ल</i> ा	तहमील	पर्गना	ग्राम र	गटा संख्या	लिया गया
				1018	0-03						रकवी
				1015	0-08						. (, ()
				1016	0 -06						
				1013	0-02	1	2	3	4	5	6
				1014	0-86						
				984	0-01	इटावा	बिधूना	बिधृना	रायपुर	69	0 → 1 2
				985 987	0-02				कैथाना	34	0-15
				986	0-21 0-03					38	0-01
				970	0-05 0-15					37	0-11
				10	0 -05						
				1277	0 -05					27	0-02
				1305	0-15					41	0-01
				1303	0-25					42	0-28
				1308	0.03					43	0-02
				1306/	0 06					4.4	0-15
				1444	0 00						0-11
				1306	0-35					45	
				1321	0-41					46	0-08
				1322	0-12					47	0-10
				1323	0-08	4				51	0-30
				1314	0-09					52	0-30
				1320	0-78					53	0 - 42
				1330	0-35					5.4	0-02
				1331	0-15					49	0-11
										*F 47	()— I I
				1334	0-88	•				50	0-01

[No. O-14016/03/85-G.P.]

का. प्रा. प्रायत — यतः पेट्रांलियम ग्रीर खिनंज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के श्रक्षिकार का श्रजेंन) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की भ्रारा 3 की उपधारा (1) के श्रधीन भारत सरकार के पेट्रांलियम मंत्रालय की श्रिधिसूचना का. श्रा. म. 557 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्राय सरकार ने उस श्रिभूचना से संलग्न श्रनुसूची में शिनिहिंग्ट भूमियों के उपयोग के श्रिधकार की पाइप लाइनों को श्रिष्ठानि के लिए श्रिजिन करने का श्रथना श्राम्य श्रीपन कर दिया था।

# [मं॰ ओ-14016/04/85-जी पी]

S.O. 4143.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 557 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conterred by sub-section (1) of Section 6 of the suid Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India I td. free from encumbrances.

**SCHEDULE** 

F	Iajira Bar	eilly Jago	lishpur	Pipe	Line Project
Distt.	Tehsil	Par- gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawal	h Bidhuna	Bidhuna	Raipur	69	0–12
			Kaith-	34	0-15
			wa	38	0 -0 1
				37	0-11
				27	0-02
				41	0-01
				42	0-28
				43	0-02
				44	0-15
				45	0-11
				46	0-08
				47	0-10
				51	0-30
				52	0 - 30
				53	0-42
			•	54	0-01

[No. **O**-14016/04/85-G.P.]

0-110-01

49

50

मा. आ. 4144: — यतः पेट्रोलियम और खिनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिमूचना का. आ. मं. 558 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछान के लिये अजित करने का अपना आश्रय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि- दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अभित करने का विनिम्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिमूचना में संलग्न अनुसूची में विनिद्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोगन के लिये एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस नारीख को निहित होगा।

अनुसूची हाजिरा--बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैंग्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	- बिधूना	गुलरिहा	100	1-22
				101	0-04
				102	0-83
				104	0-11
				111m	1 5 8
_				112	0-16
				113	0-05
				115	0-11
				116	0-41
				1 2 3 m	0-08
				146	0-29
				149	0-25
				150	0-61
				152m	0-63
				156m	0-20
				176	0-02
				177	0-12
				180	0-14
				181	0-03
				182	0-20
				183	0-57
				184	0-35
				187	0-02
				188	0-02
				193	0-28
	,	_		202	0-89

					<del></del>						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				203	0-70			·		181	0-03
					- ·					182	0-20
				204	0-01					183	0-57
				230	0-06				,	184	0-35
				235	0-01					187	0-02
				237	0-02					188	0-02
				238	0-67					193	0-28
				199	0-02					202	0-89
										203	0-70
		ſ₹	नं० ओ∗।	4016/05/	85-जीपी				1	204	0-01
1.		L		1019109	,, ,,1					230	0-06
S.O. 414	4.—Wher	reas by m	otification	n of the Go	vernment of				-	235	0-01
lia in th	ie Minis	try of P	etroleum	S.O. 558 d	iated 9-2-85					237	0-02
					oleum and er in Land)					238	067
					ent declared					199	0-02

[No. O-14016/05/85-GP]

its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this not)fication;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE Hajira -Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par- gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	. 5	6
Etawa	h Bidhun	ia Bidhur	na Gula-	100	1–22
			riha	101	0-04
				102	0-83
				104	0~11
				111m.	1-58
				112	0-16
				113	0-05
				115	0 - 11
				116	0-41
				123m.	0-08
				146	0~29
				149	0-25
				150	0-61
				152m.	0-63
				156m.	0-20
				176	002
				177	0~12
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	180	0-14

क:० आ० 4145.-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) के मधीन मंत्रालय, पेट्रोलियम विभागकी अधिसूचना भारतसरकार के र्स० 559 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों की विछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था। और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा

6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है। और, आगे यतः केन्द्रोय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का बिनिश्चय ਜ਼ਿਰਾ है।

उन्ब, अतः उन्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दे देतो है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बनाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख निहित होगा।

अनुसूची हाजिरा-बरेली-जंगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

 जिला	तहसील तहसील	परगना	ग्राम	 गाटा	संख्या	लिया गया रकवा
1	2	3		4	_ 5	6
इटावा	 बिध्नना	बिधू न	ा ब	iध _म ऊ	5 2	0-77
			[₹	ां० ओ-	1401	3/06/85-जी पी]

S.O. 4145 - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 559 dated 9-2-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Ministry Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this not fication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for faying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

## Hajira-Bareilly Jag dishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par- gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawal	 1 Bidhur	na Bidhu	ma Band	h 52	0-77
			Mau		
					_

# [No. **Q**-14016/06/85-GP]

का. आ. 4146. —यतः पेट्रोलियम भीर खनिज पाइप लाइन (भूभि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम. 1962 (1962 का 50) के धारा, 3 के उपधारा (1) के अजन आरत सरकार के पेट्रोतिय मंत्रालय की अधिसूचना का आ. मं. 560 तार ख 4-2-85 द्वारा केंन्य सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में बिनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों हो बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

भीर यतः सक्षम प्राधिकारः ने उक्त श्रक्षिनियम को धारा 6 की उप-धारा (1) के श्रश्न सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

श्रीर श्रापे यतः केन्द्रंय सरकार ने उक्त स्पिटि पर विचार करने के पण्चात् इस अधिमुक्तना से संतरत श्रापुत्रः में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का श्रीधकार भ्रतित करने का विनिश्चय किया है ।

श्रम, श्रतः उक्त श्रश्चिनियम कं. श्रारा ८ के उपयोग (1) द्वारा श्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिमृष्का में संजयन प्रतमूत में विविद्धित उक्त भूमियों से उपयोग का श्रिथिकार पाइप लाइन विद्यान के श्रमीकार के लिए एतद्द्वारा श्रीत किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिन्त्यों का प्रयोग फरते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देण देती है कि उस्त भिन्यों में उपदोग को अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राविकारण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त सप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अन्मूची

हःजिरा—बरेली-जगदीगप्र पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	- तह्सील	पर्गना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया
					रकवा .
1	2	3	4	5	6
- — इटावा	- बिधृ <b>ना</b>	- बिध्ना	असेर्न	1 958	0-01
				957	0-29
				656	0-50
				951	0-16
				947	0-11
				946	0-03
				945	0-04
				944	0-04
				943	0-08
				942	0-08
				940	0-02
				939	0-01
				934	0-12
				930	0-45
				929	0-02
		•		928	0-23
				927	0-01
				926	0-42
				925	0-05
				924	0-02
				923	0-42
				909	0-07
				897	0-33
				896	0-01
				895	0-02
				894	0-42
				893	0-32
				862	0-02
				848	0-60
				846	0-32
				843	0-02
				841	0-02

[सं० आ-14016/07/85-जी पी]

S.O. 4146.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 560 dated 9th February, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government; And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the nipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jag dishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par- g ana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Asai	958	0-01
				957	0 - 29
				656	0~50
			•	951	0-16
			9	47	0-11
			9	946	003
			!	945	0-04
			9	944	0-04
			9	)43	80–08
				942	0-08
				940	0-,02
				939	0-01
				934	0-12
				930	0–45
				929	0-02
				928	0-23
				27	0-01
				926	0–42
				925	0-05
				24	0-02
				923	0-42
				909	0-67
				897	033
				896	10~0
				895	0-02 .
				894	0-42
	•			893	0-32
				862	0~02
				848	1)-60
				346	0-32
				843	0-02
		•		841	0-02

[No. **Q-**14016/07/85-GP]

का आ, 3149:---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भृमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधि- निवम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का, आ, सं. 583 तारीख 23-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उप अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए, अर्जित करने का अपना आणय बोषित कर दिया धा।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उन्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

ओर आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिद्धित्व भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिध्चय किया है।

अव, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिन्त का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार रनहुतारा घोषित करते है कि इस अधिमूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप नाइन विछाने के प्रयोगन के लिए ए।दुद्वारा अजिन किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्मेंग दैती हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हीने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाणन की इस नारीख को निहित होगा।

अनुसूचा हातिया -बरेलो-- तगदीगयुर ााद्य लाहर प्रोजेक्ट

- किता	 तहसील प	(२ग <b>ा</b>	गांत्र साटा	 मंख्या लिसार	 ाजा र उदा
1	2	3	4	5	6
फरुखीब	नद छित्रन	લાવ	क्षा-व	1666/1	1 -25
	मऊ	ग्राभ	ग्राम	1666/6	0-82
				1671/1	0 -0 f
		•		1672	0 - 36
		,		1673	0 -11
				1674	0 - 19
	,			1675	$0 = \{0\}$
	,			1681	1 - 30
				1682	0-03
				1683	0 .25
				1684	0 - 72
				1995	0 - 38
				1997	0 -12
				1998	0.49

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				2002	0-03			·		2685	0-5
				2008	0-32					2686	0~0
				2021	0-01		•			2687	0~0
				2022	0-07					2692	0-0
				2023	0 - 23					2895	0-0
				2024	0 - 2 7					2906	0 -03
				2033	0-22					2908	0-3
				2034	0-13					2909	0 -1
				2027	0-02					2911	0 -1
				2935	0-17				-	2913	0 - 3
				2036	0-06					2914	0-1
				2037	0 - 0.4					2915	0 - 2
				2038	0-03					2918	0~5
				2039	0 - 0.2					2907	0 -4
				2043	0 - 37					3043	0 - 6
				2044	0-01					3044	0 · 0
				2045	0-01					3045	0-1
				2046	0-28					3046	0-1
				2093	0-03					3729	0-6
				2096	0-06					3731	0 - 6
				2097	0-09					3732	0-0
				2098	0-22					3759	3-4
				2099	0-67					3763	0-2
				2100	0 - 0 3					3766	0-3
				2107	0 - 1 4					3767	0 ~ 4
				2425	0-12	,	-			3768	0 → 1
				2106	0-03					3769	0~0
				2449	0-71					3789	0 -0
				2450	0-96					3806	1 ~ 2
				2451	0-06					3807	0-9
				2447	0-11					3811	0 - 3
				2636	0-02					3812	() <b>→</b> 4
				2638	0-18					3813	0 - 2
				2639	0-22					3815	0 ~ 5
				2650	0-80					3816	0-0
				2674	0-07					3817	0-8
				2676/2	0-25					3818	$0 \cdot 1$
				2676/1	0-12					3819	0 - 4
				2677	0-19					3093	0 - 5
				2678	0-36					3730	0 - 3
				2679	0 - 03						
				2680	0-01				[सं०अ)	-14016/32/	85-जीपी
				2681	0-01		44.45	٠٠٠ - مـــــــــــــــــــــــــــــــــ	mat164	ion of the	Governme
				2683	0-69	S.O. 4 of India		nereas by Ministr	nouncat v of Peti	ion of the roleum S.O.	583 da
				2681	0-24	32 1 3			,	n (I) of Secti	

			<del></del> -		<u></u>			 			
ral Gover	rnment er in th	declared ne lands s	l its intent pecified in	ion to the sched	), the Cent- acquire the ule appended	•	1	 	3 4 Talgram	2046 ⁵	<u>6</u>
to that no	ouncanc	он тог ро	npose of	iaying pi	penne;				_	2093	0-03
					under Sub-					2096	0-06
to the Gov			I me said	Act, sum	mitted report					2097	0-09
		•								2098	0-22
					nt has, after the right of					2099	0-67
					ended to this					2100	0-03
notification		•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						2107	0-0.7
Now, the	erefore.	in exerci	ise of the	nuWer e	onferred by					2425	0-14
sub-section	(1) of	the Section	on 6 of the	said Act	, the Central						
					user in the					2106	003
tion hereby					this notifica-					2449	0-71
	_									2450	0–96
					v sub-section rects that the					2451	0-06
right of u	iser in	the said	lands shau	instead	of vesting in					2447	0-11
of this dec	overnme Jaration	ont vests (	on this on Bas Author	te or th	e publication dia Ltd. fres				,	2636	0-02
from all en			Juli Timilor	ity OI III	-iu Ltd. 1700					2638	0-18
										2639	0-22
		SCHED							2	2650	0-80
Haj	ji <b>ra-B</b> a	reilly-Jag	dishpur P	ipe Line	Project					2674	0-07
Distt, 7	rehsil	Par-	Village	Plot	Area					2676/2	0-25
21012,	/	gana		No.	Acquired					2676/1	0-12
- ·	•	•	,							2677	0-19
_ <u> </u>	2	3	4	_ 5	6					2678	0-36
Faru- C	Chhibra	a Tal-	Tal-	1666/1	1–25					2679	0-03
khabad I	Mau	gram	gram	1666/6	0~82	•				2680	0-01
				1671/I	004					2681	0–01
		•		1672	0-36					2683	0–69
				1673	0-11					2681	0-24
				1674	0-19					2685	0–57
				1675	0-10					2686	0-01
				1681	1 - 30					2687	0.01
				1682	0-03					2692	0-03
				1683	0-25					2895	0-06
				1684	0-72					2906	0–03
				1995	0-38					2908	0-32
				1997	0-12					2909	0-10
				1 <b>99</b> 8	0-49					2911	0-12
				2002	0-03					2913	0-31
				2008	0-32					2914	0-15
				2021	0-01					2915	0-28
				2022	0-07					2918	0-53
				2023	0-23					2907	0–46
				2024	0-27					3043	0-60
				2033	0-22					3044	0-02
				2034	0-13					3045	1-10
				2027	0-02					3046	0-13
				2035	<b>0-</b> 17					3729	0–65
				2036	0-06					3731	0-63
				2037	0-04					3732	0-08
				2038	0-03					3759	3-42
				2039	0-02					3763	0-20
				2043	0~37					3766	0-39
				2044	0-01					3767	0-45
				2045	0-01					3768	0-12

1	2	3	4		5 6	New Delhi, the
		-	— _{Tal}	3769	0-06	S.O. 4148.—Whereas by
			gram	3780	0 0 5	of India in the Ministry dated 30-5-1985 under sub
			(Contd.)	3806	1-24	the Petroleum and Minerals I
			,	3807	0-93	User in Land) Act, 1962 (5 ment declared its intention in
				3811	1-39	the lands specified in the sch
				3812	0~45	tion for guspose of laying pig
				3813	0-24	And whereas the Compet Section (1) of Section 6 of
				3815	0-53	to the Government;
				3816	0-01	And further whereas the
				3817	0-80	c nsidering the said report,
				3818	0–15	user in the lands specified in notification;
				3819	0-45	·
				3093	J-50	Now, therefore, in exerci- sub-section (1) of the Section
				3730	0-33	Government hereby declares  said lands specified in the sel  tion hereby acquired for lavir

[No. **O**-14016/32/85-GP]

नई दिण्यो 29 अधस्त 1985

का भा. 4148.—यतः पंद्रोलियम भार खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रीलियम मंत्रालय की अधिसूजना का. भा. सं. 2582 तारीखा 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूजना मे संलग्न अनुसूजी में विनिर्धिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को विद्यान के लिए अर्जित करने का अपना आश्य योषित कर दिया था।

श्रौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के श्रधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है।

भीर भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पक्ष्वात् इस प्रक्षित्वना से संलग्न भनुसूची में विनिर्दिण्ट भूमियों में उपयोग का भविकार श्रीकृत करने का विनिश्चय किया है।

भ्रम, भ्रतः उनतं ग्रिथिनियमं की धारा 6 की उपधारा (1) हारा भ्रवस्त मिन्न का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्शारा घोषित करती है कि इस मधिसूचना में संख्यान भ्रतुसूची में विनिदिष्ट उनतं भूमियों में उपयोग का मधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्शारा अजित किया जाता है।

भीर भागे उस धारा की उपधारा (4) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार में निहिन होने के भजाय भारतीय गैरा प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस नारीख की निहिन होगा।

धनुसूत्रः स्राजिरा-वरेलं -जगदंशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

(जला	तहमी'ल	पर्गना,	ग्राम	गाटा मं०	ग्रजिल रकवा व.० वि० वि.
— 1	2	3	4	5	6
हरदाई	भाहात्राद	पछोहा	 नगल-	2	0-07-00
•	•	•	हुसन	3	0-01-00
			•	5	0-00-12
				7	0 − 1 0 <b>−</b> 0 5
				8	0-05-08
				5)	0-19-05
			_	10	v − 1 v <del>−</del> 0 4
			-	13	0-10-04

्रितंय **O** -14016/363/85-जी पी]

## New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4148.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2582 dated 30-5-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after c nsidering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to the notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of their in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project.

Distt.	Tehail	Pirgini	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hırdoi	Shuhubad	Pachhoha	Nagla Hussain	2 3 5 7 8 9	B. V. V 0-07-00 0-01-00 0-00-12 0-10-05 0-05-08 0-19-04 0-10-04

[No. O-14016/363/85-GP]

का. आ. 41.19:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंद्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1791 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आगय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने हे पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया हैं। अब, अत: उक्त तियम की धारा 6 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त णितत का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपध्रारा (4) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा !

यनुभ्ष

हाकिया-बरेल -जगद शपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेथट

जिला नहस ल परभना ग्राम गाटा स० श्राजत रक्षा
हेक्टर में

1 2 3 4 5 6

हरदोई विलग्राम कटियार नदृषापुर
नरीया 28 0630

1	2 3	4	5	6
हरदोई	 विलग्राम कटिया	- र नद्रवापुः	 T	
•		नगया	28	0630
			29	0630
			3.0	0250
			3.1	0400
			: 2	0150
			896/189	0250
-			7.5	0450
			77	1000
			78	0075
			8.1	1300
			8.2	1800
			83	0850
			86	1250
			132	0480
			133	072 <b>0</b>
			134	2700
			135	0400
			138	0500
			139	0500
			140	0900
			142	0600
			1 43	0420
			153	1900
			179	0380
			180	0130
			182	0630
			183	0780
			184	1900
			186	0630
			187	0840
			195	1250
			196	0380
			197	1800

l 	3	. 3	-1	5	6
नदुवागुर	नरीया (जा	र्रे ( )	, , , , , ,	201	1340
				363	0100
				375	1500
				403	0450
				407	0380
				414	0800
				415	0500
				416	0600
				418	0650
				420	0105
				12 l	0780
				4 12	0750
-				423	0720
				4 2 4	0100
				125	0780
				433	0600
				434	1860
				435	0300
				439	2730
				440	1370
			1	445	0590
				446	0700
				417	4810
				448	0050
				188	0050
				154	0025

[मं॰ **O** -14016/237/85-जीपी]

S.O. 4149.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1791 dated 16-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE
HBI Gas Pineline Project

	SCHEDULE HBJ Gas Pipeline Project							
Distt.	Teh iil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired			
					Hactre			
1	2	=	4		6			
Hardoi	Bilgram	Katyari	Naduapu Narotha	i! 28 29	0630 0630			
			Maioma	30	0250			
				31	0400			
				32	0150			
			,	070.107	0250			
				<b>7</b> 5 77	0450 1000			
				78	0075			
				81	1300			
				82	1800			
				83	0850			
				86 132	1250 0480			
				133	0720			
				134	2700			
				135	0400			
				138	0500			
				139	0500			
				140 142	0900 0600			
				143	0420			
				153	1900			
				179	0380			
	•			180	0130			
				182	0630			
				183 184	0780 1900			
				186	0630			
				187	0840			
				195	1250			
				196	0380			
				197 201	1800 1340			
				363	0100			
		1		375	1500			
				405	0450			
				407	0380			
				414	0800			
				415 416	0500 0600			
				418	0630			
				420	0105			
		,		421	0780			
				422	0750			
				423 424	0720			
				425	0100 0780			
				433	0600			
				434	1860			
				435	0300			
				439	2730			
				440 445	1370 0590			
				446	0700			
				447	4810			
				448	0050			
				188	0050			
				154	0025			
			[No.	O-14016	5/237/8 <b>5-</b> GPJ			

का. आ. 4150 .—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइम (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. मं. 1792 तारीख 16-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अगित करने का अपना आगय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय संस्कार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि-दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिष्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिद्धिट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोगन के लिए एतद्द्वारा आजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मितियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

श्रनुसूचः हाजिरा–बरेलं -जगर्द गपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेस्ट

जिला	नहस न	प्रगना व	ग्राम ग	ाटा सं	श्रजित <b>य</b> वि	
1 .	2	3	4	5	6	
हरडोई	- विलग्राम	भ करियारः -	जम्हरौल 	3 1		5 <b>-</b> 3
				27	1	5
				3.8	1	6
				3.9	_	6 -
				501	_	6 [
	1			3.9	1	4
				45	_	2
				91	1	7 -
				93	2	2 -
				8.0	-	8
				81	_	1 4
				170	~	9 [
				171	_	_
				172/1	_	1 1
				4.72/2	_	-1 1
				173	_	5 1
				177/1	-	4
				$177_{I}$ 2	_	5 1
				228	_	7

1	2	3	4	5		6
			अम्हरौल	229	-	18 1
				226	-	1 10
				227/1	1	- 1
				225	-	3 1
				227/2		5 -
				346	_	2 10
				347	-	6 -
				350		- 15
				544	-	11 10
				549		15 -
				390		2 9
				551	_	4 -
				552	1	
				555	-	10 15
				545	1	1 -
				538	1	7 5
				522	-	2 5
				521	-	12 10
				539	-	13 +
				520	-	1 16
				500	1	1 10
				199	_	6 5
				556/1	-	-: 3
				348	-	4 7
				556/2	_	- 5

[सं. **O**-14016/238/85~र्ज प]

S.O. 4150.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1792 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands spec fied in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

698 GI/85-6

	S	CHEDUL	Æ
нвј	$G_{i,i}s$	Pipeline	Project

	h	IBJ G.18	Pipeline	Project	t		
Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	- <del>2. v</del>	Arca Acquired	· ·
					В	v	
l	2	3	4	5		6	
Hardoi	Bilgram	K. tyani	Bramh			5	5
			rauli	37	1	5	5
				38	1	6	5
				39	_	6	
				501 39	_	6 14	10 7
				95		2	
				91	1	7	_
				93	2	ż	
				80		8	2
				81		14	5
				170 -	_	.9	12
				171	_		5
				171/1	_	4	10
				17°/2	_	4	10
				173	_	5	10
				177/1 177/2	_	4 15	10
				228	_	7	10
				229		18	10
				226		1	10
				227/1	1		10
				225		3	10
				227/2		5	
				346	_	2	10
				347	_	6	
				350	_		15
				544		11	10
				549 390		15	5
				551		4	_
				557	1		_
				555	_	10	15
				545	1	1	
				538	1	7	5
				522	_	2	5
				5^1		1?	10
				539	-	13	_
				5°0	<del>-</del>	1	16
				500	1	1	10
				499 **6#	_	6	6 3
				556/1 348	_	4	7
				146 556/י	_		5
						/238/85-C	_

[No. O-14016/~38/85-GP]

का. आ. 4151—यतः पेट्रोलियम और खिल्लि पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपघारा (1) के अर्धन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1795 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर वियाधा।

और यतः सक्षंम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दें दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोगका अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची हाजिरा – बरेली≔ जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहर्सःस	परगन	ी ग्राम	गाटा सं.	र्आर्जितरकवा वी. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
—- हरवोई	श हाबाब	पार्ली	चकरेंसी	207/2	3-8-0
			कला	209/4/2	04
				209/6	0-15-0
				209/7	1-4-0
				209/8	0~4-4
				210/10	0-15-0
				210/11	3-15-0
				211/6	1-7-10
				211/7	3-9-0
				214/2	3 1 0
				214/3,4	1-10-0
				215	0-5-0

[सं. O→ 14016/241/85- जो पी]

S.O. 4151.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1795 dt. 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to arquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Governmen, directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE H.B.J. Gas Pipe line project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area B.V.V.
1	2	3	4	3	6
Hardoi	Saliabad	Pali	Chakoti- Kalan	207/2 209/4/2 209/6 290/7 209/8 210/10 210/11 211/6 211/7 214/2 214/3, 4 215	3-8-0 0-4-6 0-15-0 1-4-0 0-4-4 0-15-0 3-15-0 1-7-10 3-9-0 3-4-0 1-10-0 0-5-0

[No. O-14016/241/85-GP]

का आ. 4155.— यतः पेट्रोलियम और खितिक पाइपलाइन (मृपि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत गरकार के पेट्रोलियम मंत्रानय की अधिपृत्रना का. आ. सं० 1756 तारीख 16-4-85 हारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को खिछाने के लिए अजिन करने का अपना आण्य घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उ≉ा अधिनियम की धारा 6की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है।

और आगे यन केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परिवार करने के पण्यान् इस अधिप्ता से संतरा अनुष्त्री में विधिद्धिः भूति में उत्योग का अधिकार अजिन करने का विनिग्नय किया है।

अब, अतः जन्न अधिनियम की धारा 6 की जनगरा (1) हारा प्रवक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा घोषित करती है कि इस अधिमूचना में संलग्न अनुमूचो में विनिर्दिष्ट जन्त भूमियों में जनमीन का अधिमूचना पाइपलाइन बिछाने के प्रयोगन के लिए एतद्दारा अतिल किया जाना है।

और आगे उस धारा भी उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त गिलिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती हैं कि उन्त मृमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित्त होते के बकाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाबाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाणन की इस तारीख को निहित्त होगा।

अनुभूची एच, बी, जे, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जि <b>ला</b>	तहर्म/स	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रक्षत्रा
1	2	3	4	5	त्रि.वि वि
हरदोई -	णा <b>ह्या</b> द	पार्ला	वेहरीं	39	0-7-14
		_		40	0-7-10

 2	3	4	5	6	
 			41	0-2-2	
			42	0-2-10	
			44	0-4-5	
			45	0-6-0	
			47	0-3-15	
			51	0-2-10	
			52	0-4-0	
			53	0-7-18	
			5.4	0-3-12	
			-179	0-12-0	
			480	0-5-0	
			489	0-16-4	
			490	0-0-10	
			491	0-10-0	
			493	0-1-4	
			494	1-0-8	
			495	0-0-10	
			496	0-12-10	
			40/636	0 <b>-7-</b> 0	
			•		

[सं. O-14016/242/85-र्जा पी]

S.O. 4152.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1756 dated 16-4-85 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the light of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conterted by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
	<del></del>				B. V. N.
Hardoi	Shahabad	Pali	Behti	39	0→7–14
				40	0-7-10
				41	0-2-2
				42	0-2-10
				44	0-4-5
				45	0-6-0
				47	0-3-15

4 5 6 51 0-2-10 52 0-4-0 53 0 - 7 - 1854 0 - 3 - 12479 0-12-0 480 0-5-0 489 0-16-4 490 0 - 0 - 10491 0-10-0 493 0-1-4 494 1-0-8 495 0-0-10 496 0 - 1 - 1040/636 0-7-0

[No. O-14016/24° /85-GP]

का. भा. 4153.— यतः पेट्रोलियम भौर खितिक पाइन्ताइन (भूमि में उपयोग के मधिकार का घर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 का उपधारा (1) के अध.न भारत सरकार के पेट्रोलियम मंजालय का अधिसूचना का. आ. सं. 1758 तार ख 16-4-85 द्वारा केन्द्र य सरकार ने उस प्रिधसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिधिक्ट भूमियों के उपयोग के प्रधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए घर्जित करने का अपना धाश्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारः ने उक्त ग्रिधिनियम क. धारा 6 को उप धारा (1) के ग्राधःन सरकार को रिपोर्ट वे वा है।

भीर भागे यतः केन्द्रय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूचः में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अधित करने का विनिष्चय किया है।

श्रय, अतः जन्त श्रधिनियम को घारा 6 का जनवारा (1) ब्रारा प्रवत्त गानित का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतदब्रारा घोषित करती है कि इस श्रधिस्वता में संलग्न अनुसूच। में विनिधिष्ट जन्त भूमियों वं जपयोग का अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन लिए एतद्द्रारा अजित किया जाता है।

भीर धारो उस धारा क, उपधारा (4) द्वारा प्रश्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र,य सरकार निर्देश देत. है कि उक्त भूमियां का उपयोग का प्रधिकार केन्द्र,य सरकार में निहित होने के बजाय भारताय गैस प्रधिकरण लि. में सभा बाधाओं से मुक्त कप में थोयणा के प्रकाशन का इस तार,ख को निहित होगा।

अनुसूची हाजिरा– बरेली– जगदीशपुर गैस-पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अजित रक्तवा वीं, वि.वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	विश्वप्राम	करियारी	वहेटार	————— [ा] म	
			पुरा	17	0-4-0
				18	1-7-12

S.O. 4153.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1758 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to the notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conterred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	T_hsil	Pargana	Village	Plot	Area in	
				1404	в. у. у.	
1	2	3	4	5	6	
H rčel	Bilgram	Katiyari	Dehtaram Pura	17 18	0-4 -0 1-7-12	
			įNe. O	14616	/244/85-GP]	

का. आ. 4154.— यसः पेट्रोलियम और खनिज पाइव लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1759 तारीख 16-4-85 द्वारा बेन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में घिनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अजित करने का अपना आगय घोषिस कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देदी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिष्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदेश्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भोषित करते है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बौधाओं से मुक्त रूप में धोषणा के प्रकागन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची हाजिपा- बरेली- जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अजित रकवा हक्टर
1	2	3	4	5	6
हरवार्ष	विलग्राम	कटियारी	चाऊपुर	16	-0670
		, ,	a	17	-0250
				21	-3000
				23	-0200
				24	-0450
				25	-1300
				26	-1000
				1024/26	-0150
				54	-0630
				5 5	-3600
				56	-0550
				57	-1400
				65	-0650
				66	-1650
				106	~1350
				107	-1125
				108	-0900
				109	-1350
•			-	150	-05 _A 5
				727	-1650
				464	-0200
				665	-0100
•				725	-1300
				724	-1024
				722	-1050
				717	-0700
				719	-0300
				720	-3000
				680	-0100
				681	-0250
				682	-0100
				683	-0600
				684	-0100
				689	-1010 -0750
				690	-0750 -0350
				692 694	-1100
				695	-1100 2400
			,	696	-0700

from all encumbrances.

-	2	3	4	5	6			SCHE	DULE		
			चाऊंपुर	699	-2500		HB	II. Gas Pi	pe line Pro	oj⊵e t	
				700	-0200	·				_ <del>_</del>	
				701	- 0050	Distt.	Tensil	Pargana	Village	Plot No.	Area requirec
				871	- 0200 - 0750						in Hector
				876	- 1150						
,	,			877	-1300	1	2	3	4	5	, O
				879	-0050	Hardoi	Bilgarm	Vatura	Channur	 j 6	0670
				880	-2600	пасо	ongarm	Katyan	Chanpur	17	0250
				881	-0500					21	-3000
				870	-5000					23	0200
				871	<b>₩</b> 0550					24 25	0450 1300
				885	-1100					26	1006
				886	-1200					1024/26	- 0150
				887	-0900					54	- 0630
				890	-1200					55 56	3600 0550
				910	- 1700				•	57	1400
				911	-2300					65	0650
				913	-0075					οb	-1650
				907	0.050					106 107	1350 1123
				918	0150					107	0900
				919	0075					109	1350
				921	0750					150	~ 0525
				923	2150					727 664	1650 0200
				930	1450 1700					004 005	0100
				931 932	1250					725	1300
				697	0125					724	1050
				929	0030					722 717	1050 0700
										- 7 ¹ 9	0300
			[सं .	<b>শা–140</b>	16/245/85⊸जी पी]					720	3000
6.0	41.64 331	// u								680	-0100
	4154.—W	nereas		lantian of	the Consument						
	in the		-		the Government			,		681	
		Minist	ry of Pe	troleum S	S.O. 1759 dated					682	~ .0100
6-4-198 nd Mi	85 under inerals P	Ministr sub-sect ipelines	ry of Pe ion (1) of (Acquisi	troleum 5 Section 3 tion of 1	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in			,		682 683	· 01 00 0600
6-4-198 nd Mi Land)	85 under inerals P Act, 196	Ministr sub-sect ripelines 2 (50 c	ry of Pe ion (1) of (Acquisi of 1962),	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government			•		682	0100 0600 0100 1010
6-4-198 nd Mi Land) loclared	85 under inerals P Act, 196 d its inter	Ministratus Minist	ry of Pe ion (1) of (Acquisi of 1962), acquire the	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the					682 683 684 689	0100 0600 0100 1010
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands s	85 under inerals P Act, 196 d its inter specified i	Ministrature Minis	ry of Pe ion (1) of (Acquisi of 1962), acquire fl chedulo a	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government					682 683 684 689 690 692	0100 0600 0100 0750
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands sport purp	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified i pose of la	Ministration with sub-sect pripelines 2 (50 contion to anything pipelines with the section of the section pripeline pripeline section pripeline section pripeline section with the section pripeline section pripeline section with the section pripeline section pripeline section with the section pripeline section pripeli	ry of Pe ion (1) of (Acquisi of 1962), acquire fl chedulo a peline;	troleum Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t	S.O. 1759 dated of the Petroléum Right of User in entral Government of user in the o that notification					682 683 684 689	0100 0600 0100 0750 0350
6-4-198 and Mi Land) leclared ands sport or purp	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified i pose of la whereas	Ministration with the Solution to the Solution to the Solution to the Solution to the Solution with the Co	ry of Pe ion (1) of (Acquisi of 1962), acquire fi chedulo a peline; ompetent	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t Authority	S.O. 1759 dated of the Petroléum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Sub-					682 683 684 689 690 692 694	0100 0600 0100 0750 0350 1100 2400 0700
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands spor purp And Section	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified i pose of la whereas (1) of S	Ministration with the Consection of the Consecti	ry of Pe ion (1) of (Acquisi of 1962), acquire fi chedulo a peline; ompetent	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t Authority	S.O. 1759 dated of the Petroléum Right of User in entral Government of user in the o that notification					682 683 684 689 690 692 694 695 696	0100 0600 0100 0750 0350 1100 2400 2500
6-4-198 nd Mi and) celared ands s or purp And section o the	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of la whereas (1) of S Governm	Ministration of the Control of the C	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire ti chedule a peline; ompetent of the	troleum S Section 3 tion of 1 the Ca he right ppended t Authority said Act,	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Subsubmitted report					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699	0100 0600 0100 0750 0350 1100 2400 2500 0200
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands s or purp And Section o the	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of lawhereas (1) of S Governm	Ministration with the second of the second o	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedule appeline; ompetent of the the Cen	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t Authority said Act,	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Subsubmitted report					682 683 684 689 690 692 694 695 696	0100 0600 0100 1010 0750 0350 1100 2400 0500 0500
6-4-198 nd Mi Land) (sclared ands s or purp And section o the And onsider	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the	Ministration whereas said reg	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedule appeline; ompetent of of the  the Cen port, decid	troleum S Section 3 tion of 1 the Ca he right ppended t Authority said Act, tral Gove	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Subsubmitted report ernment has, after quire the right of					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700	0100 0600 0100 0750 0350 1100 2400 0500 0500
6-4-198 nd Mi Land) (seclared ands s) or purp And section o the And onsider	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land	Ministration whereas said reg	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedule appeline; ompetent of of the  the Cen port, decid	troleum S Section 3 tion of 1 the Ca he right ppended t Authority said Act, tral Gove	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Subsubmitted report					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 876	0100060001001010075003501100240007002500020007501150
6-4-198 nd Mi Land) leclared ands spor purp And Section the And onsider sectificate	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion;	Ministisub-sect ripelines 2 (50 contion to a minimum the section for the confection for t	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedule a peline; ompetent of the  the Cen port, decid fied in the	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t Authority said Act, tral Gove led to ac o schedule	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in central Government of user in the other notification has under Subsubmitted report cernment has, after quire the right of appended to this					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 876	
6-4-198 nd Mi and) oclared ands spor purp And section o the And onsider user in actificat Now,	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefor	Ministration with the control of the	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedule appeline; ompetent of the  the Cen port, decid fied in the  xercise of	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce the right ppended t Authority said Act, tral Gove led to ac o schedule	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in central Government of user in the othat notification has under Subsubmitted report cernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 876	010006000100075003501100240025000500750115013000050
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands spor purp And fection the And consider user in totificat Now, ub-sect	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefor (1) of S	Ministisub-sect ripelines 2 (50 contion to a minion to section for the Continuous contin	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedule appeline; ompetent of the  the Cen port, decid fied in the exercise of ection 6 of	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce the right ppended t Authority said Act, tral Gove led to ac o schedule	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in Entral Government of user in the other notification has under Subsubmitted report ernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by 1 Act, the Central					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 876 877 879 880 881	
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands spor purp And Section the And onsider iser in totificat Now, sub-sect	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefor tion (1) of ment her	Ministration whereas said register, in exotic the Scenario of	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedule appeline; ompetent of the  the Cen port, decid fied in the exercise of lection 6 of clares the	troleum S Section 3 tion of 1 the Ca the right Authority said Act, tral Gove led to ac o schedule the pow of the said at the right	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in central Government of user in the othat notification has under Subsubmitted report cernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 877 879 880 881 870	010006000100075003501100240005000500050005000500
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands spor purp And Section the And onsider user in totificat Now, sub-sect Govern aid lar	85 under inerals P Act, 196 d its interprecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefor tion (1) coment her nds specifically properties of the specifical properties	Ministration whereas said register, in exotient of the Scenario of the Scenari	ry of Pe ion (1) of    (Acquisi of 1962),    acquire the chedule appeline; ompetent of the  the Cen port, decid fied in the exercise of ection 6 of clares the he schedu	troleum S Section 3 tion of 1 the Ca the right Authority said Act, tral Gove led to ac o schedule the pow of the said at the right	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Subsubmitted report ernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by 1 Act, the Central ht of user in the ed to this notifica-					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 877 879 880 881 870 871	0100060001000750035011002400050005000500055005500550
6-4-198 nd Mi and) feelared ands spor purp And feetion of the And consider iser in notificat Now, sub-sect Govern aid lar aion he	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefor the forment her and specifiereby acquired the specifiereby acquired th	Ministration of the Scariff of the S	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedulo a peline; ompetent of of the  the Cen cort, decid fied in the exercise of elares the he schedulor laying the	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t  Authority said Act,  tral Gove led to ac o schedule the pount at the right le append the pipelin	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Subsubmitted report ernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by 1 Act, the Central ht of user in the ed to this notificance;					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 877 879 880 881 870	0100060001000750035011002400050005000500055005501100
6-4-198 nd Mi and) foclared ands spor purp And fection of the And consider iser in notificat Now, sub-sect Govern aid lar ion he	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefor tion (1) of ment her nds specifiereby acq further i	Ministration of the Survey of	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedulo a peline; ompetent of of the  the Cen cort, decid fied in the exercise of fection 6 of clares the he schedu or laying the	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t  Authority said Act,  tral Gove led to ac schedule the power the said at the right le append the pipelin wer confer	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in Entral Government of user in the to that notification has under Subsubmitted report ernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by 1 Act, the Central ht of user in the ed to this notificance;					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 877 879 880 881 870 871	0100060001000750035011002400050005000500055011000550055005500550055005500550055005500550055005500550
6-4-198 nd Mi Land) (oclared ands spor purp And Section of the And consider iser in notificat Now, sub-sect Govern aid lar tion he And 4) of	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified is pose of law whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefore the pose of the land tion; therefore the pose of the pose of the land tion; therefore the pose of the pose of the land tion is the land tion in the land tion; therefore the land tion is the land tion in the land tion; therefore the land tion is pecificated by acquirement her individual land tion in the land tion i	Ministrative sub-section to the sub-section to the sub-secti	ry of Pe ion (1) of   (Acquisi of 1962),   acquire the chedulo a peline; ompetent 6 of the  the Cen cort, decid fied in the exercise of fection 6 of clares the he schedulor laying the ise of pov Central Central	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t  Authority said Act,  tral Gove led to acc schedule the power the said at the righ le append the pipelit wer confer	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in entral Government of user in the o that notification has under Subsubmitted report ernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by 1 Act, the Central ht of user in the ed to this notificance;					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 877 879 880 881 870 871 885 886 887	010006000100075003501100240005000500050005501100055005501100055011000550110012001200
6-4-198 nd Mi Land) loclared ands si or purp And Section to the And consider user in notificat Now, sub-sect Govern said lar tion he And A) of tright Central	85 under inerals P Act, 196 d its interspecified i pose of la whereas (1) of S Governm further ring the 1 the land tion; therefor the funds specified by acq further i that section user 1 Governm	Ministration of the Survey of	ry of Pe ion (1) of    (Acquisi of 1962),    acquire the chedulo a peline; ompetent 6 of the  the Cen cort, decid fied in the exercise of fection 6 of clares the he schedulor laying the ise of pov Central of said lands sts on the	troleum S Section 3 tion of 1 the Ce he right ppended t  Authority said Act,  tral Gove led to ac o schedule the populate append the pipelin wer confer Governme shall in is date	S.O. 1759 dated of the Petroleum Right of User in Entral Government of user in the to that notification has under Subsubmitted report ernment has, after quire the right of appended to this wer conferred by I Act, the Central ht of user in the ed to this notificance; cred by sub-section and directs that the					682 683 684 689 690 692 694 695 696 699 700 701 874 875 877 879 880 881 870 871 885 886 887	010006000100075007502400075005005005000550110005500550055005500550055005500550055005500550055005500550

					$\overline{}$
1	2	3	4	5	6
			Chanpur	907	- 0050
			_	918	- 0150
				919	0075
				921	- 0750
				928	-2150
				930	1450
			1	931	-1700
				932	1250
				697	-0125
				929	- 0030
			INO. O	14016/	245/85-C-101

[No. O -14016/245/85-GP]

का. ग्रा. 4155.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) ग्राधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंद्रालय की ग्राधिसूचना का. ग्रा: सं. 1763 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्राधिसूचना से संलग्न ग्रानुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के ग्रधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए ग्राजित करने का ग्रापना ग्रामय बोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दो हैं।

और आगं यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिल करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिद्धिण्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदस्त गांक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उनत भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची हाजिरा⊶ बरेकीं⊶ जगदींशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अजिस रफवा वी. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	 गाहा <b>बा</b> द	(पाली	अलिया		<del></del>
	6		पुर ·	238	0-7-4
			[सं. इ	गे− 1401€	/249/85— जीपी]

S.O. 4155.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1763 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (i) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargans	Village		Area in B B B
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pali	Alyapur	238	0—7 - 4
			[No. O -	-14016/2	249/85-GP]

का आ 1.4156.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थन) श्रिवित्यम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिस्वना का. आ. सं. 1764 तारीख 16-4-1985 क्षारा केनीय सरकार ने उस अधिस्वना से मंत्रान अनुसूची में विनिद्धिं भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आस्य शोखित कर विया था।

भौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की खारा 6 की उपधारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

श्रीर मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्चात् इस प्रक्षिमूचना से संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का मधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है।

श्रव, श्रातः उक्त श्रीक्षिमियम की क्षारा 6 की उपघारा (1) द्वारा प्रवस्त सक्ति का प्रयोग करते हुए केक्द्रीय सरकार एतपुदारा घोषित करती है कि इस श्रीक्षसूचना में संलग्ग श्रतुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रीकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एनद्दारा श्रीकृत किया जाता है।

ग्रीर भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त पंक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण कि. में सभी बाधाग्रों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

भनुसूची हाजिस-बरेल -जनद णपुर पाइप लाइन प्रो <b>जे</b> क्ट ।							
 जिला	— — नह्म ल	परगना	गांव	- — गाटा संख्या	लिया गया रक्तवा ववि. वि.		
 l	2	3	4	5	6		
- हरदोर्ड	णाश्चर-	पानः	उ <b>ब</b> रिया	1	0-6-0		
	वाद		कला	80/1	0-13-0		
				81/2	1-9-0		
				83/1	0-0-10		
				8.2	3-10-0		
				4	0-0-5		
				85/1	0-12-0		
				122/2	2-10-10		
				$12^{4}/4$	(j= 3=0)		
				125/2	2-14-0		
				126/2	1-15-0		
				127/2	0-1,2-10		
				134/2	1-5-0		
				135/2	0-13-5		

ऑस. O-14016/250/85-जीपी]

S.O. 4156.—Wheeras by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1764 dated 16-4-85 teneicr sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Ministry Specific (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereus the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of varing in Central Government vests on this date of the publication of this duclaration in the Gas Authority of India Lai, from from all encumbrances.

SCHEDULF.
Hajira-Barcilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Arca acquired
1	2	3	4	.5	6
Hardoi	Shahahad	Paji	Ubraia Kalan	1 80 1 81/2 83/1 82 84 85/1	0-6-0 0-13-0 1-9-0 0-0-10 3-10-0 00-5 0-12-0

	<del></del>	_===		<del>==</del>	
1	,2	3	4	4	<b>б</b>
				1 2/2	2-10-10
				123/4	0 3 0
				125/2	2-14-0
				126/2	1-15-0
				126/2	0-12-10
				134/2	15-0
				135/3	0-13-5
				No. O-1401	6/250/85-GP]

का. आ. 4157.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिमूचना का. आ. सं. 1765 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुमूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आग्रा घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्चात् इस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिद्धिट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जात करने का विनिण्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त मक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस आधसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन विछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया जाता है।

और अभि उस धाराकी उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाणन की इस तारीख को निहित होगा।

ग्रनसूचः हाजिरा–वरेलं –जशदीणपुर गैस पाइप साइन प्रोजेक्ट

जला	नहस ल	परगना	ग्राम	गाटा <i>सं</i> ख्या	धर्जित रकवा व . वि . विसे
1	2	3	.	5	6
हरदोई	गाहा- वाद	पानं	कस्हार <u>े</u>	28 <b>3/</b> 1	0-12-10
				284/2	1-15-0
				285/1	4-16-10

S.O. 4157.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1765 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government, vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE
H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Fargana	Village	Plot No.	Arca acquired
1	2	3	4	5	ა
Hardoi	Shahabad	Pali	Kanhaki	283/I 284/2 285/1	0-12-10 1-15-0 4-16-10
			'No O	-14016/	151/85-G PI

का. आ. 4158.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के प्रिष्ठिकार का धर्जन) प्रिष्ठित्यम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रर्धन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की प्रिष्ठमूचना का. आ. सं० 1766 तार्रेख 16-4-85 द्वारा के की परकार ने उस प्रिष्ठमूचना से संलग्न प्रनुपूर्ण में विनिद्धित भूमियों के उपयोग के प्रिष्ठकार को पाइप लाइनों को विद्यान के लिये प्रजिन करने का अपना धामय बोपित कर दिया था;

श्रीर यतः सक्षम प्राधिकारं ने उक्त अधिनियम के द्यारा 6 के उपधाना (1) के श्रर्धन सरकार को रिपोर्ट दे वें है।

भीर श्रामे, यतः केन्द्रीय सरकार ने जन्त रिपोर्ट पर विभार करने के पश्चात् इस श्रिधसूचना से संलग्न श्रनुसूची में निर्मितिष्ट भूमियों में उपयोग का ग्रिधकार श्रीजत करने का विनिश्चय किया है;

प्रव, असः जन्त भिधिनियमं की धारा 6 की उपधारा (1) हार। प्रदस्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्युद्वारा घोषित करती है कि इस भिधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रीधकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एत्युद्वारा श्रीजन किया जाता है;

श्रीर त्रागे उस धारा के उपधारा (4) हारा प्रयत्न णक्तियों का प्रयोग करते हुए केर्न्स य सरकार निर्देश वेर्नः है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केर्न्साय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सर्भ बाधाओं से मुक्त कप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को मिहित होगा।

श्रनुसूची हाजिरा–सरेलं ∽जबद शपूर गैस पाइप लाहन शोजेक्ट

जिला	तहस ल	परगना	ग्राम	गाटा सं.	ग्रजिस रक्षवा वं≀. वि.  वि.
1	2	3	<del>-</del> -	5	6
हरदाई	शाहा-	पाल	कनका~	525	()-0-10
	बार		पुर		
			उबरिया	ī	
				526	0-3-10
				532	0-14-10
				533	0-6-10
				506	0-2-10
				558/1	0⊶ 5─ 7
				558/2	0-10-13
				559/2	1-1-10
				561/2	0-9-0
				560	1-8-0

[मं. **O**~14016/252/85-जीपी]

S.O. 4158.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1766 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lends specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the ripeline;

And further in exercise of power conserred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE HBJ Gus Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	, 4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pali	Kanakan	ur	
			Libaria	525	- 0- 0-10
				526	0-3-10
				532	0-14-10
				533	0- 6-10
		·		536	0- 2-10
				558/1	0- 5-7
1				558/2	0-10-13
				559/2	1- 1-10
				561/2	0 0 ()
				560	1 - 8 - 0

[No. O-14016/252/85-GP]

का०न्ना० 4159.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप नाइन (भूमि में उपयोग के ग्रिधिकार का ग्रर्जन) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रियीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. ग्रा. मं० 1754 नारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रिधसूचना में संलग्न ग्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के ग्रिधकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए ग्रिजन करने का अपना ग्रामय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट देदी है;

और भागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस भ्रधिसूचना से संलग्न भ्रनुसूची में विनिर्धिष्ट भूमियों में उपयोग का श्रधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है;

श्रव, श्रतः उक्त श्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संस्कार एतदद्वारा घोषित है कि इस श्रधिसूचना में संलग्न श्रनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोगन के लिए एतदद्वारा श्राजित किया जाता है;

और श्रामे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं, कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधि-करण कि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस नारीख को निहित होगा ।

भनुसूच हाजिरा--वरेलं:-जगर्दशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

नला	तहस स	परगना	ग्राम	गाटा सं∵	भ्रजित रक्षका हेक्टर
1	2	3	4	5	6
<u>रवोर्ष</u>	विल- ग्राम	कटि- यारं	डिडवन	6	. 0500
				7	. 2000
				8 के	. 0100
				8	. 0300
				1 4 के एच	. 0400
				15	. 1000
				16	. 0600
				17	. 0700
				2 <b>7</b> के	4000
				28	. 0600
				29	. 0750
				30	. 0400
				31	. 2600

1	2	3	4	5	6
	··, ··· ·			32	.0050
				193	.0750
				213	.0400
				2 <b>14</b>	.2000
				498	.0750
				500	0750
				50 t	.0750
				502	.0250

[सं. ऑ--14016/271/85-जाप]

S.O. 4159.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1754 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in I and) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the scheduled appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE
HBJ Gas Pipeline Project

District Tehsil		Pargana	Village	Plot No.	Area in Hectares	
1		3	4	5	6	
Har-loi	Bilgram	Katiyari	Dhak-	6	.0500	
			Pura	7	.2000	
				8K	.0100	
				8	.0300	
			,	14kh	. 0400	
				15	.1000	
				16	.0600	
				17	. 0700	
				2 <b>7k</b>	. 4000	
				28	.0600	
				. 29	0.750	
				30	0.400	
				31	.2600	
				32	.0050	
				193	. 0750	
				213	. 0400	
				214	.2000	
				498	. 0750	
				500	.0750	
				501	. 0750	
				502	.0250	

[No. O-14016/271/85-GP]

का. आ. 4160.—यतं पेट्रोलियम और खनित्र पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) आंधनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिस्थना का. आ. सं. 1728 तारीख 16-4-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को विछाने के लिए अजित करने का अपना आशय भोषित कर दिया था:

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है:

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उनत रिपोर्ट पर विचार नारने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में चिनिदिष्ट भूमियों में उपयोग ना अधिकार आणित नारने ना विनिश्चय निया है;

अब, अक्त उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिद्घ्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइन लाइम बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शाकितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में शोषणा के प्रकाशन की इस तारी ख को निहित होगा।

श्रन्सूर्च हाजिरा–बरेलो--अगर्द शपुर गैस पाड प लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहस ल	परगना	ग्राम	गाटा सं.	ग्रजित रकवा वे . वि . वि .
		-			
1	2	3	4	5	6
हरदोई	विल- ग्राम	कटि- यारी	सुरजपुर दर्जन	270 ख	0-18-0
			पजीशाल	τ <u>'</u>	
				280 ख	2-0-10
				279 क	0-16-0
				281	0-1-0
				282	0-7-16
				283	0-2-0
				284	0-0-5
				315	0-2-10
				316	0-10-0
	*			318	0-16-0
				319	0-10-0

1	3	3	4	á	4
V				३ <u>३२</u> मि	1)—6-()
				233/1	0-5-10
				232	1-4-0
				233/2	2-0-5
				231/1	1-8-0
				231/2	1-6-10
				359布	0-10-0
				368	1-3-0
				369年	0-12-0
				369 <b></b>	0-17-10
				371	1-8-0
				3 <b>73</b>	1-8-0
				374 क	<b>1</b> -16-0
				<u> </u>	الاحت عرامة

सि. **O**-14016/273/85-जीपी

S.O. 4160.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1728 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user to the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laving pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil Pa	rgana Vill	age Plot N	lo. Area Acquired	Re 1 marks
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Surajpur	270kb	0-18- 0
			Durjan	280kb	7- 0-10
			Panjshala	279k	0-16-0
				281	0-1-0
				282	0- 7-1
				283	0-2-0
				284	0-0-
				315	0- 2-10
				316	0-10-
				318	0-16-
				319	0-10 -
				322 Mi	0- 6-
				233/1	0- 5-10
				23?	1-4-
•				233/2	2- 0- :
				231/1	1- 8- (
				231 /2	1- 6-10

[साग <b>II खंड</b> 3(ii)]	भाग <b>I</b> I खंड 3(ii)] भारत का राजपन्न : सितम्बर 7, 1985/माद्र 16, 1907								4709	
3 2	3 4	5	6	1	2	3	4	5	6	
		359 <b>k</b> 368	0-10-0					9.1	D = 45	
		369 <b>k</b>	1- 3- 0 0-12- 0					31	0-5-15	
		369kh	0-17-10					32	1-6-0	
		371	1-8-0					331/1 33/2	0-4-7	
		373	1-8-0					•	0-4-8	
and the same of th		374k	1-16- 0					49	0-9-9	
	[No. (	<b>D-14016</b> /3	73/85-GP]					54	0-14-4	
ं का <b>ं</b> आं० 4161.—	यतः पेट्रोलियम	और खि	तिस वाष्ट्रप					50 53	0-3-10	
• •	•								0-3-0	
लाइन (भूमि में उपयोग्								55 = 6	0-10-4	
1962 (1962 কা 50)								56 58	1-2-0	
अधीन भारत सरकार		प्रम मंत्रा						59	0-3-0 0-6-10	
अधिमुचना का०आ०सं० 172	39 ता <mark>रीख 1</mark> 6-	·4-85 द्वार	त केन्द्रीय					60	0-4-4	
सरकार ने उस अधिसूचना से								66		
में उपयोग के अधिकार को								65	0-8-10 0-17-6	
अजित करने का अपना अ								68	0-17-0	
आजत करन का अपमा अ	।शिय जाजत व	गर किया	٦١,					95	0-15-16	
» – – – (			·					94	0-03-0	
और यतः सक्षम प्रा								100	0-2-0	
धारा 6 की उपधारा (1	) के अर्घीन व	सरकार क	ा रिपोट					191	0-6-0	
दे दी है;								102	0-1-10	
								106	0-15-0	
और आगे यतः केन्द्री	य सरकार ने	उक्त रि	पोर्ट पर					107	0-4-10	
विचार करने के पश्चात् इ	स अधिसचना	से संलग्न	अनसची					108	0-4-13	
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उ								109	0-6-6	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	विभाग भाग आर	1701	400					158	0-12-0	
का विनिश्चय किया है ;								106	0-15-0	
अब, अतः उक्त अधि	नियम की धाट	ग 6 वरी	उपधारा					107	0-4-10	
								108	0-4-13	
(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का								109	0-6-6	
एतद्द्वारा घोषित करती है वि								158	0-12-0	
में विनिदिष्ट उक्त भूमियों								160	0-3-0	
लाइन बिछाने के प्रयोजन	के लिए एतद्	द्वारा अजि	त किया					159	0-15-0	
जाता है ;	•							161	0-3-0	
•			_					162	0-3-10	
और आगे उस धारा								46	0-0-1	
शक्तियों का प्रयोग करते	हुए केन्द्रीय स	ारकार नि	र्देश देती					157	0-1-10	
	۲ .	- A								

[सं. **O**-14016/274/85-ज.पी]

0-0-10

सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा। प्रनुसूर्यः

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में

हाजिरा-बरेले -जगदे शपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	नहसं≀ल	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकवा व वि.वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	विल- ग्राम	कटि- यार्रः	भूपति- पुर नगरा	19	0-9-0
		-		20 30	0-17-2 0-6-6

S.O. 4161.—Wheeras by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1729 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to arguing the right of were in the lands creatifed its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE HBJ Gas Pipeline Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B.B.
1	2	3	4	5	6
1 Hardoi	Bilgram	3 Katiyari	4 Bhopeti-pur Nagra	5 19 20 30 31 37 331/1 33/2 49 54 50 53 55 56 58 59 60 66 65 68 95 94 100 101 102 106 107 108 109 108 109 109 109 109 109 109 109 109	
				158 160 159 161 162 46	0-12- 0 0- 3- 0 0-15- 0 0- 3- 0 0- 3-10 0- 0- 1
				157 67	0-1-10 0- 0-10

[No. O-14016/274/85-GP1

का.मा. 4162.—प्रतः पेट्रोलियम मीर खनिज पाइप लाइन (मूप्ति में उपयोग के घिकार का प्रजैन) मधिनियम, 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) के मधीन मारत सरकार के पेट्रोलियम

मंत्रालय की प्रधिसूचना का, या. सं. 1730 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रंधियूचना से संलग्न ग्रनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के श्रंधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के निये भूजित करने का भूपना ग्राह्मय बोबित कर दिया था;

भीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उन्त प्रिधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

भीर भागे यकः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस प्रधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग का प्रधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है;

प्रथा, भतः उक्त प्रिविनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय तर्कार एतवृद्धारा घोषित करती है कि इस प्रिधिसूचना में संलग्न प्रनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतवृद्धारा प्राजित किया जाता है;

और आगे उस घारा की उपधारा (4) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश वैती है कि उपन भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बनाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के इकाक्षम की इस तारीक्ष को निष्टित होगा।

भनुसूच। हाजिरा--बरेलं --जगर्द गपुर गैस पाइप साइन प्रोजेक्ट

जिला	तहस ल	परगना	ग्राम	गाटा सं.	प्रजित रकवा
					वी. वि. वि
1	2	3	4	5	6
हरदोई	विल-	कटि⊬	सरेखर	256	0-0-10
	ग्राम	यार			
				303	0-1-0
				304	0-8-0
				305	0~9~0
				308	0-17-5
				312	0-10-0
				313	0-16-0
				317	0~16~0
				318	0-13-0
				452	0-7-0
				457	<b>0~ ;+−</b> 0
				458	0-11-0
				469	0-8-10
				470	0-5-10
				507	0-6-0
				510	0-2-0
				511	0-9-0
				512	0-10-0
				517	0-1-0.
				518	0-6-0
				498	0-11-0
				499	0-11-10
				50 <b>0</b>	0-0-10
				307	0-3-0
				314	0-1-10
				453	0- 2- 0
				319	0-0-10
				468	0-1-5
				491	0-2-0

[सं. O-14016/275/85-जीपी]

S.O. 4162.—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1730 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the lands appecified that the lands appecified in the lands appecified the lands in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

**SCHEDULE** HBJ Gas Pipeline Project

Plot No.	Area B.B.B.
5	6
256	0-1-10
303	0-1-0
304	0-8-0
305	0-9-0
308	0-17- 5
312	0-10-0
313	0-16- 0
317	0-16-0
318	0-13-0
452	0 <b>→ 7</b> ~ 0
457	0-9-0
458	0-11- 0
469	0-8-10
470	0- 5-10
507	0- 6- 0
510	0- 2- 0
511	0- 9- 0
512	0-10-0
517	0-1-0
518	0-6-0
498	0- 11-0
499	0 11-10
500	0- 010
307	0- 3- 0
314	0- 1-10
453	0-2-0
319	0- 0-10
468	0-1-5
491	0- 2- 0
	468

[No. O-14016/275/85-GP]

अपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा उकी उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के (पैट्रोलियम संज्ञालय की अधिसूचना काल्आल संल 1774 तारीखा वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमुचना से संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछाने के प्रयोजन के लि ये अजित करने का अपना आध्य घोषित कर दिया था।

भीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है

भीर आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिशोर्ट पर विकार करने के पपनात इस अधिसुचना से संलग्न अनुमुर्का में विनिद्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उमत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूर्धा में विनिद्धिष्ट उन्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिये एनवृक्षारा अर्जित किया जाता है।

भीर आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त गमितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकानन की इस तारीचा से निहित होगा।

अनुसुची एच वो , जे . गेस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

प्राम :	देवालखेड़ो, तहसाल: ईसागढ,	, जिला: गुना, राज्य: मध्य प्रदेश					
प्रनु. ऋ.	- <b>ख</b> सरा नं.	उपयोग भिक्षकार भर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में) ंं					
1	3	3					
1.	174	0.178					
2.	175	0.240					
3.	178/2	0.052					
4.	178/1	0.042					
5.	179	0.199					
6.	189	0.219					
7.	190	0.178					
8.	191/1	0.105					
9.	191/2	0.052					
10.	193	0,270					
11. 12. 13.	176 177 178/3	0.027					
14.	192/3	0.093					
15.	194	0.020					
16.	197	0.051					
17.	198	0.105					
18.	199	0.125					
19. 20.	200 }	0.005					
21.	210	0.260					
22-	212	0.314					
23.	188/1	0.005					
24. 25.	215 }	0.251					
26. 27. 28.	216 218 228	0.658					

29.	2 219		SCHEDULE HBJ Gas Pipeline Project						
30.	220	*****							
31.	229	<del></del>	Village:	: DYPALKHEDI;	Tehsil · Isagarh	Diest Guna			
3 2.	ر 230				tona Langurii,	Diss. Guila			
33.	233	0.314	S. No.	Survey No.		Arus to be			
34.	235/2	0.081	<b>2.</b>	Barrey 140.		Area to be Acquired for			
35.	236/5	0.005				R.O.U in			
36.	234	0.083				Hector			
37.	364	0.073							
38.	376/1	0.188	1.	174		0.178			
39.	378/1	0.031	2.	175		0,240			
40.	376/3	0.083	3. 4.	178/2 178 1		0.052			
41.	381/2		5.	179		0,042 0,199			
42.	382/2	0.010	6.	189		0.219			
43.	381/1		7.	190		0.178			
44.	382/1	0.410	8.	191/1	•	0.105			
	384/2	0.230	9.	191/2		0.052			
45.	384/2	0.230	10. 11.	193 176 )		0,270			
46.		0.178	12.	177		0.027			
47.	385	0.345	13.	178/3 J					
48.	388	0.449	14. 15.	192/3 194		0.093			
49.	389	0.010	16.	197		0.020 0.051			
50.	3 7 9/3खर / ::	0.052	17.	198		0.105			
51.	376/5	0.366	18.	199		0,125			
5 2.	376/4	0.126	19.	200		0.005			
וכלונ	:-कुल क्षेत्रफल	6.483	20. 21.	201 } 210		0.260			
711	कृत्। पात्राकत	0.400	22.	212		0,314			
		[सं. O-14016/292/85-जापं]	23.	188/1		0.005			
		[4. 0514016/292/85-414]	24. 25.	$\binom{215}{217}$		0 251			
			26.	216 )					
			27.	218 {					
		by notification of the Government	28. 29.	228 }		0,658			
		nistry of Petroleum S.O. 1747 985 under sub-section (1) of	31.	220					
		n and Minerals Pipelines (Acquisition	3.7•	230 J					
		and) Act, 1962 (50 of 1962), the	33.	233		0.314			
		clared its intention to acquire the	34. 35.	235/2 236/5		0,081 0,005			
ht o	f user in the land	s specified in the schedule appended	36.	234		0.083			
that	notification for p	ourpose of laying pipeline,	37.	364		0.073			
<b>4</b> – •			38.	370/1		0.188			
		mpetent Authority has under Sub	39.	378/1		0,031			
	Government;	of the said Act, submitted report	40.	376/3		0.083			
шс	Government,		41.	381/2		0.010			
And	further whereas	the Central Government has, after	42. 43.	382/2 <i>[</i> . 381/1 ]					
nside	ring the said rep	ort, decided to acquire the right	44.	382/1		0.410			
		ecified in the schedule appended to	45.	384/2		0.230			
8 no	ification;		46.	384/1		0.178			
Non	therefore in ex-	tercise of the power conferred by	47.	385		0 345			
		ction 6 of the said Act, the Central	48.	388		0.449			
		erest that the right as were in the	49.	389		0.010			

389

376/5

376/4

379/3 KH

TOTAL AREA

49.

50.

51.

52.

Government hereby declares that the right of user in the

said lands specified in the schedule appended to this notifica-

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this decalaration in the Gas Authority of India Ltd. free

tion hereby acquired for laying the pipeline;

from all encumbrances.

[No. O-14016/292-85-GP]

0,052

0,366

0.126

<b>ला.सा. 4164</b>	गतः वैशेषिकप्र	और खनिज	वाद्रप साहत	1	2	3	4	5	6
(भूमि में उपयोग के व							<del></del> ·	184	0-12-0
* **		•				1		185	0-12-0
(1962 का 50) की	_	•						244	0-5-0
	पेंद्रोलियम मंह		•••					245	0-4-10
का.आ.सं. 2329								246	0-3-0
ने उस अधिसूचना मे	। संलग्न अनुसूच	बी में विनि	क्षेष्ट भूमियों					247	0-2-10
के उपयोग के अधिकार	को पाइप लाइ	नों को बिछ	ाने के लिए					246	0-3-10
अजित करने का अपन	ा आशय <mark>घो</mark> षिर	त कर दिया	था।					251	0-3-0
और यतः सक्षम प्राप्ति	क्टारी <del>ने ज्याद</del> अ	<u>रिक्तिकार क्र</u> ी	' ब्लाचा ६ स्टी					253	0-3-0
	_							255	0-2-10
उपधारा (1) के अधीन	सरकार का उर	पाट्यया ह्	,					2 <b>5</b> 6	0-5-0
और ग्रागेयतः के	द्रीय सरकार ने	उक्त रिपोर्ट	पर विचार					257	0-9-0
करने के पश्चात् इस १	प्रधिसूचना से संः	लग्न ग्रनुसूची	में विनिर्विष्ट					258	0-13-0
भूमियों में उपयोग क	ग प्रधिकार <b>प्र</b> ि	जत करने थ	ा विनिध्चय					281	0 2 1 0 0 2 1 0
किया है।								318 319	0-2-10
•			5					320	0-4-0
ग्रब ग्रतः उक्त								321	0-2-10
(1) द्वारा प्रदत्त शवि								322	0-6-0
एलद्द्वारा घोषित करर्त			_					323	0-3-10
में विनिर्दिष्ट उक्त भा	मयों में उपयोग	का श्रधिकार	:पाइपलाइन					324	0-3-0
बिख्डाने के प्रयोजन के	लिए एतद्द्वारा	भाजित किय	राजाता है 🕡 👚					325	0-5-0
और आगेउस	•							328	0-1-0
अपि आग उस शक्तियों का प्रयोग								329	0-17-0
	-							253	0-0-10
- ·	मयों में उपयो							330	0-19-10
सरकार में निहित	•							331	0-12-10
लि, में सभी बाधा	· ·		के प्रकाशन					348	0-8-0
की इस तारीख के	निहित होगा	1						349	0-0-10
	अनुसूची							350	0-7-0
<b>हाजिरा – बरेर्स</b> े	-जगर्दश्यपुर गैस प	१६५ लाइन प्रोप	वेक्ट ।					352 467	0-0-10
जिला तहसील परगी		गाटा सं	अजित रक्षा					463	0-6-0
जिला तह्नाल परन	। भाग	गाटा त्त.	भागत ५३ व. मी वि.					492	0 7 0 0 5 0
			मा । पा. मि.					493	0-9-0
<del></del> -	<del></del>							499	0-3-10
<del> </del>	3 <u>4</u>	5	6					500	0-5-0
हरदोई विलग्राम करिया	रं: दफपुरा	20	0-14-10					501	0-0-10
		19	0-17-0					601	0-4-0
		29	0-2-0					602	0-9-0
		30	0-19-0					498	0-4-0
		31	0-4-0					604	0-5-0
		32	0-14-0					642	0-6-0
		73 74	0-14-0 0-7-0					644	0-8-10
		75	0-8-0					645	0-11-10
		, ,						646	0-7-0
		76	0 7 0						010
		76 116	0 7 0 0 2 1 0					648	0-1-0
		116	0-2-10					647	0-13-0
			0-2-10 0-18-0					647 707	0-13-0 0-18-0
		116 117	0-2-10					647 707 708	0-13-0 0-18-0 0-13-0
		116 117 122	0-2-10 0-18-0 0-14-10					647 707 708 709	0-13-0 0-18-0 0-13-0 0-3-0
		116 117 122 167	0-2-10 0-18-0 0-14-10 0-6-0					647 707 708 709 710	0-13-0 0-18-0 0-13-0 0-3-0 0-11-0
		116 117 122 167 132	0-2-10 0-18-0 0-14-10 0-6-0 0-18-0					647 707 708 709 710 711	0-13-0 0-18-0 0-13-0 0-3-0 0-11-0 0-1-0
		116 117 122 167 132 173	0-2-10 0-18-0 0-14-10 0-6-0 0-18-0 0-12-10					647 707 708 709 710	0-13-0 0-18-0 0-13-0 0-3-0 0-11-0

[No. O-14016/345/85-GP]

I	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
<b>ध्</b> रकोई	विलग्नाम	काटियारी	ह कप्रा	121	0-1-0	Hardoi	Bilgram	Katiyari	Dhakpura	183	0-5-0
			-	133	0-1-0					184	0-12-0
				326	0-0-5					185 244	0-1-0 0-5-0
				327	005					245	0-4-10
		•		603	0-2-0					246	0-3-0
•	•			491	0-2-0					247	0-2-10
				497	0-1-0					248 251	0-3-10 0-3-0
				469	0- 2- 0					252	0-3-0
			,	488	0-0-10					255	0-2-10
***************************************			÷ <b>Ω</b> -140	16/245/	85अपि. पी.]					256	0-5-0
		ι	<b>V</b> 140	10,343,	0041. 11.]					257 258	0-9-0 0-13-0
					Government					281	0-2-10
					S.O. 2329 of Section					318	0-2-10
3 of the	Petroleur	n and Mi	nerals Pipel	ines (Á	cquisit on of					319	0-6-0
					, the Central the right of					320 321	0 <del>-4-</del> 0 0-2-10
user in t	he lands	specified in	the schedu	icquire ile appe	nded to that					322	0-4-10
notification	on for pur	pose of lay	ying pipeline	;						323	0-3-10
And v	vhereas th	e Compet	ent Author	itv has	under Sub-					324	0-3-0
Section (	1) of Sec	ction 6 of			mitted report					325	0-5-0
to the	Governme	nt;								328 329	0-1-0 0-17-0
					nt has after					253	0-0-10
					the right of nded to this					330	0-19-10
notification		spoomed n	· tigo bonda	-re upp						331	0-12-10
Mow	therefore	i- everaje	o of the		onformed by					348 349	0-8-0 0-0-10
			e of the n 6 of the		onferred by					350	0-7-0
					f user in the					352	0-0-10
			nequie appe ing the pip		this notifica-					467	0-6-0
										468	0-7-0
					rects that the					492 493	0-5-0 0-9-0
right of	user in	the said 1	ands shall	instead	of vesting in					499	0-3-10
Central of this	Governme	nt vests of	n this date	of the	o publication dia Ltd. free					500	0-5-0
	encumbra		as Muthority	01 11	Raid Eta: Hoo					501	0-0-10
										601	0-4-0 0-9-0
		SCHEI	OULE							602 498	0-9-0
	H.B	J. Gas Pip	e Line Proje	ect						604	0-5-0
	Tobasil	Pargana	Village	Plot	Arca in					642	0-6-0
District	Tahasil	Latkana	VIII486	No.	B.B.B.					644	0-8-10
										645 646	0-11-10 0-7-0
ι	2	3	4	5	6					648	0-1-0
										647	0-13-0
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Dhakpure	1 20 19	0–14–10 0–17–0		-			<b>7</b> 07	0-18-0
				29	0-2-0					708	0-13-0
				30	0-19-0					709 710	0-3-0 0-11-0
				31	0-4-0					711	0-1-0
				32	0-14-0					712	0-7-0
				73 74	0-14-0 0-7-0					814	0-13-0
				75						118	0-2-0
				76	0-7-0					121 133	0-1-0 0-1-0
				116	0-2-10					326	0-0-5
,				117						327	0-0-5
				122 167	0-1 <b>4-</b> 10 0-6-0					603 491	0 <b>-2-0</b> 0 <b>-2-0</b>
				132						497	0-1-0
				173	0-12-10					469 488	0-2-0 0-0-10
				174	0-2-0					-700	2-0-10

175

0-11-0

1165 --- यतः केस्द्रीय भरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हर्जारा⊸बरेलीं~ अगदीकपूर अक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भीरतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानो चाहिए।

और यतः प्रतित होता है कि ऐसी लाइनी को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतर्इपायद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करन, आवश्यक है ।

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पहिष लाइन (भृमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपध्या (1) द्वारा प्रथत गम्तियो का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आणय एतद्वारा घोषित किया है।

बंधार्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए अक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ 226 020 यू. पी. की इस अधिसूचना की नारीख से 21 दिन के भीनर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने बाला हर व्यक्ति विनिधिष्टनया यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फैंस ।

अनुसूची हाजिरा-वरेली-जगदीशपुर पाटप लाइन प्रोजेबट ।

সিলা	नहस <i>ा</i> न	परगन≀	ग्रामे कानाम	गाटा सं.		गयाः वे.वि.	
]	2		4	5		(5	
	ज्ञाप्र 	हेगापुर	लालपुर छिबना				
	. —			71	6	1.5	10
				82	2	02	
				81		_	10
				105		01	
				199		03	
				201		03	05
				106	n	1.5	10
				200	2	15	
				198		01	
				197		01	
				166		02	
				109	_	0.4	10
				193		02	10
				110	_	06	10
				194		05	10
				114		0.1	10
				1 ! 5		01	
				116		_	10
				195		06	10
				1 17	_	_	10
				118		09	
				120	_	10	10
				121		07	
				123		04	
				124		08	
	•			167	1		

ι	2		4	5			6
	- 5	-		125			02
	,			166		02	15
				165			10
				134		01	08
				164		17	
				163	_	03	18
				158	_		10
				159			05
				135	1	02	
				136	_	04	05
				- 137	_		0.5
				144	_	02	
				145			
				146	_	09	
				143	1	06	10
				150	_	02	08
				482		02	10
				171		<del></del> -	05
				157			08
				122		<b></b>	10
				46	24	'3	14
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ————————————————————————————————————	) <del>-</del> 14016/	488/8	5 <b>⊸</b> ₹î.	पी

S.O. 4165.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Barcilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of Iudia Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal pract tioner.

**SCHEDULE** Hazira-Bareily-Jagdishour Pipeline Project

District	Tahasil	Pargana	Village	Pla No.		Aroa in Juired B.B.B
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	L-lpur C	-	71 82 81 105 199 201 106 200 198 197 196	6-15-10 -2-02 

1	3	3	4	1	5	6				अनुसूची		
Kanpur	Derapur	Derapur	Lalpur	China	109	-04-10	एच. वी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोगेशट					
Dehat					193	02-10						
					110	-06-10	জিলা	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गर्मा
					194	-05-10						र्षाध्
					114	-0110						विः विः विः
					115	-01				<del></del> -	<u> </u>	
					116 195	<b>1</b> 0 0610	1	2	3	4	5	6
					117		हरदोई	शाह्याद	पासी	धौरालिया		
					118	-09	•	•			15	0-10-0
					120	-10-10					29	0-17-15
					121	-07-					31	0→5-0
			•		123	-04-					32	0-3-4
					124	-08-						
					167	-1 -					33	0-14-0
					125	02					34	0→ 4− 5
					166	-02-15					35	0-0-5
					165	~ -10					36	1-4-12
					134	0108					39	1-4-12
					164	-17-				•	42	1-5-16
					163	-03-18					5.5	1~6→8
					158	10					56	080
					1 59 1 35	05 1-02-						
					136	-04-05					62	111-5
					137	- ~05					63	0-10-0
					144	-02-					67	1-4-12
					145	2					68	0-2-0
					146	-09-					65	07-10
					143	1-06-10	,		<u> </u>	<del></del>	<del>-</del>	
					150	-02-08				[सं. O-	14016/248/	85 चर्नाः पीं]
					482	-02-10				- 1111	ப ரக வி€	ायासन, उपसचिव
					171	05					ત. 'કુજા, અનાજ	TACHEL STREET
					157	08						
					122	10						Covernmen

[No. O-14016/488/85-GP1

24-3-14

का. आ. 4166-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (धमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अित्यम 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की जी उपघारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्राक्षम की अधिसूचना का. आ. सं. 1760 तारीच 16-4-95 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संसान अनुसूची में विनिविध्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइकों की बिछाने के प्रयोजन के लिये अभित करने का अपना आसय चौषित कर विया था।

और यतः समाम प्राधिकारी में उपत अधिनियम की धारा e की उपवारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अमृसूची में विमिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिष्चय किया है।

अब व्यतः उत्तर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) हारा प्रदश्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्द्वार घोषित करती है कि इस अधिस्वना में संलग्न अनुसूची में थिनिविष्ट उपत भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिये एतवृद्वारा ळाजित किया चाता है।

और कारी उस खारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदल्न कवितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश वैती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केम्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीका से निहित होगा।

S.O. 4166.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1760 dated 16th April, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

<b>SCHEDU</b> LE						
H.B.J. Gas Pipeline Project						

Distt.	Tahasil	Pargana	Villago	Plat No.	Area Acquired in B.B.B.	
1	2	3	4	5	6	
Hardoi	Shahabad	Pali	Dhauralia	15	0-10-0	
				29	0-17-15	
				31	0-5-0	
				32	0-3-4	
				33	0-14-0	
				34	0-4-5	
				35	0-0-5	
				36	1-4-12	
				39	1-4-12	
				42	1-5-16	
				55	1-6-8	
				56	0-8-0	
				62	1-11-5	
				63	0-10-0	
				67	1-4-12	
				68	0-2-0	
				65	0-7-10	

[No. O-14016/246/85-GP] M. S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

## कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) नई दिल्ली, 22 ग्रागस्त, 1985

का० प्राप्त का० का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० का० प्राप्त का० का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० प्राप्त का० का० प्राप्त का० प्राप

[सं० 50-4/84-एल०डी०टी०(ए० क्यू)] डी० डी० नाहर, ग्रवर सचिव

# MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(Deptt. of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4167.—In exercise of the powers conferred by subsection (i) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby prohibits import into India of poultry including pureline and grand-parent stock, hatching eggs, etc. from Australia for a period of 6 months from the date of issue of this notification in view of outbreak of avian influenza in that country.

[No. 50-4/84-LDT(AQ)]
D. D. NAHAR, Under Secy.

# पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 ग्रगस्त, 1985

का॰ ग्रा॰ 4168—अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ग्रिधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रोजेक्ट एवं इक्विपमेंट कार्पोरेणन ग्राफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान ग्रुप महा प्रबंधक श्री जी॰ एस॰ गुप्ता को उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की ग्रवधि के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में, ग्रनुसूची "ग" के रू॰ 3500—4000 के वेतनमान में, एतद्वारा पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं प्रणासन) नियुक्त करते हैं।

[सं० ए०वी॰ 24020/6/84-ए०ए०(एफ-H)] एस० सी० कोहली, वित्त नियंतक

## MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th August, 1985

S.O. 4168.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of Section 3 of the International Airports Authortiy Act, 197! (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Gupta presently Group General Manager, Projects & Equipment Corporation of India Limited as a whole-time Member (Finance & Administration) in the International Airports Authority of India, in the Schedule 'C' scale of Rs. 3500—4000, for a period of three years from the date of his assuming charge of the post.

[No. AV-24020[6₁84-AA(F.II)] S. C. KOHLI, Financial Controller.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 ग्रगस्त, 1985

का० श्रा० 4169—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नडन्तुनगर टेलीफीन केन्द्र में दिमांक 1-9-85 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/85--थी एच बी (पीटी)] के० पी० शर्मा, सहायक महा निदेशक (पी०एच०बी)

#### MINISTRY OF COMMUNICATION

(P&T Board)

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4169.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specified 1-9-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Naduvathunagar Telephone Exchange Kerala Crele.

[No. 5-9|85-PHB(PT)] K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

#### श्रम मंत्रास्य

नई दिल्ली, 14 श्रगस्त, 1985

कां.मा. 4170—शैद्योगिक विवाद म्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के म्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार, हिन्दुस्तान कर्माग्रयल बैंक लि० सिर्सा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियाजकों और उनके कर्मकारों के बीच, यनुबंध में निर्दिष्ट आद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, चंडीगढ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8 ग्रगस्त 1985 को प्राप्त हुआ था।

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th August, 1985

\$.O. 4170.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employer in relation to the Hindustan Commercial Bank Limited, Sirsa and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th August, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 61 of 1984; Chandgarn

#### PARTIES:

Employers in relation to the management of Hindustan Commercial Bank Ltd.

#### AND

Their Workman: Sh. Suresh Kumar

#### APPEARANCESS:

For the Employers-Shri A. C. Jain.

For the workman—Petitioner with Sh. L. S. Sachdeva.

ACTIVITY: Banking.

STATE: Punjab.

#### AWARD

### Dated the 1st of August, 1985

The Central Govt, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, vide their order No. L-12012[9] 84|D.IVA dated the 2nd of February, 1985 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication—

"Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank Ltd; H.O. Kanpur in relation to their Branch Office Sirsa (Haryana) in terminating the services of Sh. Sursh Kumar, Peon-cum-Waterman with effect from 20-1-83 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitld?"

- 2. During the course of hearing a suggestion was floated to the management to reconsider their stand because the petitioner was reported to be a poor man with family liabilities and on their own showing there was no charge of mis-conduct against him. In all fairness to them, the Management responded with grace and offerd to provide fresh employment to the petitioner in the regular cadre of their subordinate staff. They also agreed to give him certain qualified notional benefits provided it did not bind them with monetary liability in any shape whatsoever. The proposition was accepted by the petitaloner.
- 3. As such on taking down the statements of the parties on my record and hearing them. I return my Award in the following terms which are quite fair to the petitioner workman.
- (A) The Respdt, Management would take immediate steps to provide employment to the petitioner in the regular cadro of its subordinate staff; in case the matter is delayed for any administrative or such other reasons, the petitioner would report for duty at their Sirsa Branch on 16-8-1985 and thence forth shall deemed to be on duty for all intents and purposes.
- (B) Even though the petitioner would not be entitled for any monetary benefits including backwages, bonus or such service facilities which could be encashed yet he shall deemed to be in continuous service from the stage of his initial appointment for the purpose of seniority and notional increments etc.

Chandigarh 1-8-1985,

> I. P. VASISHTH, Presiding Officer. [No. L-12012]9[84-D.IV(A)] K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer.

## **मई दि**र्लिं। 26 अगस्त, 1985

लग. ओ. 4171—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 शा 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रयंक्षतल से गम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीख, अनुबंध में निर्दिष्ट अद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अद्योगिक अधिकरण, सं. 2, बम्बई के पंचाट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 अगस्त, 1985 प्राष्ट्र हुआ था।

## New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4171.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2 Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on the 13th August, '85.

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMEN'T INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2|34 of 1985

#### PARTIES:

Employers in relation to the management of State Bank of India, Nagpur.

## AND

#### Their Workmen

#### APPEARANCES:

For the Employers—(1) Shri A. G. Ramani, Assistant Law Officer

(2) Shri A. E. Kulkarni, Officer M.M.G. Sc. II. Regional Officer, Nagpur

For the Workmen—Shri S D. Phadke, President, SBI & S. B. Employees' Union, Nagpur.

_____

STATE: Maharashira INDUSTRY: Banking

Bombay, dated the 5th August, 1985

#### AWARD

By their order No. L-12012(201)[84-D.H(A)] dated 12-3-85 the following dispute has been referred for adjudication u. 3 r Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.—

- "Whether the action of the management of State Bank of India Region III, Nagpur in terminating the services of Shri B. D. Uike, Bank Guard, Chandur Railway Branch with effect from 25-6-1983 is justifled. If not, to what relief the workman is entitled?"
- 2. After holding an enquiry into the alleged misconduct of the workman concerned, on the strength of the finding noted by the Enquiry Officer by order dated 16-6-1983 the workman, a Watchman, serving at the relevant time in the Branch of the State Bank of India at Chandur was discharged from service and although an appeal was preferred against the said order the appellate authority namely the Chief Regional Manager rejected the same on 5-9-1983. Since a dispute was taised before the Assistant Labour Commissioner (C) ultimately the same led to the reference.
- 3. By award part I dated 7-5-1985 on hearing the parties and going through the enquiry papers the Tribunal held the enquiry to be not legal and invalid and at the same time at the request of the management gave them an opportunity to adduce evidence to prove the misconduct before the Tribunal, However as per para, 12 of the Award Part I this opportunity was restricted to the misconduct which was held proved by the Enquiry Officer and not that which was held not proved. It is not clear why there are two enquiry reports first dated 18-3-82 and the second dated 26-2-1983 but since there was a second enquiry, the first one is deemed to have been oblite-rated and findings as to which of the charges were held established reference necessarily will have to be made to the second enquiry. From the findings as noted in the report it is seen that regarding the chargesheet dated 2-12-1981 relating to the incident alleged to have occurred on 22-11-1981 the Enquiry Officer noted the finding that it is proved that Shri Uike has committed offence of indecent behaviour on the Bank premises and disobedience by not allowing the Branch Manager in Bank premises by uttering unparliamentary language. The charge against the workman that he remained absent unauthorisedly from duty on 8-11-1981 and 20-11-1981 was held not establishment. From the chargesheet dated 4-1-1982 relating to the alleged incident of 3-12-1981 the finding was that charge No. I namely on 3-12-1981 at about 6,30 P.M. the workman reported for duty from 6.30 to 2.30 a.m. undr influence of liquor and accompanied by lady proved. Regarding charge No. 2 namely that on the very date at about 7,00 p.m. while under influence of liquor, the workman abused the Branch Manager and threatened him by using the words "you will be beaten in the bazar with shoes at the hands of a female". It was held proved that the workman misbehaved with the Branch Manager on that day but the charge of being under the influence of liquor was held not proved. These details are stated because only the charges held proved by the enquiry officer are the subject matter of consideration before the Tribunal.
- 4. Relying upon the opportunity given to the management they have examined two witnesses SIShri Jayant Vishnu Pant Pandey and Ramesh Vishnupant Madhikar, respectively then Branch Manager and Agricultural Development Manager attached to the said branch during the relevant time. The evidence of Shrl Pandey is that on 22-11-1981 at about 6.30 or 7 P.M. when he returned to Chandur Railway town and was taking tea at the house of Shri Madhikar, the Badli Watchman Shri Paighan arrived the said house complaining of assault by the workman i.e. Uike the watchman or Bank guard. Shri Paighan had injuries and was bleeding and his clothes were soiled with blood, therefore in order to see as to what was the matter the witness along with Shri Madhikar. Shri Kapre and Shri Paighan proceeded to the Branch when they saw Shri Uike present. The witness says that on seeing them the workman closed the door of the

Branch whercupon—they knocked on the door and asked shri Uike to open it in reply to which he i.e, workman asked them to go away and further threatened that he would shoot them. According to the witness the wat hman is permitted to have a Gun because his name is shown as retainer in the Gun Licence of the Bank and he was also permitted to carry live cartridges. Shri Paigan therefore was sent to the Police Station for lodging complaint and although an attempt was made to contact the Regional Manager the said attempt failed as they could not get connections.

5. The Branch Manager then says that on 3-12-1981 at about 6.30 or 7.00 P.M. the Messenger in the service of the Bank arrived at his residence and told that Shri Uike accompanied by a lady had visited the Branch and he (Uike) entrusted to the Messenger on application after having exchange of words. It was reported that no Watchman was present on duty in the Branch. The Branch Manager therefore immediately rushed to the Bank and at that time he was accompanied by S/Shri Padnavi and others who were also serving in the same branch. The Badli Watchman Paighan when called for arrived and at about the same time the workman accompanied by a female arrived on the scene and he i.e. the workman told that he had submitted an application for leave and asked the Branch Manager whether he was not sanctioning the same. It is further stated that the workman expressed that the Branch Manager cannot do anything ill to him i.e. Shri Uike but against that he i.e. Watchman would beat the witness with shoes at the hands of a female. Those persons who were present persuaded the workman to leave the place and accordingly he left the place with his female companion. The Police protection was therefore sought and was given.

- 6. Shri Ramesh Vishnupant Madhikar also speaks of these incidents and says that on 22-11-1981 on arrival at the Branch in the company of the Branch Manager when the workman was asked to open the door which he had closed on seeing the Branch Manager and others, he threatened that he would shoot them. He further says that 15 or 20 days thereafter his son informed him of commotion in front of the Branch and to see what was the matter he went there when he found the Branch Manager present and when asked, the witness was informed by him that Shri Uike had threatened saying that he should sanction leave and that Branch Manager cannot do anything ill to him against which the Watchman can beat him in the Bazar at the hands of a female.
- 7. I have gone through the evidence of these witnesses who are responsible Bank Officers and I am convinced that what they stated must be true. An attempt was made to suggest that they are biased against the workman but I do not find any force in the same. The record shows, the matter reported to the Police and they had taken action although no charge-sheet could be lodged because steps were not taken by the Police in the prescribed time. Yet there is absolutely no reason to disbelieve these witness when they say that on the first day the workman threatened to shoot them which he could very easily have done because he kept a fire arm and on subsequent day he had threatened to beat the Branch Manager in the Bazar. It is pertinent to note that although there was this evidence on record before the Tribunal, the workman who is denying the charge never stepped into the witness box. I have carefully gone through the evidence as it stands and I am convinced that even under the S.B.I. Group instructions the Branch Manager was entitled to visit the Branch outside office hours and he has justified in trying to go there in order to see what was the matter. The attempt therefore to suggest that even the Branch Manager could not have entered the Branch and if the Watchman had threatened to shoot there was nothing illegal, must fail. Under the S.B.I. group instructions paragraph 56(vii) and (ix) nobody can order the bank premises outside office hours without the agent's permission meaning thereby that agent himself can visit the branch, which is also evident from sub-para (ix) which easts a duty on the agent or other supervisory officials to inspect the Guard at irregular intervals to see that proper watch is being maintained. The Branch Manager therefore when an untoward, incident was reported had every right to visit the Branch and varify the facts and the workman by threatening to shoot him or to beat him must be held to be guilty of gross-misconduct as per para 521(4)(b) and (e) of the Sastri Award.

8. Once we arrive at this conclusion the next question is whether the order of discharge is harsh and disproportionate. It is already noticed that the workman was armed with a fire arm under a licence in the name of the Bank, he being a retainer and when he was threatening to shoot, it is really good luck of the Branch Manager that the intention was not coverted into action. Such threatening whether to shoot or beat in the Bazar that too on the premises of the Bank where the Agent or the Branch Manager had every right to go, can never be countenanced and if the Bank has decided to discharge such a Watchman from service, I do not think that such action of the Bank was harsh and the punishment disproportionate. I therefore hold that the order of discharge passed against the workman terminating his service was fully justified and calls for no interference.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer. [No. L-12012[201]84-D.II(A)]

नर्द दिस्ली, 29 अगस्त, 1985

का. अ. 3172--- श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारो, भारतीय स्टेट बैंक के प्रवंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अमुबध में निर्दिण्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-8-8-5 की प्राप्त हुआ था।

### New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4172.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act ,1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relative to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/33 of 1985

PARTIES:

Employers in relation to the management of State Bank of India, Nagpur

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

I or the Employers—1. Shri A. K. Ramani, Assistant Law Officer 2. Shri A. E. Kulkarni, Officer M.M.G. Sc. II, Regional Office, Nagpur.

For the Workmen—Shri S. D. Phadke, President, SBI and S. B. Employees' Union, Nagpur.

INDUSTRY: Banking STATE: Maharashtra

Bombay, the 1st August, 1985

AWARD

By their Order No. L-12012/200/84-D.II (A) dated 12-3-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947:—

"Whether the action of the management of State Bank of India Region III, Nagpur in terminating the services of Shri B. M. Godhane from 24-6-83 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

- 2. The order of discharge passed against the workman Shii B. M. Godhane, a Driver in the service of the State Bank of India was a result of chargesheet indicating the workman firstly that on 7-8-1981 while returning from Chandur Bazar on official duty the workman had driven the Bank's vehicle at a high speed prejudicial to the interest of the jeep and its occupants due to his consuming alcohol and knocked down two persons and also caused damage to Bank's jeep and secondly that he i.e. the workman had also unauthorisedly allowed an outsider to occupy the Bank's jeep while returning from Chandur Bazar. An enquiry was held on these charges and ultimately the Enquiry Officer on going through the evidence adduced before him held that the workman was negligent in his duty and caused damage to jeep No. M.H.R. 4757 and that while driving the vehicle the workman was under influence of alcohol. So far as the second charge was concerned he held that the same is not proved. Similarly part of the first charge of knocking down two persons while driving the vehicle. The Enquiry Officer's finding dated 1-12-1982 culminated in the order of discharge passed by the Regional Manager-cum-Disciplinary Authority dated 15-6-1983, being aggrieved of which the workman had preferred an appeal to the Chief Regional Manager but by his order dated 30-9-1983 the appellate Authority refused to interfere in the order and rejected the appeal. Ultimately this led to the present reference.
- 3. The parties had filed respectively the statement of claim and written statement whereby on one hand the workman challenges the validity of the enquiry agaist which the management re-affirmed the same but on hearing the parties by Award Part I dated 1-5-1985 the enquiry was held vitiated and therefore cannot be said to be valid, yet as there was a request of the Bank to allow them to prove the misconduct before the Tribunal an opportunity was given and the matter was heard.
- 4. During the course of subsequent hearing there is evidence of Shri A. R. Oka, Cashier in the service of M/s. Gadre Motors, Amravati, MW-1, Shri S. D. Deogongkar, the then Branch Manager of Amravati Branch in whose disposal the jeep was placed at the relevant time. MW-2 and lastly the evidence of Shri L. B. Gadre, Senior partner in Gadre Motors at Amravati. The workman chose not to adduce any evidence either of himself or of any witness.
- 5. Since an opportunity has been given to the bank to establish the misconduct the question which arose for determination at this stage and my findings thereon are:—

Issues Findings

1. Whether the misconducts as alleged are proved?

No

2. If yes whether the punishment as awarded is harsh and disproportionate?

Does not arise

3. Is the action of the management in discharging the workman justified?

Not justified

4. What award?

As per award.

## REASONS

6. We have already seen that the charge against the workman is that he had driven the vehicle while under the influence of alcohol, was negligent in his duty and caused damage to the jeep. So far as the remaining part of charge No. 1 and the entire charge No. 2 were concerned the enquiry officer himself held them to be not proved, therefore there was no question of their proving before the Tribunal nor there is any evidence led during the enquiry here. The question naturally would be whether there is material to hold that at the relevant time the Driver i.e. the workman concerned was under influence of alcohol and further was negligent in his duties as a result of which the Bank had suffered great loss.

- 7. That the vehicle met with an accident and that for carrying out the repairs to the vehicle the Bank had spent Rs. 10,511.85 has been proved by the evidence of Shri Gadre proprietor of Gadre Motors, Amravati and his employee Shri Oka who prepared the bills and works as Cashier. Although there was an attempt made to suggest that the bill was an inflated bill and that the vehicle might not have been damaged to this extent as tried to be projected the evidence of these two witnesses especially the proprietor of Garage disproves the said suggestion. I conclude relying on this evidence and further relying on the evidence of the Branch Manager that on the relevant date i.e. 7-8-1981 the vehicle had met with an accident while it was being driven by the workman who was in the service of the Bank as a Diver and that for carrying out the repairs the Bank had to incur an expense of Rs. 10,000 and odd.
- 8. This however cannot conclude the matter and unless there is sufficient evidence to establish the alleged part played by the workman, conclusion of proof of misconduct would not be justified. We have already seen the charges levelled against the workman which are stated to be gross-misconduct. Under the Sastri Award Para 521(4)(c) drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour on the premises of the bank is one of the gross-misconduct so also under sub-clause (j) gross negligence or negligence involving or likely to involve the bank in serious loss is another gross misconduct for which the workmen can be discharged or dismissed.
- 9. Firstly it was urged that the Driver was guilty of drunkenness and while he was under influence of alcohol he drove the vehicle and caused the accident. Now if we go to the list of gross-misconduct as contemplated by para 521 (4)(c) of the Sastri Award it is evident that drunkenness or disorderly behaviour has to be on the premises of the Bank while in the instant case the accident admittedly occured not on the bank premises but far away from the said place on the public road. In M/s. Glaxo Laboratories (I) Ltd. case reported in (1984) 1 Supreme Court cases 1 while considering the relevant clause in the Standing Orders of the company where drunkenness committed within the premises of the establishment or in the vicinity thereof it was held that to be a misconduct. The misconduct must have connection with the place of work and the employer has no extraterritorial jurisdiction. No doubt it is true that being in-charge of the vehicle as Driver it was the duty of the workman to drive the jeen and it is necessarily in public places or on highways but this cannot mean that he was for the said purpose on the premises of the Bank. Therefore assuming that there is evidence of drunkenness, when sub-clause (4)(c) requires drunkenness on the premises of the bank, before a workman is held guilty for that misconduct. that charge cannot be said to have been substantiated.
- 10. But still the question would be whether drunkenness has been established. Since the enquiry is held vitiated and therefore opportunity was given to the bank to establish or substantiate the charge, whatever ingredient of the charge is to be established the bank has to establish it by cogent evidence in support thereof. Since drunkenness or being under influence of alcohol would require the word of medical expert who would speak authoritatively on the said point, the word of Medical Officer who is alleged to have examined the Driver immediately on his arrest was essential which the Bank failed to adduce. In the absence thereof the bank is relying upon the evidence of the Branch Manager, Ex. MW-2 who in examination in chief stated that on 7-8-1981 when the Driver returned to the Branch with the vehicle he found him to be under influence of alcohol and he had bruises on his The Branch Manager even if held to be expert in the bank affairs cannot be an expert in medical science unless he proves to be so and therefore his word that he found the workman under influence of alcohol would be nothing but a word of layman having no evidential value. No conclusion therefore is possible on the strength of his statement that the Driver was drunk or that he was under influence of pleohol. He even found the workman smelling of Alcohol but this would not lead to any conclusion one way or other in the absence of direct evidence.
- 11. In the written arguments the Bank is also relying upon para 521(4)(d) of the Sastri Award which says that

wilful damage or attempt to cause damage to the property of the Bank would amount to gross misconduct. It is important to note that the chargesheet does not speak of any wilful damage nor there is evidence to show that the workman deliberately caused damage to the vehicle the property of the bank. Reliance therefore on para 521(4)(d) of the Sastri Award at this stage in the first place would not be permissible and particularly in the absence of any evidence. The question then is whether the workman was guilty of gross misconduct of negligence involving or likely to involve the bank in serious loss in other words is he guilty of misconduct as defined in clause (j) sub-clause (c) of para 521 of the Sastri Award. For the said purpose the bank is placing reliance of proof of damage whereby the bank had incurred expense of Rs. 10,511.85 for carrying out the repairs to the vehicle and also on the maxim res ipsa loquitur. So far as the damage to the vehicle is concerned. there is absolutely no reason to disbelieve the statements of three witnesses of management including Shri Gadre and the bill's submitted and the payments received by him. This shows that on the relevant date i.e. on 7-8-1981 while the vehicle was moving from Chandur to Amravati it met with a scrious accident and that at the relevant time the workman was driving the vehicle. The Magistrate who heard the criminal case against the workman even went to the length of holding absence of proof of vehicle being driven by the workman but the fact that he was driving the vehicle at the relevant time is not denied before the Tribunal. However, merely because the vehicle suffered severe damage would not automatically lead to any inference of negligence or rash and negligent driving. There is no evidence barring the proof of damage suggesting any rash or negligent driving on the part of the Driver and in my view when there is no such proof the management cannot invoke maxim res ipsa loquitur. Had there been some proof in this regard like the evidence of eye witnesses, the failure of the workman to step in the witness box might have been a circumstance appearing against him but when there is absolutely no evidence attributing negligence to him, failure of the workman to appear before the Tribunal cannot be a proof of his act. The record shows that the vehicle met with the accident on the highway where the speed as admitted by Shri Gadre of 50-60 Km, per hour cannot be said to be excessive but would be normal speed. If the vehicle was being driven assuming at this speed met with an accident the damage as seen is likely to result but in the absence of any other material on record it would not lead to any conclusion of rashness or negligent driving. Shri Gadre has admitted that the vehicle is kent on low gear while climbing a gradient and if the vehicle dashes against any object major damage is likely to be resulted. In the appeal Memo as well as during the enquiry the plea of the workman was because it was raining the road had become slippery and while trying to avoid a bullock which had suddenly run on the road the vehicle turned turtle. There is nothing to disprove this statement and if the workman is to be dismissed or discharged on the ground of gross negligence the burden cannot be thrown on the workman but some evidence would be necessary on behalf of the management rebuttal for which the workman would be responsible. However as already stated there is absolutely no evidence except the proof of damage but by itself it would not lead to proof of ingredients as incorporated in the chargesheet,

12. The result is that drunkenness or being under influence of alcohol is not established nor it is established that the workman was grossly negligent nor that as a result of this gross negligence the Bank suffered heavy loss. The net result therefore would be that no ingredient of the charge is proved and so the order of discharge can never be said to be instified. The Bank is therefore directed to reinstate the workman forthwith. Treating the period from the date of suspension till the date of award as that of period of suspension the Bank shall make payment.

Award accordingly,

M. A. DPSHPANDE, Presiding Officer[No. L-12012/200/84-D.II (A)]K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

## नई दिल्ली, 19 ग्रगस्त, 1985

ार-प्रा०७173.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (सघ के शासक्तिय प्रयोजनी के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के ग्रन सरण में निम्नलिखित कार्यालया को, जिनमे कर्मचारियों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमुचित करती है, अर्थात् :---

- 1. सहायक श्रम श्रायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, पूर्णे।
- 2. महायक श्रम श्रायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नागपुर।
- 3. महायक श्रम ग्रायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, चन्त्रपुर।
- महायक श्रम श्रायक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, वास्को ।
- 5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) का भमाचल ।
- 6. श्रम प्रवर्तन ग्रधिकारी (केन्द्रीय) का कार्यालय, सांगली ।
- श्रम प्रवर्तनः श्रिधकारी (केन्द्रीय) का कार्यालयः फोंडा, गोवा।

[मंख्या ई-11017/2/85-सी एल टी] भवानी सिंह मीना, उप सचिव

New Delhi, the 19th August, 1985

S.O. 4173.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi, namely :---

- 1. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Poona.
- 2. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Nagpur.
- 3. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Chanderpur.
- 4. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Baseo.
- 5. Labour Enforcement Officer (Central)'s Office, Bhusa-
- 6. Labour Enforcement Officer (Central)'s Office, Sangli.
- .7. Labour Enforcement Officer (Central)'s Office, Phonda GOA.

[F. No. E-11017/2/85-C.L.T.] B. S. MEENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 श्रगस्त, 1985 ·

का०ग्रा०4174.--औद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के श्रन्सरण में, केन्द्रीय सरकार पी एण्ड टी सीनियर सुपरिटेंडे न्टं श्राफ पोस्ट श्रिफेसेज भ्रागरा के प्रशंधनंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच भ्रनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक श्रधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 ग्रगस्त, 1985 को प्राप्त हमाधा।

## New Delhi, the 20th August, 1985

S.O. 4174.—In persuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal. New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of P and T through Senior Supdt. of Post Offices Agra, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th August, 1985.

# BEFORE SHRI O. P. SINGLA. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVFRNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. NEW DELHI

I. D. No. 72/84

In the matter of dispute between:

Shri Surendra Kumar Srivastava S/o Shri Ravindra Pal Srivastava 14/219 Mani Sayced Khan, Agra.

#### Versus

Senior Superintendent of Post Offices, Agra Circle, Agra.

APPEARANCES:

Shri R. D. Aggarwal—for the Management, None-for the workman.

#### AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 31-10-84 vide Order No. L-40012(9)/84-D.II (B) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:

- "Whether the action of the Senior Superintendent of Post Offices Agra Circle, Agra in terminating the services of Shri Surendra Kumar Srivastava, Wireman, Agra Fort, Head Post Office with effect from 2-1-82 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"
- 2. Notices were sent to the parties and the claimant appeared on 20-4-85 and sought a date for filing claim statement which was allowed to him for 18-5-85 but thereafter he became absent and has not appeared despite notice sent to him by registered post. He has been proceeded against exparte.
- 3 The Management explained that the workman S. K. Srivastava was engaged as outsider C. P. Wireman vice Raghubir Singh who had resigned from the post w.e.f. 24-8-79 purely on daily wages and was paid from contingencies and he was never sponsored by Employment Exchange nor were names called from Employment Exchange.
- 4. There was a complaint about the Tube Well not functioning and the motor had gone out of order and a preliminary enquiry was made believing S. K. Srivastava to be at fault and the Department incurring loss of Rs. 425 for repairs of the motor. Ultimately the Management did not employ him further after 2-1-82.
- 5. In the circumstances aforesaid, the workman does not seem to have had any regular post being employed on contingency without names being called from Employment Exchange in a Government Department and, therefore, prima facie does not have a case for interference by this Tribunal and the Management action prima facic does not appear to he unjustified and the Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

Dated : August 5, 1985,

O. P. SINGLA, Presiding Officer [No. L-40012(9) /84-D.II (B)] HARI SINGH, Desk Officer

## नई विल्ली, 26 अगस्त, 1985

का. भा. 4175—अधिविक विकास अधिविसम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अनुसरण में केन्द्राय सरकार, कैन्टोमेन्ट बोर्ड, आगरा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के क्षांच, अनुवंध में निविष्ट आंधोगिक विवाद में केन्द्राय सरकार आंधोगिक अधिवारण, पानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्राय सरकार को 12 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था।

#### New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4175.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantt. Board, Agra and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1985.

#### BEFORE SHRI R, B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

#### I.D. No. 218|83

In the matter of dispute between:

The General Secretary, Cantonment Board Employees Union (INTUC), 2/236 Namnair-Agra.

#### AND

The Executive Officer, Cantonment Board, Agra.

#### APPEARANCES:

Shri Surendra Singh—for the workman & Shri M. P. Khanna—for the management.

#### AWARD

- 1. The Central Government, Ministry of Labour vide its notification No. L-13011|3|82-D.II(B) dated 15-7-83 has referred the following dispute for adjudication;
  - "Whether the action of the management of Cantonment Board Agra in not absorbing their daily wages employees and granting them the benefits of permanent employees is fair, just and legal ? If not, to what relief the workmen concerned entitled?"
- 2. On the first hearing one Shri N. Anandan as Secretary Cantonment Board Employees Union Agra moved an application that the parties are negotiating settlement which will be filed carliest under way and so adjournment be granted, and thus the court granted adjournment and the parties reached on settlement which settlement is signed by President, Secretary of the Employees Union Cantonment Board Agra and the Cantonment Executive Officer on behalf of the cantonment Employer Agra. Agreement filed annexure B that the cantonment board will re-appoint 17 retrenchment daily rated workers in the following manner that first six will be absorbed in 6 posts and another six will be appointed in Head F-9 after receipt of the sanction and they will continue to year to year basis and remaining 5 persons will be appointed in regular scale for 4 months. On the basis of this agreement an award was sent by my learned predecessor on 9th September, 83 for publication, but mean while Shri Surender Singh General Secretary INTUC moved an application that the award was obtained on the basis of false statement and the office bearers of the ur on mentioned therein were no more office bearers of the employees union Agra and that the reference was of a general nature and not recading 17 workers. It was requested that the award he set aside. A notice was issued to the management but none appeared. On the evidence given by union representative Shri Surender Singh, the court ordered that the award made by Tribinal on 9-9-83 is set aside and the proceeding will be continued in this industrial dispute 698 GTIR5--9.

and the workman may lead his evidence in support of his contention. This order is dated 14th May, 84 and is record. There was again a contest between rival unions alleging that the review application be rejected and award dated 9-9-83 be sent for publication. In the end the management moved an application on 8-4-85 alongwith photo copy received from the government stating that subsequent to the reference made and during the pendency of the case the Ministry of Defence. Government of India has issued an order dated 28-2-85, photocopy of which file) and that order dated in view of this order the dispute raised by employees as per reference order dated 7-9-83 is stand reserved and the reference becomes infructous now, consequently the adjudication proceedings too are not proper. The government order shows that in relaxation of rule 5(B)(i) of the Cantt Fund Servants Rule 1947, I am directed to convey the sanction of the president to the regularisation of the canntt board employees w.e.f. from the date shown against each in annex-ure (i) and (ii) to this letter The annexure includes 16 names and it contains list of 16 persons including that of Shri Usman, Ayoob and Ashok Kumar their designation is also mentioned and different dates of appoint against them are mentioned. On 23-4-85, the mangement and workman's representative agreed that the award be given in terms of government letter submitted by the employer.

- 3. I accordingly give my award in terms of the letter of the Ministry of Defence. Government of India giving 16 daily wages casual employees regular appointment with the dates mentioned against them in permaneut vacancies and also on the post mentioned as their designation.
  - 4. I, therefore give my award accordingly.
- 5. Let 6 copies of the award be sent to the government for publication.

Dated: 2nd August, 1985

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer, [No. L-13011(3)|82-D.II(B)]

((10, 3) 15011(5)(62 15.1

## मई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का. आ.4176 — औशोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एयर इन्डिया के प्रश्नंत्रनंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, बस्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है।

## New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4176.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1. Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workmen.

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

Reference No. CGIT-3 of 1984

#### PARTIES:

Employers in relation to Air-India, Nariman Point.

#### AND

#### Their workmen

#### APPEARANCES:

For the workmen-Mr. Dighe, representative

For the employer—Mr. Verma, Advocate.

INDUSTRY: Airlines STATE: Maharashtra

Bombay, dated the 21st day of June, 1985

#### AWARD

This is a reference relating to the action of the management of Air-India in respect of 34 casual workmen whose names are listed in the schedule. The issue referred is whether the action of the management "in not reinstating the 34 casual workers" is justified and "if not, to what relief the workmen are entitled?" I will briefly refer to the statement of claim and the written statement filed by the employees and the employer.

- 2. It is common ground that the action in question was taken on 18th January, 1982, meaning thereby that these workmen who were previously employed as casual workmen were not employed again. The contention of the workmen is that this action amounts to retrenchment of these workmen, without following rules laid down for the purposes of retrenchment, without assigning any reason, without notice and without paying retrenchment compensation. The claim statement, therefore, in short is that these 34 workmen were retrenched on 18th January. 1982 without showing any reason and without notice and without payment of retrenchment compensation. Their non-continuation of service amounts to dismissal without payment of retrenchment compensation and therefore, bad in faw, the workmen having acquired the status of continuos workmen within the meaning of Section 25(f).
- 3. The management's contention is that the workmen were engaged as casual labourers and were not workmen within the purview of the Air-India Employees Service Regulations. As they were casual employees, there was no question of termination and there was no contract of employment between them. Hence, according to the employer, the demand for reinstatement is illegal. In other words, according to the employer, the scheduled workmen were not workmen at all and were only casual workmen engaged as and when required and necessary. They can not be deemed to have acquired the status of continuous employees, so as attract the provisions of Section 25(f) of the Industrial Disputes Act. It denied that these workmen were retrenched or can be called to be retrenched. According to the Service Regulations of the Air-India employees, there are certain categories of workmen, such as permanent, temporary, pro-bationers and substitutes. There is no category of casual workmen as contemplated by the regulations, and therefore. it is contended that there was no employer-employee re-lationship between the Cornoration and these employees. Therefore, they are not entitled to any retrenchment com-nensation or notice pay. The Corporation also denied that these scheduled workmen had put in 240 days in a year. Their employment is on a day-to-day basis and is not of a continuous nature. Their employment depends upon the exigencies of work and is not for work which is of a permanent nature. The workmen are of unspecified categories.
- 4. Besides, these contention, it is the also the contention of the Corporation that "there is no industrial dispute as defined under section 2(k) of Industrial Disputes Act. 1947" existing between the Corporation and its workmen and the Reference as such is bad in law and not maintainable. At the time of the arguments, it was however contended that what the Corporation means is that there is no dispute between its 20,000 workmen who are represented by its 20 unions and the management. The 34 workmen whose case was espoused by the present union, called Airlines Employees Union, does not have any membership amongst the Corporation's what may be said to be accredited workmen, and therefore is not entitled to raise the present dispute. I have already referred to the other contentions that the scheduled employees are not its workers. Therefore, it was ureed for both the reasons, namely, that the scheduled workmen are not workers and the representative union is not a representative union and has no membership amongst the accredited workmen and therefore the reference is not maintainable.
- 5. As regards this last contention, it must be mentioned that with regard to the question whether the Airlines Employees Union has no representation amongst the existing

- or accredited workmen of Air-India is a question of fact. The Corporation has not raised it in its written statement and therefore, the union could not have been called upon to answer. Nor is it a question which can be gone into as a purely legal question. The question whether the concerned union has a membership among other workmen is a question of fact. This factual foundation must be laid before any legal argument can be raised thereon. This contention therefore, can not be considered. What remains therefore is the only question with regard to these 34 workmen and whether the action in their behalf is justified or otherwise.
- 6. The matter was first argued in part on 17th of December, 1984 and an order came to be passed on that date. According to the workmen, these workmen were employed from 1977 onwards, though there was no evidence whatsoever to show that they had completed 240 days in a year or that they were employed from 1977. For the employer, it was stated that these were casual workmen not borne in any muster roll nor any pay-sheets were maintained for them. They were paid on vouchers. In that view, the employer was directed to produce vouchers; vouchers relating to each workmen showing the dates on which he worked and for which he was paid during the years 1977 to 1982. Subsequently, another order was passed on the 20th of January 1985 which would go to show that the employees were directed to file a statement "showing which of the workman was working continuously or was working discontinuously for which period and months year by year." The parties took time either to produce vouchers or to produce records and ultimately on behalf of the corporation, the learned counsel on 15th April, 1985 states that pay-sheets for the year 1981-82 are only available. Earlier pay-sheets are not available. That for the concerned work-men, all the pay-sheets which were available are produced and that no other document can be produced or are available. The union was, therefore, directed to inspect these vouchers and see whether the signatures of the concerned workmen are correct and theirs and whether they were paid accordingly and then file a statement. Another order came to be passed on 30th of April 1985, by which the Corporation was directed to produce muster rolls, if any and the nay-sheets for 12 months of 1981-82. In view of the fact that earlier records were not available that is more relevant order. Thereafter, inspection was allowed and taken by the union representatives of the record which was available with the Air-India. The union then produced on 12th of June, 1985, a statement showing the number of days the workmen have worked in between the period 19th January, 1981 to 18th of January, 1982. Which is the period which has to be taken into account for purposes of Section 25(f) and Section 25(b) of the Industrial Disputes Act. That is with annexure-A to the application of that date.
- 7. Of the 34 scheduled workmen, it is common ground that S. P. Jadhav at Sl. No. 18 and N.A. Karkera at Sl. No. 24 are no more concerned with the dispute. They have already been appointed and regularly employed by the Air-India Corporation and their case is not pressed. At a later stage, the union also gave up its claim with regard to 13 more workmen and confined its case only to 21 persons whose names are mentioned in the annexure to the application dated 12th June, 1985. Thus, it is the case of these 21 workmen alone which now survives for consideration.
- 8. The matter was posted for evidence and evidence was to be recorded today, when a statement was made by the employers and the employees to the effect that out of the statement filed by the union, six people at Sl. No. 9. 10, 12, 17, 19 and 21 have even according to the Corporation completed 240 days in a year preceding 18th Innuary 1982. The Corporation conceded therefore, that their claim falls within S. 25(b).
- 9. It was contended for the Cornoration that Sl. No. 13, 14 and 18 in the Annexure A. do not figure in the schedule of reference. That position is not disputed. There is no dispute that the name of some T.W. Bansode at Sl. No. 18 in annexure A to the application dated 12th June. 1984 does not figure at all amongst the names appointed to the reference in Schedule. So far as the other two are concerned, who are at Sl. No. 13 and 14 in the Annexure-A, their names are given as 'O.M. Sawant' and 'S. P. Kosole' in the schedule to the reference. The union contends that there is a mistake

in printing or typing, and persons at Sl. No. 30 and 32 are D. M. Sawant and S. V. Kasole and are the same persons. Its further contention is that I should make an order with regard to D M. Sawant and S. V. Kasole also, as they worked for 240 days in a year prior to 1982. I am afraid that this contention can not be accepted. I have no power to substitute in place of O.M. Sawant one D. M. Sawant and in place of S. P. Kasole, one S. V. Kasole, If correct names are not given in the order of reference and the Schedule, it was for the union to get the schedule amended by suitable action. As long as the schedule remains ag it is, I have to treat the concerned workmen as O. M. Sawant and S. P. Kasole which do not figure in the statement at annexure-A. Threfore, the cases of workmen at Sl. No. 30 and 32 in the schedule of reference will also have to be droppped. That leaves the case of 4 more workmen only.

- 10. It is contended for the union that 10 workmen in annexure-A at Sl. No. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20 and 21 have completed 240 days of working and therefore are entitled to protection under Section 25(f), 25(b) and Section 2(00) of Industrial Disputes Act. Of these, as I have already pointed out, it is admitted by the Corporation that persons at Sl. No. 9, 10, 12, 17, 19 and 21 have completed 240 days. Therefore what remains to be examined is the cases of workmen at Sl. No. 3, 5, 7 and 20 of the Annexure, for consideration as to whether they have completed 240 days.
- 11. A reference in this connection may be made to Section 25(B) which defines what is mean by continuous service. Of this sub-section, clause (2)(a) with which we are concerned reads as under:
  - "(2) Where a workmen is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous under an employer—
    - (a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—
      - (i) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below ground in mine; and
  - (ii) two hundred and forty days, in any other case."
- 12. It is clear therefore, that what has to be seen is the number of days these workmen had actually worked in a period "of 12 calendar months preceding the date" with reference to which this perod has to be counted. As the date in this case is 18th of January, 1982, preceding 12 calendar months will have to be taken into account and considered. According to Mr. Verma, learned counsel for the Corporation the calculation made by the union is for 13 months, since it took January, 1981 to January, 1982 into account. That seems to be as a result of misreading. What has been done perhaps and it was also clarified during the arguments, that the period was calculated from 18th January, 1982 backwards up to 19th January, 1981. The heading of the statement clearly goes to say that what has been taken into account is the period from 19-1-1981 to 18-1-1982. This statement is not disputed so far as its correctness is concerned and that could not have been disputed as it is a compilation from the Corporation's own record. In the circumstances, Mr. Verma learned counsel for the Corporation, subject to his contention, which I shall presently refer admits that these persons also completed 240 days, if the period accounted is from 19-1-1981 to 18-1-1982.
- 13. The learned counsel for the Corporation contended that the term 12 calendar months preceding the date has to be considered as 365 days. According to him, that contention finds support in certain settled judicial decisions. He was however, not able to cite any immediately. However, I find that the period considered for purposes of operation of Section 25(b) according to the Supreme Court is 12 calendar months, as held in Sur Enamal and Stamping Works Ltd. v. Their workmen (1963-II LLJ p. 367). The normal and natural meaning of the expression '12 calendar months preceding the date' would mean really the 12 calendar months which had preceded the date in question and the month in

- which that date tails, will have to be left out. By way of illustration for the present case, in my view the month of January may have to be left out and the period calculated from 1st January, 1981 to 31st December, 1981 which are the 12 preceding calendar months. In that view of the matter the case of these workmen would still become stronger. In view, however of the fact that the completion of 240 days it is stated to be from 19th January, 1981 uselt, calculating 365 days prior to 19th January, 1982, and is not disputed it seems to me clear that these three workmen are also entitled to benefit of Section 25(f).
- 14. Now, section 25(f) lays down that "no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
  - (a) the workman has been given one months' notice in writing indicating the reason for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:"
    - Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifics a date for the termination of service;
  - (b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and
  - (c) Notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette,"
- 15. I have already held that these 10 workmen have already completed service for a period of one year. As mentioned in Section 25(f) read with Section 25(b), their termination would be deemed to be retrenchment. It is common ground that they have not been given notice or notice wages or any retrenchment compensation. Therefore, retrenchment or termination of service, of them is bad in law. Section 2(00) defines what is a retrenchment and means "the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action..." The termination of the employees' services or discontinuation which amounts to Retrenchment, attracts the provisions of the three sections, i.e. Section 2(00) Section 25(b) and Section 25(f). The retrenchment/termination is bad in law and the employees are entitled to be reinstated. Hence the Award. The ten employees whose names follow as annexure to this Award shall be reinstated within one month from the publication of the award.
- 16. The employees would be normally entitled to backwages from the date of termination. Unfortunately, the statement of claim has not made any claim in that behalf. As the issue has not been joined in the absence of a claim, it would not have been possible for the employers to show that the workmen were not employed during all these days or that they gainfully employed. In the absence of either of the contention in the written statement and in the absence of anything in evidence. I would not grant them any back wages, but grant them only a lumpsum compensation of an amount of Rs. 2,000 per person.
- 17. Award accordingly that workmen at Sr. No. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21 in annexure-A to application dated 12th June, 1985 (Sr. No. 6, 9, 15, 25, 27, 29, 22, 11, 26, 12 in the schedule) are directed to be reinstated within one month from the date of the publication of the award. The corporation is also directed to pay them a sum of Rs. 2,000 each.

ANNEXURE						
SI. No.	Name of the workmen	Sl. No. in the annexure-A to the application of union dt. 12-6-1984	Sl. No. in the schedule of reference order			
1.	A.J. Sable	3	6			
2.	V.J. Raul	5	9			
3.	B.K. Moro	. 7	15			
4.	C.B. Donde	9	25			
5.	K.D. Pawar	10	27			
6.	V. J. Das	12	29			
7.	T.G. Savardokar	17	22			
8.	S.T. Satam	19	11			
9.	D.N. Ghadi	20	26			
10.	P.B. Kahor	21	12			

R. D. TULPULE, Presiding Officer
[No. L-11011(2)]83-D.II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer.

## नई दिल्ली, 21 श्रगस्त, 1985

का०ग्रा०4177—मैसर्स जय श्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लाल द्वारा बिल्डिंग न्यू लिंक रोड, स्वामी राम सीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055 (डी० एल/2819) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध श्रधिनियम, 1952) (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रधीन छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भ्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन बीमा जीवन के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक भ्रनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीय, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के भ्रधीन उन्हें भ्रनुक्रेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के श्रधान रहते हुए उक्त स्थापन कोतीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेसी हैं।

## **अनुसूची**

1. जक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ग्रस्तांन लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रभियम का संदाय, लेखाओं का भौतरण, निरीक्षण प्रमारों संदाय श्रादि की हैं, होने बाले सभी ध्ययों का बहुन नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियं कक, केन्द्रं य सरकार द्वारा भ्रम्मोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति भौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मजारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसक. मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचार, जो कर्मचार: भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के प्रधान छूट प्राप्त किया स्थापन का भविष्य निधि का पा पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहिक बामा स्काम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरस्त वर्ण करेगा भीर उसका बाबत श्रावश्यक प्रमियम भारत्य जावन बामा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कंम के ग्रष्ठम कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ामें आते हैं तो नियंजक सामृहिक बीमा स्कम के ग्रष्ठन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समृजित रूप से वृद्धि की जाने क व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बामा स्कम के ग्रष्ठान उपलब्ध कायदे उन कायदों से मिधक भनुकूल हों, जो उक्त स्कम के ग्रष्ठान भनुजीय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कं.म में किसं बात के होते हुए भी, यि किसं। कर्मचिरा का मृत्यु पर इस स्क.म के मर्घान संदेय रकम उस रकम में क्य है ती कर्नेत्रारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के घ्रधन होता तो नियोजक कर्मचार के विधिक वारिस/नाम निर्देशिता की प्रतिकर रूप में दोनों रकमों के घ्रवनर के बरावर रकम का संवाय करेगा।
- 8, सामृहिक बंमा स्काम के उपबंधों मे कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा भौर जहां किसा संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक संविष्य निधि प्रायुक्त प्रपना अनुभोदन देने से पूर्व करने का युक्तिग्रह अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिग्रह अवसर देगा ।
- 9. यदि किसा कारणवण, स्थापन के कर्मचारा, भारत य जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बामा स्काम के, जिसे स्थापन पहले अपमा चुका है, अधान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसा रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह का जा सकता है ।
- 10. यदि किसी कारणवरा, नियोजक उस नियत तारोच के घीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निर्मम नियत करें, प्रामियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसा को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11- नियोजक द्वारा प्रांमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम को दमा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक धारिसों की जो यदि यह कूट न दो गई होता तो उक्त स्काम के भ्रंतर्गत होते, बामा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व कियोजक पर होगा।

12. इस स्क.म के अधान भान गाने किसा सबस्य का मृत्यु होने पर भारताय आंवन बामा निगम, ब माइत राधा के हकदार नाम निर्देशित/विविध शारिस को उस राधा का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दथा में हर प्रकार में पूर्ण यांव की प्राप्त के एक मास क मातर सुनिश्चित करेगा।

[सं० रस-3501/164/85 एस० एस० 4]

New Delhi, the 21st August, 1985

S.O. 4177.—Whereas Messrs Jay Shree Tea and Industries Lunned, Lal Dward Building, New Link Road, Swami Rain Thath Nagar, New Delhi-110055 (DL/2819) (herematier referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benents under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinatter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal help/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insulance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(184)]85-SS.TV]

का. था. 4178.— मैसर्स महाराष्ट्र एपेक्स कारपोरेशन लिमिटेड, सिण्डिकेट हाऊस, पी॰ बाक्स नं० 38, मनीपाल-576119, कर्नाटक (कर्नाटक/4470 (जिसे इसमें इसके पश्चास् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मेचारी भिवष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रिधिनयम कहा गया है) की घारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट दिए जाने के लिए धावेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उसत स्थापन के कर्मचारी, किसी पूथक अधिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुहोय हैं;

ग्रत: केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्राधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त गावितयों का प्रयोग करते हुए ग्रीर इससे उपावद ग्रानुसूची में विनिर्दिष्ट गर्तों के प्रधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की ग्रावधि के लिए उक्त स्काम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से खूट देती है।

#### **बन्**सूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरिणयां भेजेगा भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त भ्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के भ्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकाशन में, जिसके शंतर्गत लेखाओं का रखा जाना,विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का पंतरण, निरोक्षण प्रभारों/संदाय ग्रांदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएका।

- 4 तिरोशका, केटरीत गरिक हारा अस्पोदित गोपा स्कोम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनर्ने संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की शाषा में उसकी मुख्य बातों का भनुबाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का मा उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरक्त वर्ष करेगा भौर उसकी बाबत भावष्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबक्ष करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बड़ा य जाते हैं तो निमोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कमचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था फरेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रनुकूल हों, जो उन्त स्कीम के प्रधीन धनु वैस है।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मजारी की भृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मजारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो नियोजक कर्मजारी के विधिक बारिस/नाम निवेशिक्षी को प्रतिकार के क्या में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. स. पृष्टिक जीवा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि भागुक्त, कर्नाटक के पूर्व भनुभोदन के विना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भागुक्त भपना भ्रमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को स्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को गुक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अमेन तहों रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छुट रद् की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन भीमा निगम द्वारा नियस तारीख के भीतर प्रीभियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजंक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिकाम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देगितियों या विधिकवारिसों को जो यदि यह छूट, न दी गई होती तो उकत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन अंते वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हक्कवार नामनिर्वेणिती/विधिक वारिसों को उस राणि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिष्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/177/85-एस.एस.-4]

S.O. 4178.—Whereas Messig Maharashtra Apex Corporation Limited, Syndicate House, P.B. No. 38, Manipal-576119, Karnataka (KN/4470) (hereinafter reterred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and hiscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in employment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULF**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/177/85-S.S.IV]

का. आ.4179:— मैसर्स युनाइटेड शिपर्स एण्ड ड्रैजर्ज लिमिटेड, 67/2, लाबेला रोड, बंगलीर (के. एन./5599) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदम किया है;

और केन्द्रीय सरकार का सामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायभों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करें।

- 3. संस्कृतिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसकें अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्था-पन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के के रूप में उसका नाम शुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल्त करेगा।
- 6. यिव उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों से समुचित रूप से वृद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम केअ धीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कमंचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कमंचारी को उस दणा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कमंचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशों-धन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मधारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रह की जा सकती है।

- 10. यदि किती करगान नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में अस्पत्त रहता है तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन अने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राणि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक घारिसों को उस राणि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनि-क्वित करेगा।

[संख्या एस०-35014/188/85 एस. एस.-4]

S.O. 4179.—Whereas Messrs United Shippers and Dredgers Limited, 67/2 Lavella Road, Bangalore (KN/5599) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition; specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, navment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his

- establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Netwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all tespects.

[No. S-35014/188/85-SS.tV]

का ०आ ० 4180 - —मैसमें ड्रैंजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया किमिटड, जीवन प्रकाण, विशाखापट्टनम (आरघ प्रदेश/5965) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गय, है) ने धर्मधारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिए जाने के जिए आबेदन क्षिया है;

अर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के क्मेंचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय विणे क्षिन: ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे यन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमेय हैं: अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतौं के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

# अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजिक प्रादेणिक भिनिष्ण निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को एेमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के निए एमी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3%) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रक्ति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रित तथा कर्म चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उपका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दर्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्म चारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीम स्कीम के अधीन कर्म चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे जि कर्म चारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से आधक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनु ग्रंय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देग रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देग होती है, जब वह उक्स स्कीम के अधीन 698 GI/85—10

होता तो, तियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/तामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के अगकर रक्षम का सन्दाय करोगा।

- 8 सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन में जर्म चारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भिविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कमचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट जरने जा युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि ित्सी द्यारणवंश, स्थापन के वर्निचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उप सामृहित बीमा स्कीम के जिले स्थापन पहले अपना चुता है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रत्नद् की जा सकती हैं।
- 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मदाय करने में अनुफल रहता है, तो पालिमी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रहकी जा मकती है।
- 11. नियोज इत्या प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दणा में, उन मृत सदस्यों के ना:- निर्देशितियों या विधिए वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय दा उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले िसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा कृत राणि के हरूदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राणि का संवाय नत्यन्ता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

# [संख्या एस-35014/191/85-एस ०एस ०-4]

S.O. 4180.—Whereas Messrs Dredging Corporation of India Limited, Jeevan Prakash, Vishakhapatnam (AP|5965) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establish-

ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the I'mployees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount navable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Andhra Pradesh where any amendment is likely to affect udversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable onportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cornoration of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal being of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheine the Life Insurance Corporation of India shall ensure promot payment of the sum assured to the nomine Aegal heirs of the deceased member entitled for it and in one continuous month from the receipt of chim complete in all respects.

का. आ. 4181.— मैससं आर. जी. इस्पात लिमिटेड, भीट नं. 9, विश्वकमी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राजस्थान/2328) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवट्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 17 का उपधारा (2का) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय संरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए जिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के क्यमें फ़ायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल है. जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके, पण्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदन्त अक्तियों का प्रयोग करने हुए और इसमें उपाबद्ध अनुमूची में विनिधिष्ट गर्नी के अधीम रहते हुए उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन छूट देती है।

# अनुसूची

- उनत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी मुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय, सरकार समय-समय पर निदिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मांस की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय संरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गंत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोमियम का मंदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण, प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक हारा किया जाएगा।
- 4. नियंजिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमौदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मभारियों की बहुर्सख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भिषय निधि का या उपत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवष्य निधि का पहले ही सदस्य है. उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामृहिक बीमा स्कीम केसदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी

[No S-35014/191/85-SS.IV]

बाबत आवश्यक प्रोतियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

- 6. यदि उक्त स्कोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामू हिक बामा स्काम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप में वृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजिंक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधम, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधम से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बोमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसीको व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यक्तिम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हक्कदार नामनिर्देशिती /विधि वारिसों को उस राणि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिष्चित करेगा।

[मंख्या एस - 35014/186/85-एस. एस - 4]

S.O. 4181.—Whereas Messrs R.G. Ispat Limited, Road No. 9. Vishwakarma Industria? Area, Jaipur, (RJ/2328) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shaft submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirhominee of the employee as compensation.
- 3. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the intereset of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the duc date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/186/85-SS.IV]

का. आ. 4182 :— मैंसर्स इंटरनेशनल कोंडिट एण्ड डेवलपमेंट सिंडीकेट लि., मनीपाल, डी. कन्नाडा, कर्नाटक-576119 (के. एन./6966), (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्ट स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त दोधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो एया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक जीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अहः कंद्रीय सरकार, उक्त अभिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुमूची में विनिदिष्ट शतीं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन गर्ध की अविधि के लिए उक्त स्कीम के ग्मी उप-बन्धों के प्रवर्गन से छूट देती हैं।

#### अनम ची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के रूण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. साम्हिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, दिवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्धाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक हारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्स्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया

- जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियीजित किया जाता है तो, नियोजक, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सूरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के उधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृधित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कृल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्चेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदौंशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अन्सोदन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकाण स्पष्ट कराने का युक्तियुक्त अवसर वेगा।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले जायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यिष किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम ब्रारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रव्य की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निवंधितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, तीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, जीमाकृत राशि के हकवार नाम निदे शित/विधिक बारिमों को उन राशि का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मृनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/181[/]85-एम, एस.-4]

S.O. 4182.—Whereas Messrs International Credit and Development Syndicate Limited, Manipul, D. Kannada, Karnataka-576119 (KN|69663 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Schome of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall imediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 5. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reproportative to the employees to explain their point of view

- 9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable  $t_{\Omega}$  be cancelled.
- 11- In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the onmineellegal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(181)/85-SS.IV]

का. आ. 4183:— मैंसर्स नोक्टे टिम्बर कम्पनी लिमिटेड, डा. डिओमली, अरुणाचल प्रदेश (ए. एस./481), (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भिवष्य निधि और प्रकीर्ण उपदस्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन स्कृट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहहक ब्रीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचाता उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजोय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, अवत अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायद्ध अग्मौची मो विनिर्धिदष्ट शतो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन का नीय वर्ष की अवधि के लिए अवत स्कीम का मधी उप-बन्धों के इंकर्न से छुट देती हैं।

#### 3 नमची

- 1. उक्त रथापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रांशिक भविष्य निधि आयुक्त, गोहाटी को ऐसी विवरणियां भंजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रवान करेगा जो केंन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के रूण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जारा विवरिणयों का प्रस्तृत कियाजाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, वब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रविश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबंत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की स्ववस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अभाने अभीन अन्नेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम मों किसी बात के होते हुए भी. यदि किसी कर्मधारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सम्बंध रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीव होता तो, नियोजक कर्मधारी के विधिक बारिस/नामनिदें शिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन, प्राविशिक भविष्य निधि आयुक्त, गोहाटी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्राविशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमादन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकांण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते ही, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने धाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते ही, तो यह छूट रव्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत सारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदव की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-नियंशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीर अ अभीन आगे वाले किसी सदस्य की गृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगमा, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निवेशिका/विधिका यारिसों को उस राशि क। संदाय सत्परता में और प्रत्येक दक्षा में हुर प्रकार से प्रणे दावे की प्राप्ति के एक भाग के भीतर सनिश्चित करेगा।

_[संख्या एस-35014/182[/]85-एस. एस.-4]

S.O. 4183.—Whereas Messrs Nocte Timber Company Limited. P. O. Deomali, Arunachal Pradesh (AS/481) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gauhati maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall imediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the leval bein nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gauhati and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the amployees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said extablishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fived by the Life Insurance Corporation of India, and the nolley is allowed to lupse, the exemption is liable to be cancelled
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of chim complete in all respects.

[No. S-35014(182)/85-SS.IV]

का. आ. 4184 :— मैंस्म मंद्राम एल्मिनियम कम्परी लिमिटेड, मेट्टर डेम, स्लीम जिला (टी. एत./5324), (जिमे इसमें इसके पडचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपजन्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उदल स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म-चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध सीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचार उन्ने स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजय है;

अतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अस्मूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन का तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीस है रभी उप-बन्धों के प्रवर्तन से छुट देशी है।

## अनमची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रोदेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तिमलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेगा नथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविक्षाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार. उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के रूण्ड (इ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक वीमा स्कीम के प्रकासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विकरणियों का प्रस्तृत किया जाना, दीगा ग्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो सन्दाय आदि भी है, होने जाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार हारा अनुमोदित कीण स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुर स्था की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अन्वाद, स्थापन के सूखना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मजारी, जो कर्मजारी भिष्ठिय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिषठिय निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में निदीजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामहिक बीमा स्कीम के रदस्य के रूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवदयक प्रीमियम भारतीय जीवन नीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक मामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मगृचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कुल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्जेय' हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्हीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रक्षम उस रक्षम से काम है जो कर्मचारी को उस दशा में सक्ष्य होता, जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोकक धार्मचारों के विधिक बारिस/नामनिवाधिती की प्रतिकार के स्वा में बोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का सन्दाय करोगा।
- 8. सामृहिक बीसा स्किम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुसोदन के बिदा नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावधिक भिष्य गिधि आयुक्त, अपना अनुसोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दिष्टकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किशी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय बीवन दीमा निगम को उस साम्हिया बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना च्का है, अधीय नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायचे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय श्रीवन श्रीमा निगम द्वारा नियत तारील के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रव्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यक्तिक म की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निद्धितियों या दिशिक दारिसों की जो यदि यह, छुट न दी गई होती को उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के मंदाय का उन्तर दारित्व नियोजक एक होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निरमा, जीमाकट राष्ट्रि के हकदार नाम निवेधिकां /दिधिक वारिसों को उस राष्ट्रि का मंदाय तत्परना से और प्रकारित द्या में हर प्रकार से एण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीवर सनिविध्य करेगा।

[संख्या एस-35014/189/85-एस. एस. -4]

S.O. 4184.—Whereas Messrs The Madras Aluminum Company Limited, Mettur Dam, Salem District (TN/5324) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employed the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the sail Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirhominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Gicup Instrance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employeees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Science of the Life Insurance Corporation of India is already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 16. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11- In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal here of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Schenic the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S-35014(189)/85-SS.IV]

का. आ. 4185: — मैंसर्स अत्ल ग्लास एण्ड इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लिसिटेड, 14/1 मधुरा रोड, फरीदाबाद (पी. एन./1465), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक जीना स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायबे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायबे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाता उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अहः कंन्द्रीय सरकार, उदत अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद अनुसूची में दिनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उकत स्थापन को तीय दर्घ की अधिध के लिए, उक्त स्कीम के सभी उप-बन्धों के प्रदर्शन से छूट देनी है।

# अन्मूची

- ा. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य गिधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा शिरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय गरकार, सभय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के रूण्ड (क) के अधीन समय-सस्य पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक जीमा स्कीम के प्रशासन मो, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीसियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्मोदित बीमा स्क्रीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया

जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के छूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अभीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के अभीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से दिख्य की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कृल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्त्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी. यदि किसी कार्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्वये रकम उस रकम से कम हैं जो कर्मचारी को उस दक्षा में सन्वेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीय होता तो, नियोजक कर्मचारों के विधिक बारिस/तमिनिद्दें शिक्ष प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्वाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंद्योधन, शादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाण के पूर्व अन्मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी मंद्योधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ाने की मंभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदिन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना ब्रिष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कोम के, जिसे स्थापन पहाले अपना चूका है, जिन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने गाने फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, नो यह छूट रहद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन वीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिमी को क्षपणत हो जाने दिया जाता है तो छट रदय की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में कियं गये कियो व्यतिक्रम को दक्षा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निदंशितियों या विश्विक दारिमों की जो यदि यह, छाट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा अयदों के संदाय का उत्तरदाधित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीर आने वाले किसी सदस्य की राष्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकर राष्ट्रि के हकदार नाम निवेक्तिति/विधिक वारिसों को उस राष्ट्रि का संदाय तत्रारा में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्रान्ति के एक माम के भीतर सनिदिखत करेगा।

[मह्या एस-35014/183/65-एस. एस.-47

S.O. 4185.—Whereas Messrs Atul Glass and Industries (Private) Limited, 14/I, Mathura Road, Faridabad (PN/1465) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Empfoyees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Haryana maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be home by the employer.
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shalf immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident fund Commissioner. Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrealy adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to ray the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11- In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(183)|85-SS-IV]

का. आ. 4186 :— मैसर्स वड़ौदा जिला को-आपरेटिट मिल्क प्रोड्यस्प यानियन लिमिटेड, बड़ौदा डेयरी, (गुजरात/4856), (जिसे इसमें इसके परचात् उकत स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी अविषय निधि और प्रकीर्ण उपवस्थ अधिनियस, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके परचात् उदल अधिनियस कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीर छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथका अभिदाय या प्रीसियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं। और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनक्त हैं। जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इस्में इसके परचात् उदन स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय है;

अतः कोन्द्रीय गरकार, उक्त अभिनियम की धारा 17 की उप-भारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिवनयों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबंड अनुसूची में बिनिविष्ट शतों के अभीन रहने हुए, उदत स्थापन का तीन पर्की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुस्ची

- 1. उवत स्थापन के सरवन्ध में सियोजक प्रारंशिक भविष्टा निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा गिरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदास करेगा जो केंद्रीय सरकार, समम-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्योक साम की समाण्ति के 15 दिन को भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 17 की उग-धारा (3-क) के सण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. गान् हिक वीमा रूपिम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्भ लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रमान किया जाना, बीधा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्मोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्वाद, स्थापन के सूचना-पटट पर प्रविधित करेगा।
- यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उदत अधिकियम के अंधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-

- निधि का पहले ही सदस्य है, इसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, नामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आनश्यक प्रीनियम भारतीय जीवन नीमा निगम को सन्दल्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक माम्हिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मम्चित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजोग है।
- 7. साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के हांने हुए भी. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देथ रकम उस रक्षम में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब बहु उक्षत स्कीम के अधीन होता तो, नियोक्क कर्मचारी के बिधिक बार्सि/गामनिर्देशिनी की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रक्षम का सन्दाय करोगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपवल्थों मो कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिवष्य निधि अग्रुक्त गुजरात के पूर्व अन्मादन के बिना रहीं किया जाएगा और किसी रहीं के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संशावन हो बहां, प्रादेशिक भिवष्य निधि आग्रुक्त, अपना अन्मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कराने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन दीमा निगम को उस सामृहिक दीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहल अपना ज्का है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायद किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छ्ट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन जीमा निगम द्वारा नियत तारील के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में असफल रहता है, क्षो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत रायस्यों के नाम-नियंशितियों या विधिक दारिसों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा छायबों के संदाय का उत्तरवायिल्ल नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की राज्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, तीमाकृत राशि के हकदार नाम निवेशिकां(टिधिक वारियों को उस राशि का संदाय तहारता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से एण दावे की प्राप्ति हो एक साथ के भीतर सुविश्वित करेगा।

· [संख्या एस-35014/187⁷85-एस. एस.-4]

# New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4186.—Whereas Messrs Baroda District Co-operative Milk Producer's Union Limited, Baroda Dairy, Baroda-9 (GJ]4856) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any reparate contribution or payment of premium, in enjoyn ent of benefits under the Group Jusurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employes' Deposit Lunked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

# **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Gujarat, maintain such accounts and provide such faculaties for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group lasurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- I. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- f. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Schene a group tately, if the benefits available to the employee under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if one the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisious of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable or portunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alteady adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of prension the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominec legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]187[85-SS,IV]

क: आ. 4187: — मैसर्स सूरत जिला को-अपरेटिक मिल्क प्रोड्यसर्स यूनियन लिमिटेड, सुमैल डेयरी, सूरत (गूजरात/ 2269) (जिसे इसमें इसके परचात् अवस्य स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके परचात् अध्यत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आबेदन किया है;

अंदि के द्वीय सरकार का समाधान हो गया है कि उद्देत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए विना ही, शारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन अविन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध तीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजीय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उदन अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2--5) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध अल्याने में विविधित्य शतीं के अधीन रहते हुए, उदल स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप-कथीं के प्रवर्तन से छूट देनी हैं।

# अनुस्ची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी दिन्दिण्यां भेजेगा और ऐसे लेका रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान करेगा जो कोदीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर रन्दाय करेगा जो केन्द्रीय नरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के लण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामृहिक जीमा रुतिम के प्रशासन में, जिस्के अन्तर्गत् लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक हारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पटट पर प्रविश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मजारी, जो कर्मजारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, गामहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उमका नाम त्रन्त वर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीगियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दन्त करेगा ।

- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मणारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मणारियों की उपलब्ध फायदों में ममृणित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मणारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उस्त स्कीम के अधीन अनुनेप हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम सं कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जम बहु उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिद्देशितों की प्रतिकर के रूप में दांनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिषय निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पहने की संभावना हो बहां, प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्क्रीम के, जिसे स्थापन पहले अपना भूका है, अधीन नहीं रह जासे हैं, या इस स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले जायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन भीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता हैं तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संन्दाय में किये गयं किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निवासितयों या विधिक बारिसों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों को संदाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की मृत्यू होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाक्ष्ट्र राशि के हकवार नाम निवेशिशित/बिधिक बारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वाबे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[No. 35014(190)/85-S\$-IV]

S.O. 4187.—Whereas Messrs Surat District Co-operative Mlik Producer's Union Limited, Sumul Dairy, Surat (GJ|2269) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in cnloyment of benefits under the Group Insurance Sheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees

than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, mansfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as any when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an entablishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said. Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under—the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. \$-35014¹190]85-\$\$.1V]

का. आ. 4188.—मैंसर्स कोपर-फोम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 14/10, सध्रा रोड, फरीदाबाद (पी. एन.-5598) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया हैं) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपहन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त जिधिनियम कहा गया हैं) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवंदन किया हैं;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन श्रीमा निगम की सामृहिक नीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म-चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकून हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें पनके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजोय हैं;

अह: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्विष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष को अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन में छट देती हैं।

# अन्सूची

- 1. उकते स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविषय निधि आयुक्त, हरियाणा को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के गिए ऐसी गुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यंक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के रूण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विदरिणयों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मुचना-पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्ठिय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम त्रन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबम आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दल्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के राधीन उपलब्ध फायदों में समृचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृत हों।

- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उसते स्कीम के अधीन होता तां. नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/नामनिदेशिती की प्रतिकर के एप में बोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- . 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई भी संशोधन, प्राथिशिक भिविष्य निधि अञ्चलत हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो बहां, प्राविधिक भिविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमादन दोने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर दोगा।
- 9. यदि किसी कारणवर्थ, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कोम के, जिसे स्थापन पहले अपना चूका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन शीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गयं किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निदंशितियों या विधिक वारिमों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्थीम के अधीन आने वाले किसी भदस्य की मृत्य् होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राद्यि के हकवार नाम निव्योदिती विधिक धारिसों को उस राशि का संवाय नत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार ने पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक माम के भीतर मनिश्चित करेगा।

[सं. एस.-35014(178)√85-एस.एस. 4]

S.O. 4188.—Whereas Messrs Coirfoam (India) Private Limiteed, 14[6, Mathura Road, Faridabad-121002 (Harvana) (PN-5598) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making my separate contribution or nayment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees

than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

# **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if one the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Haryana and where any amendment is jikely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the permitted etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said. Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Schene the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/178/85-SS. IV]

का. आ. 4189.—मैंगर्म जनरत इजीनियरिंग इण्डिंग्ट्रीज, 26-ए, इण्डिस्ट्रीयल एस्टेट, गोजिन्दपुरा, भोगाल-मध्य प्रदेश (म. प्र./2049) (जिसे इसमें इसके परचाता उदत म्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवध्य निधि और प्रकीर्ण उपदेध अधिनियम, 1952 (2952 का 19) (जिसे इसमे इसके परचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजय हैं;

अनं: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-5) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीय धर्य की अवधि के लिए उक्त स्क्षीस है सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन में छूट देती हैं।

# अन्मृची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविषय निधि आयुक्त, मध्य प्रवेश को एसी विवरणियां भंजेगा और एमि लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विध्य करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की समाणि के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के रुण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्देश्व करें।
- 3. सामृहिक तीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवर्रणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमस्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का अनुबाद, स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में निशीजिंद किया

जाता है तो, नियोजक, सामृष्टिक गीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नग्म तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बागत आवस्यक प्रीसियम भारती: जीवा दीमा निगम को सन्दल्त करेगा।

- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों से समृत्रित क्य में बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अगुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभेत हैं।
- 7 सम्बुहिक बीमा महीम मां किसी बास के होते हुए भी, यदि किसी कार्मवारी की मृत्य पर हम स्कीम के अधीन सन्देश रक्षम उस रक्षम से कम के जा कार्मवारी की उस स्वाम में किसी कार्मवारी के उस स्वाम में किसी होता तो, नियोजक कार्मवारी के विधिक वारिष्ट/लग्निविधिनी की प्रतिकार के रूप में बोनों रक्षमों के अन्तर के दराहर रक्षम का सन्दाय कार्मा।
- 8. साम्हिष्ट टीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई भी संकोशन, प्रदेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के दिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन में कर्मचारियों के दिन पर प्रतिक न प्रभाग पड़ाने की संभावता हो बहां, प्राविक्षिक भीषाय्य निधि आयुक्त, अपना अनुमादन दोने से पूर्व कर्मवारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यिक्षियतन अवस्थ देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन वीमा निगम को उस सामृहिक वीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले पायद किमी गीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक भारतीय जीवन जीमा निगम द्वारा नियत तारील के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में अमफल रहता है, तो पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सो छट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्ताय में किये गयं किसी व्यक्तिक में की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निद्धींकितियों सा विधिक वारिमों की जो यित यह, छूट ने दी गई होती तो उद्दारकीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय उत्तरदायिक नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्थीम के अधीन अभी वाले किसी स्वस्य की मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकत राष्ट्रि के हकदार नाम किवीं किती विधिक वारियों को उस गाँव का गंदा तत्याला में और प्रत्येक द्वारा में हार प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक साथ के भीवर मिरिक्त करेगा।

[बंद्रा एस. 35014 180 85 एस. एस. 4]

S.O. 4189.—Whereas Messrs General Engineering Industries, 26-A, Industrial Estate, Govindpurn, Bhopal (MP) (MP) 2049. (heroinafter referred to as the said establishment) lune anglied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schadule unnexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessive remium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the leval ben nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Greup Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9 Where for any teason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme an reduced in any minor, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer sails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to

lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]1921;85-SS-IV]

# नई दिल्ली, 23 अगस्तः 1985

का. आ. 4190. — मैसूर्म कीयर-फोर (इण्डिया) प्राइधेट लिमिटेड, 14/6, मध्या रोड, (पी. एन. 5593) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके प्रचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आबंदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उद्या स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथका अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहित वीमा रकीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं। और ऐसे कर्म-चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके प्रचात उसके स्थीम कहा गया है) के अथीन उन्हों अनुहोय हैं:

अर: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करने हुए और इससे उपाबद अनुसूची में विनिधित्द शर्ता के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन दर्प की अविधि के लिए उचल स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रतर्नन में कूट देती हुँ।

# अनुस्ची

- 1. जक्ष स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिटिष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेडेंगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के सिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समक पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय संस्कार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उग-धारा (3-क) के रूपड (ऋ) के अधीन समय-रामय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. साम्हिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिलके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तत किया जाना, वीमा प्रीमियम का सन्दत्य, लेकाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोदक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उम संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के गवस्य के रूप में उसका नाम तुराना दार्ज करेगा और उसकी गांबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्वत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममचित रूप से बिद्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से अधिक अनकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुष्ठेम हैं।
- 7. सामृहिक वीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यिद किसी कर्मचारों की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारों को उस देशा में सन्देय होती. जब वह उसके स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक अर्मचारों के विधिक वारित्र/तामनिद्वेषिती की प्रतिकर के मण् में योनों रकमों के अन्दर के बराबर रकम का मन्दाय करेगा।
- 8. सामितिक बीमा स्कीम के उपवन्थों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पर्व असमोदन के दिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मनारियों के दिल पर प्रतिकाल प्रभाद एउने की संभावना हो नहां, प्रादेशिक भविष्य निधि शायुक्त, अपना अनुमोदन दोने से पर्व कर्माशीर यो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अस्तर दोगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी. भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक नीमा स्कीम को. जिसे स्थापन पहले अपना चुका है. अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से क्षेत्र हो जाते हैं, तो यह छुट रह्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन भीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक हारा प्रीमियम के सन्दर्थ में किये गये किसी व्यतिकास की द्रशा में, उन मृत सद्यस्यों के नाम-निर्देशितियों ए विधिक वारिसों की जो यदि यह. छूट नदी गर्ड होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरवादित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की सत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, नीमाक्त राशि के हकदार गम निविधिक वारिसों को उस राशि का संदर्ध तत्परा में और प्रत्येक दक्षा में हर प्रकार में पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीगर सनिश्चित करेगा।

[लंख्या एस. 35014[/]176[/]85 एस. एस. 4]

## New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4190.—Whereas Messrs. The Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Raipur, Madhya Pradesh (MPI1135) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section17 of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Groum Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such amployees than the benefits admissible under the Employees' Denosit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Nov, therefore, in exercise of the powers confered by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the sain establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7 Notwithstanding anything contained in the Comp Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be nayable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Lagrance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a ensonable opportunity to the employees to collain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the amploves of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the henefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

  698GI/85—12

- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the parnium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defult, it any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the non-necs or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme out for great of this exemption, shall be that of the emptoy or
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal beits of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of chilin complete in all respects.

[No. S-35014/176/85-SS-IV]

का. आ. 4191.—मैसर्स आटो ग्लाइड प्राइवेट लिगिटेड, प्लाट नं. 64, सेक्टर-6, फरीवाबाद (हरियाणा/9592) (जिसे इसमें इसके पश्चाच् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविषय निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अभीन छूट दिए जाने के लिए आवेसन दिश्या है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उदत त्थापन के कर्मचारी, किसी पृथका अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए दिना ही, भारायि जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कार्यदे उठा रहे हैं। और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदो उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं। जो कर्मचारी निक्षेप सहद्व वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके प्रचात् उत्तर स्कीम कहा गया हैं) को अधीन उन्हों अनुकोय हैं।

अतः कंन्द्रीय भरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) इत्रा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अत्याभी में बिनिविष्ट शतों के अधीन रहारे हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कोस के सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन में छुट देखी हैं।

# अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्मन्य मी नियोजक प्रावेशिक भविष्या निधि वाय्कत, हरियाणा को एरेरी विवयणार्था रोजेस अरि एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण की लिए एसी सुविधाएं प्रवान कारीगा जो केन्द्रीय गरकार, समय-समय पर निविध्य लिए।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक साम की संमाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के एण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सास्तृहिक वीमा स्कीश के प्रशासन मो, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रका जाना विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों स्नदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन जियोजक द्वारा विवया जाएगा।
- 4. िशयोजक, केन्द्रीय मरकार द्वारा अनमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य कार्यों का अनुवाद, स्थापन को संख्या-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामहिक बीमा स्कीम के गवस्य के रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवद्यक प्रीगियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजोग हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यिव किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती. जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिद्धिती की प्रतिकर के रूप में बोनों रक्तमों के अन्तर के बराइर रक्तम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व उनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीसा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चूका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रव्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में असाहल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सो छट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निवेंशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संस्थय का उस्तरहायित्व संयोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की मत्य होने पर भारतीय जीवन तीमा चिगम, तीमाकृष्ट राशि के हकदार नाम निदेविती/विधिक वारिसों की उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्राप्ति के एक साम के भीतर मिन्शिकन करेगा।

[मं. एस. 35014/180/85-एम. एस. 4]

S.O. 4191.—Whereas Messrs. Auto Glide Private Limited, Plot No. 64. Sector-6, Faridabad (HR¹⁹592) (horeinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2-A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in entoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now therefore, in exercise of the powers confered by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed herete, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the mapority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall nay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversors the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any monner, the exemption shall be liable to be cancelled

- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life luxurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

No s 35014/180/85 SS IV]

का. आ. 4102. — रीसर्प भारत फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, 15/4, मथुरा रोड, फरीदाबाव (हरियाणा) (पी.एन./3634) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपभारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद उठा रहे हैं और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सह बढ़ बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके प्रचास उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवंधों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

## अनसची

- उनस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भिवष्य निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भंजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरक्षिण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति की 15 दिन के भीतर सन्धाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत ने लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियन का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरक्षिण प्रभारां संवाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा एकीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संघी-धन किया जाए, तब उस संघोधन की प्रति तथा कर्मचारियों

- की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य कार्तों का अनुवाद, संस्थान के सुचना पट्ट एर प्रवर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उदत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजित, साम्हिक वीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवहयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनक्षय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसंगाम निदेंशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिय्वस अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा न्विगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्व की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणदश, नियोजक उस नियत सारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रखद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निदेणितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निदें शिलियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संबाय तत्परता से और प्रत्येक वंशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिष्कित इतेगा।

[संबद्धा एफ 35014/179/85 एख॰ एस॰]

S.O. 4192.—Whereas Messrs, Bharat Foam Udyog Private Limited, 15|4, Mathina Road, Faridabod-121002 (PN|3654), (heteinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellenous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers confered by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government he eby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana, maintain such accounts and provid) such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Netice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme by less than the amount that would be payable had employee been covered under the said &cheme, the employer shall pay the difference to the legal bein nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approximity to the employees to explain their tolar of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the henefits to the enaployees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the logal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/179/85-SS. II]

का. श्रा. श्र193.-- केन्द्र य सरकार को यह प्रतित होता है कि मैसर्स प्रसोड़ा फार्भाष्य टिकल ईन्डम्ट्रंज 82, रंपन म्हें.ट. ज . पं . भी . काक्स 2558, कलकत्ता-16 नामक स्थापन के संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारा भविष्य निधि और प्रकृण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

भतः केन्द्र य सरकार, उन्त प्रधितियम के धारा-1 कः उपधारा-(4) शारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्त प्रधितियम के उपबंध उन्त स्थापन को लागू करते हैं।

S.O. 4193.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Arora Pharmaceutical Industries 82, Ripon Street, GPO Box 2558, Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(80) /85-SS-II]

का. थ्रा. 4194.-- केन्द्रीय सरकार की यह प्रतंत होता है कि मैसर्स काली दास मुलिक सेरायटन, 47, गणेश चन्द्र एवन्यू, कलकत्ता-13 नामक स्थापन के संबंध नियोजक धौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रकोण उपबंध प्रश्चित्रियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उसत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

भ्रतः केन्द्र य सरकार, हेक्त ग्रह्मितयम क धारा । कं उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त भ्रक्षिनियम के उपशंध उक्त स्थापन को लाग करतें हैं।

S.O. 4194.—Whereas it appears to the Central Government, that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kalidas Mullick Sebayatan, 47, Ganesh Chander Avenue, Calcutta-13 have

agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(79) /85-SS-II]

का. था. 4195.-- केन्द्रं य सरकार को यह प्रत स होता है कि मैससे फोना रवड़ प्रा. लि., 77, जिरस्टोफर रोड़, कलकत्ता-46 नामक स्थापन के गबंद्ध नियोजक भ्रौर कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारा भविष्य निधि भ्रौर प्रक ण उपबंध भ्रधिनियम, 1952 (1952 को 19) के उपवंध जक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

श्रतः केन्द्रं य सरकार, उक्त भ्रधिनियम कः धारा 1 कं उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त श्रधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करते हैं!

[सं. एस.-35017(81)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4195.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fona Rubber Private Ltd., 77, Christopher Road, Calcutta-46 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made aplicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(81)/85-SS-II]

का. भा. 4196---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतंत होता है कि मैसर्स कर्माणयल प्रोडेक्स लि., स्टेंडर्ड इन्डस्ट्रियल ईस्टेट, पोस्ट आफिस टटा-गढ़, 24-प्रगना भौर (रिजि. आफिस), 95 पार्क स्ट्रूट, कलकत्ता-16 गामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों के बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचार भविष्य निश्चि और प्रकर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

श्रतः केन्द्रःय सरकार, उक्त स्रधिनियम क. धारा 1 क उपधारा (4) हारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त स्रधिनियम के उपंबन्ध उक्त स्थापन को लागू करतः है।

[सं. एम.-35017(82)/85-एम. एम.-2]

S.O. 4196.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Commercial products Ltd., Standard Industrial Estate, P.O. Titagarh 24-Parganas including its regd. Office at 95 Park Street, Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(82)/85-SS-II]

का श्रा 4197.--वेन्द्रच सरकार को यह प्रश्व होता है कि मैसर्स बैन पोल.मर्स, 56, टोपसिया चोड, (साउथ) कसकत्ता-40, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक श्रीर कर्मचारियों क बहुसंख्या इस बात पर सहमा हो गई है कि कर्मचार भविष्य निधि श्रीर प्रकीण उपवंध प्रशिनियम, 1952 (1952 को 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागृ किए जाने चा हुए ।

श्रतः केन्द्रं य रास्कार, उक्त ग्रिधिनिका कः धारा । कः उपधारा (4) द्वारा प्रदल्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त ग्रिधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागु करतः हैं।

[मं ए.-35017(83)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4197.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis. Bani Polymers 56, Topsia Road (South), Calcutta-46 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(83)/85-SS-II]

का. मा. 4198.-- केन्द्र य सरकार को यह प्रतात होता है कि मैससं इन्डियन केन प्रा. लि; विशेज नार्रासिधापुर, पोस्ट आक्तिए छोटो जागित्या, बडसा जि.-24-मगना मीर (रिज. म्राफिस) 6, मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-71 में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक भीर कर्मबारियों के बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मबार. अविष्य निधि भीर प्रकाण उपपंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

श्रतः केन्द्रःय सरकार, उक्त अधिनियम के धारी 1 के उपधारा (4) हु द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतः है।

[सं. एस.-35017(84)/85 एस. एस.-2]

S.O. 4198.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messra. Indian Can I td. Village Norasinghapur P.O. Chhoto Jagulia Barasat, Dist. 24-Parganas, including its Regd. office at 6, Middleton Street, Cafeutta-71 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(84)/85-SS-II]

का. था. 4199.-- केन्द्रंग सरकार का यह प्रतित होता है मैससं भाना रखड़ ईन्डस्ट्राज, 56, टोपियदा रोड़ (माज्य), कलकत्ता-46 और 1, मेरेविय स्ट्रट, कलकत्ता-72, में स्थित आफिम नामक स्थापन के मंबद्ध नियोजक और कर्मचारियों क बहु मंख्या इस बान पर सहमत हो गई है कि कर्मचार पविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू किए जाने चाहिए ।

धत. केर्न्द्राय सरकार, उमन प्रधिनियम क धारा 1 कें/ उपधारा (4) इंगर प्रदक्त शक्षि,यों का प्रयोग करते हुए ⊃वन अधिनियम के उपयंध - उमत स्थापन को लागु करती हैं।

[स. एस-35017(85)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4199.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bani Rubber Industries 56, Topsia Road (South), Calcutta-46 and its office 1, Meredith Street, Calcutta-72 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(85)/85-SS-II]

का. या. 4200.-- केर्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स देखी मणीन टूल्स प्रा. कि. 59, पेनथीनियन रीड़, फर्स्ट लेन, इगमोर, मद्रास-600008 नामक स्थापन के सबद्ध नियोजक घीर कर्मचारियों की बहु-संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि घीर प्रकर्ण जपबंध छितियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

श्रातः फेन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) हारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रिक्षियम के उपबंध उक्त स्थापन को लान् करते हैं।

[सं. एस-35019 (328) / 85-एस. एस.-2]

S.O. 4200.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Devi Machine Tools Private Limited, 59, Pantheon Road, 1st Lane Egmore, Madras-600008, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(328)[85-SS-II]

का. घा. 1201.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्न नवयुगा पिक्वर्श, गुनटाकल, घानध्र प्रदेश न(मक स्थापन के संबद्ध नियोजक घीर कर्मचारियो क. बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारा भविष्य निधि घीर प्रकर्ण उपबंध धाधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु किए जाने चाहिए।

मतः केन्द्रंय सरकार, उक्त प्रधिनियम क धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करते हैं।

> [स. एस-35019(330) 85-एस-एस-] ए. फे. भट्टाराई, अवर सिषय

S.O. 4201.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Navayuga Pictures Guntakal, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(330)|85-SS-II] A. K. BHATTARAI, Under Secy. नई दिल्ली, 22 भगस्त, 1985

का०न्ना० 4202.—- औद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 (1947 का 4) की धारा 17 के भ्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कील लि० की जीलगोरा कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियाजकों और उनके कर्मकारों के बीच, भ्रनुबंध में निर्दिष्ट आंद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-8-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4202.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., At and Post Office, Jealgora, District Dhanbau, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 57 of 1982

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES:

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.
On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary,
R.C.M.S., Dhanbad.

STATE: Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 9th August, 1985

## AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 1.-20012(28)/82-D.III (A), dated, the 19th May, 1982.

# **SCHEDULE**

"Whether the demand of the workmen of Jealgora Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, At and P.O. Jealgora, District Dhanbad that Shrimati Jaya Devi should be regularised on the post of Cartridge Maker in Category-I as per National Coal Wage Agreement is justified? If so, to what relief is the workman concerned entitled?"

The case of the workmen is that the concerned work fady Smt. Jayadevi was appointed as Wagon Loader in 1972. She was confirmed as Wagon Loader. In the year 1978 she was engaged by the management of Jealgora Colliery on the job of Clay Cartridge Maker along with a gang of other similar workers. The other workers who were engaged as Clay Cartridge Makers are all paid time rated Cat. I plus other benefits available to a colliery worker but the concerned lady was paid a consolidated wage of Rs. 15 per day without paying any other benefit. The management has taken a different stand in case of the work lady and thereby she has been discriminated with other workmen doing the

same type of job. When she had worked for sufficiently long period she represented her case before the management and the union of workmen also made a written representation but the management did not pay any heed. Thereafter the union raised an industrial dispute before the ALC (C) Dhanbad who took up the matter with the management and held conciliation proceeding which ended in failure and thereafter the Ministry of Labour referred the present reterence before this Tribunal for adjudication. It is submitted that the management has discriminated by not paying the concerned work lady the same rate of wages and allowances as have been paid to other workmen employed on the same job and as such the demand of the workmen is justified and she should be paid wages and allowances etc. in time rated cat, I as have been paid to all other similar workmen from the date of joining the duty in 1978 with all consequential effects and other relief.

The case of the management is that the concerned work lady was a confirmed wagon loader and was continuing as such. As her substantive appointment was to the post of Wagon Loader she had no right to claim for the post of Clay cartridge maker. The concerned work lady approached the management to give her employment as Clay cartridge maidoor in Cat. I for a temporary period to tide over her difficulties and thereafter she was employed as Clay cartridge maker. The job of making clay cartridge is a light job given to workmen on account of health reasons and to overcome certain personnel difficulties. The workmen given light job to overcome his difficulties is to resume her original duties as soon as the difficulties are over and the workmen cannot insist to continue in the employment of the light duty although. When the concerned work lady was asked for resuming her original and substantive duty of wagon loader, she approached the union which raised the present dispute. The union is not justified in demanding for regularisation of the concerned work lady as clay cartridge maker.

Her employment as clay cartridge maker temporarily cannot entitle her for permanent absorption in that post. The concerned work lady will not be entitled to regularise as clay cartridge maker.

The only point for consideration in this case is whether the concerned work lady should be regularised in the post of Clay cartridge maker in Cat. I.

The workmen examined two witnesses and the management also examined one witness in support of their respective cases. The management has further produced documents which have been marked M-1 to M-9. It will appear from the evidence of WW-1 the concerned work lady herself and the evidence of WW-2 that she is working as clay cartridge maker and is getting wages of Rs. 15 per day. It will further appear that 6 other women employed along with her to work as clay cartridge makers were getting time rated Cat. I wages. WW-2 is one of the workmen working with the concerned work lady as Clay cartridge maker. She was also formed working in another place as shale picker and thereafter she was transferred to work as Clay cartridge maker. Similarly the concerned work lady who was working as Wagon loader was transferred to work as Clay cartridge maker along with 6 others. It will appear from the evidence of MW-1 that the concerned work lady is entitled to get the wages of time rated Cat. I since she was employed to work as Clay cartridge makers. Thus it will appear that now there is no controversy whether the concerned work lady who is working as clay cartridge maker is entitled to the time rated wages of Cat. I since her employment in the job of Clay cartridge maker.

The management is not insisting now for sending her back as a wagon loader. The concerned work lady has worked admittedly as clay cartridge maker since 1978 till now and as such she deserves to be regularised as a clay cartridge maker in time rated Cat. I. The management has filled some wage sheets to show the actual amount of payment made to the concerned work lady for some period. It will appear from NCWA-I which was applicable from 1-1-75 that the basic wages of Cat. I daily rated worker was fixed @ Rs, 10 to 12. The concerned work lady was employed to work as clay cartridge maker in 1978 and as such she was entitled to this rate of wages till NCWA-II came into force from 1-1-79. According to NCWA-II the wages, of

daily rated Cat. I workmen was raised from Rs. 10 per day in the scale of Rs. 15.00-0.26-18.12 and as such the concerned work lady was entitled to the revised pay scale of Rs. 15.00-0.26-18.12 P. per day from 1-1-79 to 1-1-83 when NCWA-III came into force. According to NCWA-III which can into force from 1-1-83 the wages of daily rated Cat. I workmen was revised to Rs. 21.16-0.43-27.18 P. The concerned work lady is not in possession of papers to show the amount of wages which was actually received by her and the said account are with the management. The management therefore will account for the amount which she is entitled to receive in accordance with the scale of wages stated above and after making deduction of the amount which has already been paid to her, the balance which remain to be paid must also be paid to her. In this connection I may mention that I have only stated about the basic wages which she was entitled under the different awards of NCWA. She is also entitled to the other benefits available to a Cat I time rated worker and account has to be made in respect of those other benefits as well and the belance which has not been paid to her is to be paid at an early date.

In the result, it is held that the demand of the workmen of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. that the concerned work lady Srimati Jayadevi should be regularised on the post of Clay catridge maker in Cat. I as per NCWA is justified and the amount due must be paid to her after calculation as indicated above.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer [No. L-20012(28)/82-D.III (A)] A. V. S. SARMA, Desk Officer

# वर्ड दिल्फी, 26 अगस्त, 1985

का. था. 4203:—औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी, भारतीय स्टैट बैंक के प्रवंधतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचकारी के बीव अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करनी है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-8-85 को प्राप्त हुआ था।

# New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4203.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial, Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRABUNAL, KANPUR

Industrial Dispute No. 243 of 1983

In the matter of dispute between:

Shri Suresh Chandra Unreti, 135/206, Bans Mandi Muttiganj, Allahabad. Workman.

#### Versus

The Regional Manager, Region III, State Bank of India, The Mall, Kanpur. Management.

# APPEARANCE:

Shri Mangalwadekur, representative for the worknan & Shri A. S. Saxena, representative for the management.

## AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/146/83-D. II A, dated 8th December, 1983, has referred the following dispute for adjudication;

- Whether the section of the management of State Bank of India, Region III, Kanpur in relation to their University Branch, Allahabad in discheraing from service Shri Suresh Chandra Upreti, Clerk with effect from 27-10-77 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?
- 2. It is common ground that the workman Shri Suresh Chandra Upreti was a clerk in the management bank's branch of the University Branch, Allahabad, and that his appointment was made by Deputy Secretary and Treasurer of State Bank of India, at Kanpur, at the Allahabad Branch, on 31-12-70 and deputed at University Sub-Office on 4-1-1971, and that at the time of discharge from the service the workman was working in the management bank's University Branch, Alfahabad and that the workman was getting total emoluments Rs. 720 plus Rs. 72 as salary and allowance excluding banks contribution towards Provident Fund and pension.
- 3. It is further admitted that the management bank is an industry. It is further admitted that on 13-12-76, the opposite party No. 2 i.e. Branch Manager issued a memo to the applicant regarding Saving Bank Account No. 6223, in the name of Smt. Pratima Sharma to which the applicant replied on 20-12-76. Thereafter, the applicant was suspended by the management on 22-12-76. It is further not denied that on 10th January, 77 Mrs. Sharma holder of saving banks alc No. 6223 of bank's University Branch, Alfahabad, wrote a letter to the management dated 10-1-77. According to the workman the letter was to the effect that the workman was not at all guilty to the charge of mistake with which the workman was charged. It was on 12-2-1977 that the workman was served with a charge sheet by the management to which the workman replied on 14-2-77. It is further admitted that one Shri G. S. Kapoor Officer Gr. I of the Aflahabad Branch informed the applicant on 22-3-77, about the enquiry and completed the enquiry on 23-4-77. The workman has averred that in the enquiry he was not allowed opportunity to cross examine nor was heard. On 23-4-77 the workman submitted written arguments but despite all that he was discharged in terms of para 521(10)(c) of the Sastri Award, defined by para 18.20 of the Desai Award and thus the services of the workman were terminated w.e.f. 20-10-77, without giving a chance for hearing on the proposed punishment. It is not denied that the applicant requested the management vide letters dated 29-10-77 and 21-11-77, on the copy of enquiry proceedings and the findings of the enquiry officer made thereon but the same was turned down by the management vide letter dated 5-12-77.
- 4. The management contention is that in view of initial admission of charges levelled against him and his plea of mercy, the workman was not required to furnish the documents required. It is further admitted that the workman submitted an appeal on 22-9-78. It is further admitted that the workman filed appeal dated 7-4-78, 15-11-79 and on 8-10-80 to the Chief Regional Manager, State Bank of India, Varanasi, which were not replied by the management as according to them there was no provision of the second appeal. The management has admitted that the applicant was suspended on 22-17-76 while the charge sheet was issued on 12-2-1977 was justified as the workman was suspended on pending enquiry. It is not specifically denied that alongwith char esheet conies of the decuments and statements of service should have been supplied.
- 5. The workman has raised objection that the Enquiry Officer, was not competent authority and the appointment of the enquiry officer was illegal. In the end the vort man has averred that the submissions made during the domestic enquiry were under duress and thus it can not be relied upon. It is consequently prayed that the termination order duted 25-10-77, he quashed and the workman be reinstated with continuity of service.
- 6. The management denied the admissions referred above and have averred that the workman was charge sheeted for having collected the amount from one Smt. Pratima Sharma account holder of S.B. A/c. No. 6223 and retaining

- it and misutilising the same unauthorisely and making false entries of the rais book of the account holder of S.B. A/c. No. 6223 and thereby falsely representing the factum of deposits to the bank. That vide letter dated 20-12-76 he made unclarified admission of his guilt and pleaded for pardon in the following words:
  - That I committed a grave errors of judgment by not keeping in mind the implications and/or complications that might arise from my foregoing actions, and for that I take this opportunity Sir, to offer my profound apology and regret. Lastly Sir, I offer my unconditional surrender and pray for your merciful pardon as a special case, and for this act of your benevolent charity, I shall ever remain grateful to your goodself, as well as the institution.
- 7. It is averred that in view of the mercy appeal the bank took lenient view as a special case and the workman was discharged from the bank not amounting to punishment under section 521(10)(c) of the Sastri Award.
- 8. The discharge letter filed by the workman is signed by Regional Manager I who is disciplinary authority. In this he has observed that considering the enquiry proceedings and findings of the Enquiry Officer, the punishment warranted dismissal from the service, but having regard to the young age of the workman, the disciplinary authority decided to condone the mistake and simply to discharge the workman from service, which discharge was under para 521 (10) (c) of the Sastri Award which reads as follows;
  - In awarding punishment by way of disciplinary action the authority concerned shall take in to account the gravity of the misconduct, the previous record, if any, of the employee and any other aggravating or extenuating circumstances that may exist. Where sufficiently extenuating circumstances exist the misconduct may be condoned and in case such misconduct is of the gross type he may be merely discharged, with or without notice or on payment of a month's pay and allowances, in lieu of notice. Such discharge may also be given where the evidence is found to be insufficient to sustain the charge and where the bank does not for some reuson or other, think it expedient to retain the employee in question any longer in service discharge in such cases shall not be deemed to disciplinary action.
- 9 Thus this discharge was by way of punishment though mentioned as discharge in view of provision of para 521(10) (c) of Sastri Award as the management did not consider it proper to retain the emoloyee any longer in its service and passed the order of discharge which was to be deemed not amounting to punishment.
- 10. In the rejoinder the workman took plea that discharge simplicitor being retrenchment section 25F were not complied whith, hence, order of the discharge is violative and he deserves to be reinstated in service with full back wages.
- 11. Despite the fact that the account holder Smt. Pratima Sharma gave letter ext.M-3 dated 10.12.76 that she had received Rs. 550.72 paisa from Shri Upreti the discrepancy of between the pass book and ledger and authenticated entries in the pass book by workman himself could not be reconcilied and it was in these circumstances that the workman admitted his guilt. Even if discharge from service on 15th Octuber, 77 the workman on 22.9.78. filed his mercy appeal which is admitted by him. In the said mercy appeal workman admitted that having almost family relations, he always extended her facility which was never ill intended but was contrary to the rules of the bank and that whatever transactions were there in that account were never by way of any gain to the annlicant or by any loss to her. He has further admitted that some entries confirming with the ledger were made in her bass book in good confidence as an arrangement conveyance to her and that the mistake by him innocently came to the notice of the Branch Manager when the

book of Smt. P. Sharma account holder of 5B A/c 6225 some entries were found not in conformity with the ledger account.

- 12. In view of the above admissions and despite the fact that account holder Smt. P. Sharma wanted that the workman be exonerated and despite the fact that in view that the termination was not effected by the management the workman blame himself in view of the admissions and the discharge order was rightly passed by the management in view of provision of section 52(10)(c) of the Sastri Award.
- 13. The only mistake committed by the management was not taking the note that the termination for any reason whatsoever, the point be considered is whether the dicharge from service would be retrenchment within the meaning of section 2000) of the I.D. Act. If the discharge is by way of punishment inflicted by way of disciplinary action it would be retrenchment. Termination order reads as follows:

The papers have been examined by me. In view of the clear admission of guilty by Shri S. C. Upreti the finar punishment of dismissal as envisaged in the case involving fraudulent entries in the bank's books as also the pass books of the depositor should be inflicted. However, in view of the unblemished service record as also complete surrender made by the employee as also the fact that he is a young and up coming employee, the extreme penalty by way of dismissal is not being imposed on the merits of the case so that avenues for rehabilitation of the employee still remain open. He is accordingly discharged from the Bank's service.

The order of discharge is by way of punishment though in place of extreme penalty of dismissal so that avanues for rehabilitation of the employees still remain open. Thus even section 25F also has not been violated by the management nor a question of giving charge sheet notice or one months notice or retrenchment compensation is required

14. Now coming to the point whether discharge order was passed by an officer not to competent to pass that order. The workman alongwith his affidavit has filed annexure I the photo copy of the appointment letter dated 13-12-70 whereby as a result of interview held he was required to join duty latest by 31-12-70. The letter is signed by Deputy Secretary and Treasurer of the Kanpur Local Head Office of the management and the workman was ternsinated by the Regional Manager, Region No. II Kanpur. It is common ground that after service on 31-12-70, at Kanpur, the workman transferred to Allahabad University Branch on 4-1-71. It has not been shown by the workman how Sceretary and Treasurer of the management bank is higher in rank and the termination made by Regional Manager Region II Kanpur is lower in rank. The highest Officer in the region is General Manager and thereafter Chief Regional Manager and then Regional Manager Dy. Secretary and Treasurer of the Kanpur Local Head Office, has not been shown to be lower in tank than the regional manager. The management witness Shri V. K. Mehrotra M.W.1 has deposed that Deputy Secretary and Treasurer is equivalent to the post of General Manager and Regional Manager is lower in rank to the Chief Regional Manager. There is no other post between General Manager and Chief Regional Manager. Thus according to the testimony of the management banks witness the termination has been made by an officer lower in rank than the person who had appointed him. Discharge or termination should not be by person lower in rank than the officer who appointed him. In the instant case admittedly a person lower in rank terminated the services of the workman and on that account the termination of the workman is illegal. Thus in view of the reculation 55 of the State Bank of India para (2)(a)(iv) lays down such officer or employees shall not be dismissed from service of S.B.J. by an authority lower than the appointing authority".

15. Thus in view of the discussion above, the discharge of the workman by person lower in authority is illegal. The result is that the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages.

16 On the point of delay it may be pointed out that there is no limitation for sending the reference for adjudication. Further it was in the wisdom of the Government to have refer the dispute for adjudication at any proper time, it desired so and it can not be said that the reference is invalid on account of delay.

17. In view of the reasons discussed above I hold that the action of the management of State Bank of India, Kanpur, in adation to their University Branch Allahabad in discharging Shri Suresh Chandra Upreti Clerk with effect from 27-10-77 is not justified

- 18. The result is that the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages.
  - 19. I, therefore, give my award accordingly.
- 20. Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer[No. L-12012|146|83-D, II(A)]N. K. VERMA, Desk Officer

नर्फ दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का. आ. 4204 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुमरण में, केन्द्रीय मरकार भारतीय खाड़ निगम, पंजाब क्षेत्र के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कर्मिक के प्वाट को प्रकाशित करनी है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-8-1985 को प्राप्त हुआ था।

#### New Delhi, the 29th August, 1985

S.O.4204.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal. Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Punjab Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1985.

# BFFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CFNTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CHANDIGARH

Case No. I. D. 18/1984

PARTIES:

Empolyers in relation to the management of Food, Corporation of India.

ΛND

Their workman-Garibu Singh.

APPEARANCES:

For the Employer—S/Shri Mangoo Ram and  $V_{\rm c}$  K. Bansal

For the Workman-Shri P. K. Singla.

INDUSTRY: Food Corporation of India STATE: Punjab

### AWARD

Dated, the 6th of August, 1985

The Central Government Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, vide their Order No. L-42012(9)/83-D.IV (B)/D.V. dated the 28th of May, 1984 teferred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Shri Garibu Singh. Watchman with effect from 2-3-82 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?"

698 GI/85 13

- 2. Buef facts of the case, according to the petitioner Workman, are that he was working as a Castal watchman under the Respolt. Corporation at their Dhuri Storage Depot since 1-5-1981 till 2-3-82 when he suddenly fell ill and could not attend duty for the next two months. It was complained that on 3-5-1983 when he returned to duty and produced a medical certificate, the management refused to entertain it and informed him that his services had already been terminated since 2-3-82. The petitioner assailed his termination on the ground that it was violative of the mandatory provisions of Section 25-F. 25-G. 25-H. and 25-N because he was deprived of all the terminal benefits. He, therefore, approached his Union and raised a demand for his reinstatement with full back wages. But the management was found annessionsive despite the intervention of the A.L.C. (C) at the Conciliation stage and hence the Reference.
- 3 Resisting the proceedings, the management justified their action on the plea that the petitioner had voluntarily abandoned his job without caring to inform them and that the entire story of his alleged illness was a fake, an after thought and sheer concoction. As a necessary corollary, they opposed his effort to seek any terminal benefits. On facts, despite an admission of the petitioner's casual engagement, they denied that he had completed 240 days of service in one year. It was rather explained that he had worked for them in two different spells from 1-5-1981 to 15-11-1981 and 21-12-1981 to 2-3-1982.
- 4 Keeping in view the comprehensive nature of the terms of Reference, the parties were called upon to adduce evidence in support of their respective versions without going through the drill of casting any formal issues. Thus the petitioner examined his authorised representative Shri P. K. Singla and filed a number—of documents whereas the management felt contended with the deposition of their Asstt. Manager Shri Mangoo Ram. I have carefully gone through the entire available data and heard the parties.
- 5. The crucial point which requires determination in this case is as to whether or not there was voluntary abandonment of job by the petitioner, because in the light of Management's own pleadings in para No. 2 of the written statement he appears to have been in continuous services for more than one year within the meaning of Section 25-B of the Act and it hardly requires any emphasis that disengagement of such like workman calls for a strict compliance of the provisions of Section 25-F, G and H.
- 6. On behalf of the petitioner my attention was drawn towards the documents Exts. W-4 and W-7 to W-10 with the submission that when the petitioner reported for duty on 3-5-1982 he had produced the medical certificate Ex. W-4 revealing that during the period of his absence he was bedridden due to Typhoid and that Ex. W-7 to W-10 were filed to impress that a similarly placed worker named Karamsungh was shown indulgence of reinstatement by the management. It was, therefore, argued that it was a clear case of flagrant discrimination.
- 7 Inspite of its seeming attraction the submission failed to carry conviction with me because it appears to relate more to the domain of surmises and conjuctures rather than facts. It may be worthwhile to mention here that no such plea was taken either in the Claim statement or the Rejoin-der. So much so that it was not even projected in the affidavit Fx. W-1 of petitioner's representative Shri Singla. To put it in other words, the management got no opportunity to address evidence of fact or circumstances leading to the reinstatement of Karam Singh Otherwise also, a bare perusal of the netitioner's Medical certificate Fx W-4 would expose the hollowness of his claim. This document purports to have been issued by a Registered Medical Practitioner named Manohar I al who neither cared to disclose his own address nor attestation thereon by the petitioner Ordinarly such type of certificates are issued for the patients who are kept under treatment on being entered in the "Patient-Register" But in this case no such norm was observed, as would be evident from the absence of any registration number on the document. And it hardly requires any emphasis that both of them i.e. the Doctors as well as the netitioner dimself. who could have been the best witness of the incident of his alleged illness; onted to refrain from the witness box for no explicable reason. The inference is, therefore, obvious that

they wanted to avoid exposure on the acid test of cross-examination. It is besides the point that even this Certificate Ext. W-4 issued expost facto.

- 8. On the other hand from the documents Pxts, W-8 to W-10 it appears that Karam Singh was bed ridden due to fractured leg when he approached Dr. O. P. Bansal of Sangrur i.e. the place where he was employed; he got himself registered with the Doctor on the very first day of his absence at Registration No 450 and in due course the fitness certificate was also issued to him. In a manner of speaking documents Ex W-9 and W-10 give prima facie indication that there was nothing doublous about his illness.
- 9. Be that as it may, in our case there is absolutely no explanaion as to how and why the petitioner failed to inform his I'mployer for more than two months regarding his alleged illness. Similarly there is no worthwhile evidence to show that on 3-5-1982, he had furnished his aforesaid medical certificate to any particular officer of the Corporation with a prayer to condone his absence. In my considered opinion, against such back-drop, the management had every logic to assume that he was no more interested in serving them and had abandoned his job voluntarily—for the reasons batter known to him.
- 10 Hence in the totality of the circumstances, I find no impropriety in their action and, as such, return my Award against the petitioner/Workman.

Chandigarh, 6-8-1985

I. P. VASISHTH, Presiding Officer [No. 1-42012/9/83-D.IV (B)/D V.]

का. आ. 420 5.—अीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार व प्रीजेक्ट अधिकारी, टापिन माज्य कोलियिंगी मैं भी मी. एल. के प्रबंधनंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकरों के बीच अनुबंध में निविष्ट जीधा-गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण ने. 2 धनवाद के पंचाट को प्रकाशित करनी है, जो केन्द्रीय सरकार की 2188-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4205—In pursuance of section—17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Central Government Industrial Tribunal No. 2, P.O. Jagjiwan Nagar, Dhanbad, as shown in the Annexute, in the industrial dispute between the employers in relation to the management Project Office. Tapin South Colliery of M/s. Central Coalfields 1 td. and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th August, 1985.

# BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 4 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Setion 10(1)(d)

of the L.D. Act. 1947

# PARTIFS:

Employers in relation to the management of Project Officer, Tapin South Colliery of M/s. CCI, and their workmen.

APPFARANCES:

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen-Shri B. Joshi, Advocate.

STATE: Bihai INDUSTRY: Coal

Dhanbad, the 14th August, 1985

#### AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the l. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(73)/84-D IV (B) dated the 18th January, 1985.

#### SCHEDULE

- J. "Whether the stoppage of three annual increments of Shri Gurudayal Singh, Dumper Operator of Tapin South Colhery by the Project Officer (TSC), Tapin South Colliery of the Central Coalfields Ltd. is legal and justified?"
- II. "Whether the action of the Project Officer Tapin South Colliery in withholding/1/3rd of the wages of Shri Gurudayal Singh during his suspension period in addition to the stoppage of his three annual increments with cumulative effect is legal and justified?"
- III. "If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

The acse of the workmen is that the concerned workman Shri Gurudayal Singh was working as Dumper Operator at Tapin South Colliery of M/s. CCI. He was an active members of the Coalfields Labour Union since the year 1976. In the year 1977 and 1978 there was a serious rivalry between the Coalfields Labour Union and RCMS in which the concerned workman being staunch supporter of the Coalfield Labour Union took active part in the organisation of his union. The rival union made several attempts to win over the concerned workman so that he may desert Coalfield Labour union and he was allured for an accelerated promotion it he joins the rival union but he did not agree. Due to the trade union activities of the concerned workman the rival union could not take its root in the Tapin South Colliery. When the rival union failed to gain over the concerned workman they hatched up a plan with the connivance of the management of the Tapin South Colliery and thereby on false allegation chargesheet was submitted on the concerned workman on 22-11-78. The concerned workman was falsely charged for committing rape on Smt. Bitco Kamin wife of Ritlal Manihi. A drama of domestic enquiry was enacted in which the members of the rival union who had been persuading the concerned workman to join the unron deposed as management's witnesses before the Enquiry Committee. Not a single independent witness appeared in support of the charge against the concerned workman. The woman alleged to have been raped by the concerned workman was not an employee of CCL and the place where the alleged rape was committed was outside the leased area of Tapin South Colliery. The Enquiry Officer did not correctly record the statement of the witnesses of the Enquiry proceeding. Even the statements of Bitco Majhiain was not correctly recorded as the same Bitco Majhiain had flutly denied to have any know of the case when she deposed before the Sessions Court at Hazaribagh in the case of rape instituted against the concerned workman. She had deposed before the Sessions Judge that she was not raped and her husband Ritlal Manjhi has denied his knowledge about the alleged rape of his wife and accordingly the concerned workman was acquitted by the Second Additional Sessions Judge, Hazaribagh. The concerned workman had made a representation before the Project Officer that the enquiry Officer was biased and had wrongly recorded the statement of Bitco Majhiain under the pressure of S/Shri K. K. Bajoni, Mahuan Keshri etc. The Project Officer ordered the Enquiry Officer to record the statement of Bitco Majhiain afresh and thereafter the Enquiry Officer took the statement of Bitco Majbiain on 14-4-79. Biteo Majhiain had admitted in crossexamination at that time that the concerned workman did not committ rape on her or take away her petty coat. It is submitted on behalf of the workman that the management should have withdrawn the charges levelled against the concerned workman after consideration of the athdavit of Smit. Bitco Maihiam made before the Court and her statement dated 14-4-79. The act of the management in stopping three annual increments with cumulative effect and withholding 1/3rd of his wages during the period of his suspension was an act of victimisation for the trade union activities of the concerned workman. The management had paid only 2/3rd of wages to the concerned workman during the entire period of his suspension and the remaining 1/3rd of his wages had not been paid to him even after the order of punishment notified on 1-1-79. It is prayed on behalf of the concerned workman that an Award be passed in his favour.

The case of the management is that on receipt of report of certain acts of misconduct stated to have been committed by the concerned workman and two other workers namely S/Shri Balmukund Singh, Dumper Operators and Jagdish Ram, Grader Operator of the same colliery were issued with a chargesheet dated 22-11-78 and were placed under suspension with effect from the said due pending enquiry into the charges framed against them. The charges framed against them were:—

- 1.) That on 19-11-78 at about 7.50 PM near the colliery dispensary of Tapin South Colliery, Shri Gurudayal Singt, Dumper Operator, Tapin South, Colliery had forcibly snatched the transistor belonging to Shri Ratilal Manjhi, Piece rated worker of Tapin South Colliery, Shri Gurudayal Singh also assaulted Shri Ratilal Manjhi in the course of which Shri Gurudayal Singh tore up his shirt. Shri Gurudayal Singh further caught hold of Smt. Bitco wife of Shri Ratilal Manjhi, and forcibly dragged her to the side of the road although Smt. Bitco protested and struggled to get free from his clutches, Shri Gurudayal Singh forcibly laid her on the ground and violated her chastity by molesting her and by committing rape on her.
- (2) That S/Shri Balmukund Singh, Dumper Operator, Tapin South Colliery and Jagdish Ram, Grader Operator, Tapin South Colliery were with Shri Gurudayal Singh at the above mentioned place during the time when the above acts were committed and had actively aided and abotte! Shri Gurudayal Singh in the above acts.

The concerned workman was served with a chargesheet and the eafter he submitted his cepty dated 12-12-78. His explanation was considered to be unsatisfactory by the Project Officer/Agent and thereafter a detailed enquiry was ordered by how and Shi B. N. Singh, Administrative Office Tanin Colhery was appointed as Figury Officer. After due notice to the workman concerned the enquire officer held the enquiry in accordance with the principles of natural justice and full apportunities were given to the concerned workman to defend himself. The management's witnesses were examined in his presence and was given an opportunity to cross-examine the meaagement's witnesses. The workman also was given an opportunity to make his statement and to examine his witnesses in defence. After completing the enquiry the enquiry officer found the concerned workman guilty of having conmitted rape on Smt. Bitco wife of Ratilal Manjhi which was an not involving moral turpitude. The enquiry officer submitted his enquiry report on 27-2-79. Thereafter the conce ned workman had submitted a copy of the affidavit proported to have been sworn by Smt. Bitco stating that she had made the allegation against Shii Gurudayal Sinch and others at the instigation of Shri K. K. Balpei and others. Thereafter the Project Officer with the approval of the General Manager, Hazaribagh Area advised the Enquiry Officer to interrogate Smt. Bitco in presence of the concerned workman and the same was done by the Figury Officer and the concerted workman was given an opportunity to cross-examine Smt. Bitco Kamin. The enquiry officer submitted a further report stating that Smt. Bitco had denied to have filed the affidavit in question. The Enquiry Officer had further stated in his report that Smt Bitco Kamin was enticed and Inmidated by the concerned workman and others to life a petition given contradictory statement by her and by her husband after the enquiry was over and the enquiry officer further reported that the findings given by him in his enquiry report dated 27-2-79 would stand. The Project Officer/Agent, Tapin South Colliery considered the enquiry report and having agreed with it imposed the punishment of stoppage of three annual increments with cumulative effect by his order dated 1-5-79. The Project Officer also passed an order that the concerned workman will not be paid anything more than the substantive allowance already paid to him for the period of suspension pending enquiry. The concerned workman was allowed to resume duty from 2-5-79. It is submitted on behalf of the management that the stoppage of three annual increments of the concerned workman was fully justified and that the payment of only 2/3rd subsistence allwance for the period of suspension was also justified. It is prayed on behalf of the management that the Award be passed in their favour.

By order dated 21-6-85 this Tribunal has held that the domestic enquiry held against the concerned workman was fair and proper. Thereafter the case was heard on merit and the entire proceeding before Enquiry Officer was gone into to see whether the charge was established against the concerned workman and whether the punishment inflicted upon him was just and proper.

Ext M-13 is the Enquiry Proceeding in which the statement of all the witnesses examined before the Enquiry Officer has been recorded and Ext. M-19 is the Enquiry report dated 27-2-79. It will appear that four witnesses were examined on behalf of the management out of whom Enquiry Officer did not place reliance of his evidence of Ratifal Manjhi as it was not convincing. MW-4 is the lady Smt. Bitko who was alleged to have been raped by the concerned workman. She had clearly stated that while she was coming along with her nusband she met three persons in the way out of whom she could not identify two at that time who cought hold of her husband and the concerned workman whom she indentified dragged her towards the nearby jungle and committed rape on her. There is nothing in the enquiry proceeding Ext M-18 to show that Bitko had ever stated that the concerned workman had not committed rape on her person. Her evidence finds corroboration by the evidence of MW-2 Haridutt Awasthi and MW-3 Anwar Hussain who are also working as Dumper Operator. Both of them were comin. together after making an enquiry whether there would be a cinema show or not and while coming in the way they found the concerred workman lying upon Bitko and her body was naked below her waish. It was about 730 in the evening and it had become dark but some dim light was coming at the spot from the hospital side. It is clear therefore from the cyldence of Bitko and the evidence of MW-2 and MW-3 that the concerned workman had committed rape on the person of Smi. Bitko and that on arrival of these two witnesses the concerned workman fled away. The evidence of MW-2 and MW-3 has been criticised or the pround that they belong to the rival union and as such they were deposing against the concerned workman. In the earlier reply of the concerned workman to the chargesheet it had not been stated that Haridutt Awasthi and Anwar Hussain were having rivalry with the concerned workman. Fxt M.2 is the reply to the chargesheet which was filed by the concerned workman. It was also after Haridutt Awasthi and Anwar Hussain gave their statement in the enquiry proceeding that the concerned workman started making allegations against them so much so that the concerned workman got examined defence witnesses alleging that Haridutt Awasthi was seen committion rang on Smt. Bitko and that Anwar Hussain was seen taking the transister of Ratifal Manihi. On this point of fact as is alleged in the statement of defence witnesses, there was no reason for Smt. Bitko not to make any allecation against Harldoff Awasthi and Anwar Hussain and instead making allogations of rane against the concerned workman. Moreover if the defence as has been alleged before the Enquiry Officer was true, the said fact must have been stated in Fet M 2, which was the earlier statement of the record in which the concerned workman could have stated that he had not committed rape but Haridutt Awaschi had committed the range on Smt. Bitko, Besides that there is no reason for

Sint. Bitko to talsely implicate the concerned workman and to feave Haridutt Awasthi if he had really committed the tage.

Out of the witnesses examined in detence DW-1 lagdish Mann, DW-2 But Mukung are the two personal against whom chargesheet had been shoundted along with the concerned workman and as such it is quite natural that they are avoiding to admit the facts affeged in the chargesheet. DW-5 Kamaljit Kaur is the wife of the concerned workman Gurdayal Singh from whose mouth the story of rape of Bitko by Haridutt Awasthi has been alleged. Gurdayal Singh has also stated that on being reported by his wife he went out and saw rape being committed by Haridutt Awasthi on Smt. Bitko. As I have already stated above these facts appear to be clearly concocted just to have a defence as the said fact was not stated earlier in the reply to the chargesheet by the concerned workman or in the written statement of this case although the facts which are being alleged were known to them since before filing of the reply by the concerned workman. DW-3 Balwant Singh stated that he was at the residence of Jagdish Ram along with Gurdayal Singh, Jaginder Singh and Lachman Singh on the alleged date and time of occurrence. DW-4 Shri Jainarain Singh was not present at the place of occurrence. Moti Majhi has stated that Anwar and Awasthi came to him at the Pump house and asked him to go and see and thereafter he went and found the wife of Ratilal Manithi lying to the south of the female hospital. He had not seen the real occurrence, but in a way it supports the case of the management. Had Awasthi committed the rape on Smt. Bitko he would not have gone to Moti Manjhi to go and see wife of Rati Manjhi. Thus there were materials before the Enquiry Officer to show that the concerned workman had committed rape on the person of Smt. Bitko and on the basis of the statement made before him he submitted his enquiry report Ext. M-19 on 27-2-79. Till then there was nothing before him to show that Smt, Bitko was making varying statement denying the rape on her person by the concerned workman and as such if the matters which came subsequent to the filing of his report could not have been envisaged by him and as such the said enquiry report cannot be said to be vitiated for non consideration of the affidavit of Smt, Bitko or any statement made by her before the Sessions Court.

Ext. M-21 is the further enquiry report of the Enquiry Officer dated 24-4-79. On perusal of Ext. M-20 and M-22 along with the Enquiry report Ext. M-21 it will appear that after the enquiry concluded on 22-2-79 and the enquiry report submitted on 27-2-79 the concerned workman had submitted to the Project Officer a copy of affidavit of Smt. Bitko Majhiain in which she was alleged to have stated that she had made allegation against the concerned workman and others on the instigation of Bajpei and others. It will appear from Ext. M-20 and M-22 that the Project Officer Tapin South directed the Enquiry Officer to take the statement of Smt. Bitko in presence of Gurudyal Singh as to whether Smt. Bitko had made any affidavit in the Court and thereafter the Enquiry Officer recorded the statement of Smt. Bitko in presence of the concerned workman on 19-4-79. Ext. M-6 is the proceeding dated 19-4-79 in which the copy of affidavit was sworn to Smt. Bitko in presence of the concerned workman and was asked whether she had gone to Hazaribagh Court to file an affidavit to which she denied. In crossexamination by the concerned workman she relierated reported that the had not filed any affidavit or given her signature. Thus the truth of the affidavit having been filed by Smt. Bitko is belied. However, she stated on that day that the concerned workman had not committed any act (meaning thereby that she was not raped). I think the Fnourry Officer has given good reasons as to why he did not accept the said statement of Smt. Bitko. It appears that when the concerned workman was found guilty of the charge he made all efforts to win over Smt. Bitko so that he may be absolved from the charge and I think that the Enquiry Officer was correct in coming to the conclusion that Smt. Bitke enticed and intimidated by the concerned workman and others in the filing of netition giving compade tors statement by her after the Figure was over on 27-2-79. The Figure Officer stuck to his Enquiry report dated 27-2-79 while making his further report dated 24-4-79 that the concerned workman had committed rape on Smt. Bitko.

The evidence discussed above shows that there was evidence before the Enquiry Officer to show that the concerned workman had committed tape on Smt, Bitko and good reasons have been given as to why the statement of the management's witnesses have been accepted. In view of the above evidence it cannot be said that the conclusion arrived at by the Enquiry Officer would not have been arrived. In my opinion the findings are not perverse as the same is based on evidence before the Enquiry Officer. The Enquiry Officer was careful enough to find the concerned workman guilty of the charges in respect of rape only and he has found him not guilty of the other allegations that the concerned workman had either snatched the radio or had assaulted Ratifal Manjhi or had tore of his shirt as he did not find any reliable evidence on those facts. The enquiry Officer, therefore, cannot be alleged to have any bias against the concerned workman.

In view of the above I hold that the charge of rape of Smt. Bitko by the concerned workman was established before the Enquiry Officer and I find no reasons to hold the said findings as perverse.

It has been submitted on behalf of the concerned workman that he has been doubly punished in as much as 3 annual increments with cumulative effect has been stopped and his remaining subsistence allowance of 1/3rd of his pay has been with held. The concerned workman as a way of publishment has been inflicted with the stippage of three annual increments with cummulative effect as the charge was proved against him. So far non payment of 1/3rd of his wages is concerned, the same is not stopped as a way of punishment but as the charge against the concerned workman was established the management did not think it proper to pay the remaining amount except which has been paid as subsistance allowance during the pendency of the proceeding. In accordance with clause 17(iii) of the Model Standing Order applicable in the colliery if a workman is not found guilty of the charges framed against him, he shall be deemed to be in duty during the full period of his suspension and he is entitled to receive the same wages as he would have received if he had not been suspended. This clause is applicable when a workman is found not guilty but in case a workman is found guilty of the charge it is not applicable and it is for the management to decide whether to pay the entire amount or not to the workman in case the charge have not been proved against him. The management was therefore within his rights to stop further payment for the period of suspension except the subsistance allowance which his already been pald to the concerned workman. I further hold that the non payment of amount other than subsistence allowance was not an order inflicted by way of punishment to the charge established against him.

In the result I hold that the stoppage of three annual increment of the concerned workman Shri Gurudyal Singh is legal and justified and that the action of the Project Officer, Tapin South Colliery in with holding 1|3rd of the wages of the concerned workman during his suspension period is also legal and justified. The concerned workman is not entitled to any relief.

This is my Award.

Dt. 14-8-85

I.N. SINHA, Presiding Officer [No. L-24012](73)|84-D. IV(B)] R.K. GUPTA, Desk Officer

11111

वित्त मंद्रालय (राजस्व विभाग) भ्रादेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1985

का. मा. 4206 --- भारत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण ऋधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के ऋधीन

विशेष रूप से सणकत किया गया है, उक्त उपधारा के प्रश्नीन प्रादेश फ़ा.सं. 673/15/84-सी.णु.-8 ताराख 28-6-1984 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री नरेश वी. ताल(नी 20 प्रजन्ता एपार्टमेंट्स, 10वी मंजिल, 124/126 बाहकेश्वर रोड, बम्बई-400006 की मेन्ट्रल जेल, बम्बई में निरुद्ध किया जाए और श्रीक्रिश्का मे रखा जाए ताकि बहु ऐसा कोई भा कार्य नहीं कर सके जो बिदेशों मुद्रा का श्रीक्रियुद्ध के लिए हानिकारक हो ।

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वीक्त व्यक्ति फ़रार हो गया है या प्रपने को छिका रहा है जिससे उस स्रादेश का मिल्पादन नहीं हो सके; और
- 3. अतः, अव केन्द्राय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 का उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देता है कि पूर्विक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपन में प्रकाशन के सात दिन के भोतर पूर्विस आयुक्त बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

फ़ा. सं. 673/15/84-सा.**म्.**-8]

# MINISTRY OF FINANCE (Revenue Department) ORDER

New Delhi, the 14th September, 1985

- S.O. 4206.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Sumggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/15/84-Cus. VIII, dated 28-6-1984 under the said sub-section directing that Shri Naresh B. Jhalani, 20 Ajania Apartments, 10th Floor, 124/126, Walkeshar Road, Bombay-400006 be detained and kept in Custody in the Central Prison Bombay with a view to preventing him from acting in any manuer prejudicial to the augmentation of foreign exchange;
- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing him self so that the order cannot be executed; and
- 3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bumbay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|15[84-Cus, VIII]

# आदेश

का. था. 4207 — तरत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशो मुद्रा संरक्षण और तस्करो निवारण श्रिधिनयम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के श्रधीन विशेष रूप स सणक्त किया गया है उक्त उपधारा के श्रधीन श्रादेश का. स. 673/17/84-सी. शृ. -8, तारीख 28-6-84 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री रिवन्द्र की झलानी, 20 ग्रजन्ता एपार्टमेंट्स, 10वी मंजिल, 124/126 बाल्केश्वर रोड, बंबई 400006, को सैंट्ल जेल, बंबई-400006 में निरुद्ध कर लिया जाए और श्रिकरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे विसी भी कार्य को करने से निवारित किया जा सके जिससे विदेशी मद्रा को संबंधि पर प्रतिकन्न प्रसर पड़ता ही:

- 2. केन्द्राय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वीक्त व्यक्ति फ़रार हो गया है या श्रपने को छिपा रहा है जिससे उस स्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके; और
- 3. ब्रतः ब्रब, केन्द्रीय सरकार उक्त ब्रिधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खड़ (ख) ब्रारा प्रदत्त शिक्तिओं का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि पर्वेषित व्यक्ति इस अर्थिण के राजपन्न में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पृलिम श्राकुक्त बम्बई के समक्ष हाजिए हो।

[फा, मं. 673/17/84-सी.सु.-8]

프로프로 크로 드로드 ::':

# ORDER

S.O. 4207.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673|17|84-Cus. VIII, dated 28-6-1984 under the said sub-section directing that Shri Ravindra B. Ihalani, 20 Ajanta Apartments, 10th Floor, 124|126, Walkeshwar Road, Bombay-400006 be detained and kept in custody in the Central Prison Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and
- 3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

  [F. No. 673]17[84-Cus. VIII]
- का. या. 4208--- शरत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षा और तस्करी निव(रण प्रिधिनियम, 1971 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्धान विणेप रूप में सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/136/84 मी. शू.-8. तारीख 29-6-84 जारी किया था जिसमें यह आदेश दिया था कि श्री जावेद खान पुत्र धली मोहम्मद खान. 4/441 कमल मैंशन, अर्थर बंदर रोड. कोलाबा, बंबई 400005 को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी का बढ़ावा देने से निवारित करने की दृष्टि से नागपुर सैंट्रल जेल नागपुर में निरुद्ध कर लिया जाए और श्री भरक्षा में रखा जाए।
- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त त्यक्ति फरार हो गया है या ग्रामे को खिपा रहा है जिससे उस ग्रादेण का निष्पादन नहीं हो सके: और
- 3. भ्रतः श्रव केन्द्रीय सरकार उक्त ग्रीर्धानयम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वेक्ति व्यक्ति इस ग्रादेश के राजपव में प्रकाशन के साल दिन के भीतर अतिरिक्त पृलिस आयुक्त (भ्रवराध) ग्रेटर बंबई के समक्ष हाशिर हो।

[फा. सं. 673/136/84~सी. श्.-8]

S.O. 4208.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/136/84-Cus. VIII, dated 29-6-1984 under the said sub-section directing that Shri laved Khan, son of Ali Mohammed Khan of 4/441, Kamal Mansion, Arthur Bunder Road, Collaba, Bombay-400005 be detained and kept in custody in the Nagpur Central Prison, Nagpur with a view to preventing him from enuggling goods and abetting the snuggling of goods;

- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Additional Commissioner of Police (Crime), Greater Bombay, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

LF. No. 673 136 84-Cus. VIII

- का. ग्रा. 4209—भारत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण श्रिधिनयम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के श्रधीन विशेष रूप से सशकत किया गया है उक्त उपधारा के श्रधीन अदेश फा.सं. 673/137/84—सी०शु०—8 तारीख 29-6-84 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री सैयद मोहम्मद श्रारिक वावामिया फ्लैंट नं. 10 चौथी मंजिल नसीम बिल्डिंग रेंड काम स्ट्रीट बम्बई को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी को बढ़ावा देने से निवारित करने की दृष्टि से नागपुर सैंद्रल जेल में निरुद्ध कर लिया जाए और श्रिभरक्षा में रखा जोए;
- 2. केन्द्रीय नरकार के पास यह विग्धास करने का कारण है की पूर्वीक्त व्यक्ति फरार हो गया है या भ्रपने को छिपा रहा है जिसमें उन भादेश का निष्पादन नहीं हो सके; और
- 3. श्रतः श्रव केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुए यह निदेण देती है कि पूर्वेक्ति व्यक्ति इस श्रादेश के रोजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर श्रितिरिक्त श्रायुक्त पिलिस (अपराध) ग्रेटर बंबई के समक्ष हाजिर हो।

[फा . सं . 673/137/84-सी०श०-8]

S.O. 4209,—Whereas the Additional Secretary to the Covernment of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673[137[84-Cus. VIII. dated

.. _ . . . : = 29 6-1984 under the said sub-section directing that. Shri-Sayed Mohamed Arif Bawamiya Flat No. 10, 4th Floor, Naseem Building, Red Cross Street, Bombay be detained and kept in custody in the Nagpur Central Prison, Nagpur with a view to preventing him from smuggling goods and abetting the smuggling of goods;

----

- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and
- 3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Additional Commissioner of Police (Crime), Greater Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673]137]84-Cus. VIII]

का था. 4210--भारत सरकार के संयक्त सचिव जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण श्रिधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के स्रधीन आदेश फा० संत 67-3/187/84**-**मीमा तारीख 25-9-84 जारी किया गया था जिसमें यह निदेश दिया गया था कि श्रीरोहताश कुमार श्रप्रवाल उर्फ सिख् पृत श्री केदार नाथ अग्रवाल की माल की नस्करी करने नथा माल की तस्करी के लिए दृष्प्रेरित करने में उसे निवारित करने की द्धि से प्रेमीडेंसी जैल, श्रलीपुर में निरुद्ध किया जाए तथा ग्रभिरक्षा में रखा जाए ;

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का. कारण है पूर्वोक्त व्यक्ति फरारहो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त ग्रादेश का निष्पादन न हो सके।
- 3. श्रतः श्रव, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वेक्ति व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र प्रकाशन के साने दिन के भीतर महानिरीक्षक, पृश्विस, पश्चिम, बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिंग हो ।

फि. मं. 673/187/84-मी. ण . 8]

S.O. 4210.-Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974). issued order F. No. 673187184-Cus. VIII. dated 25-9-1984 under the said sub-section directing that Shri Rohtas Kumar Agarwal ahas Sidhu, son of Shri Kedar Nath Agarwal, be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore with a view to preventing him from smuggling goods and abetting smuggling of goods;

2. Whereas the Central Covernment has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

. ... -- --

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

(F. No. 673)187'84-Cus. VIIII

का ग्रा.4211--भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण श्रिधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन विणेष म्प में सणक्त किया गया है उक्त धारा के प्रधीन प्रादेण फा. मं. 673/215/84~सीमा शब्क~8 तारींख 6-12-84 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया गया था कि श्री श्रशोक महादेव उर्फ श्रशोक महतो पुत्र श्री महादेव पाटिल को माल की तल्करी और तस्करी के माल को लाने ले जाने से निवारित कारने की दृष्टि से सैट्रल जेल यश्वदा, पूर्णे में निरुद्ध किया जाये और श्रीभरक्षा में एखा जाये;

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण कि पूर्वेक्ति ज्यक्ति फरार हो गया है या भ्रमने को छिपा रहा है जिसमें इस भादेश का निष्पादन हो सके:
- 3. श्रतः स्रव केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस क्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर महानिरीक्षक पुलिस, बंबई के समक्ष हाजिए हो।

[फा. म. 673/215/84-सी. ण -8]

- 5.0, 4211.- Whereas the Joint Secretary to the Government of India, Specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673 215 84-Cus. VIII, dated 6-12-1984 under the said sub-section directing that Shri Ashok Mahadeo Patil alias Ashok Mahato, son of Mahadeo Patil be detained and kept in custody in the Central Jail, Yerwada, Pune with a view to preventing him from smuggling goods and engaging in transporting smuggled goods;
- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;
- 3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by classe (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673]215[84-Cus. VIII]

का. आ. 4012 - भारत सरकार क संयुक्त सचिव ते जिमे मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी नियारण श्रीधनियम, 1974, (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन विशेष क्रप से सशक्त किया गया है। उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/61/85—सी.म्.-8, तारीख 13-6-1985 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री निरंजन कुमार उर्फ बर्ला । इ. श्री हकीं अ। राय गुलबानी सी-123, शक्ति नगर एक्सटेंगन, दिल्ली को सैंट्रल जेल. तिहाड़, नई दिल्ली में निम्ब कर लिया जाए और श्रिभरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल लाने ले जाने और उसे ग्रपने कोश अपने पास रखने और तस्वारी के माल को छिपाने के श्रलावा तस्करी के माल का धंधा करने में निवारित किया जा सके;

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या ग्रपने को छिपा रहा है जिसमें उस भादेणका निष्पादन नहीं हो सके; और
- श्रतः श्रव केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वीक्त व्यक्ति इस स्रादेश

के राजपत के प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस भायक्त, दिल्ली के समक्ष द्वाजिए हो।

> [फा.मं. 673/61/85-सी.गु.-8] ग्रार, के. तिवारी, उप सचिव

- S.O. 4212. Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foregin Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673 61 85-Cus. VIII, dated 13-6-1985 under the said sub-section directing that Shri Niranjan Kuman thus Bulli can of Shri Hakilat Boi Galubani C 123 Shriki ulus Balli, son of Shri Hakikat Rai Gulabani, C-123, Shakii Nagar Extension, Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in transporting and keeping smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by concealing smuggled goods;
- 2. Whereas the Central Governmeent has reason be believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and
- 3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673]61]85-Cus. VIII] R. K. TIWARI, Dy. Secy.